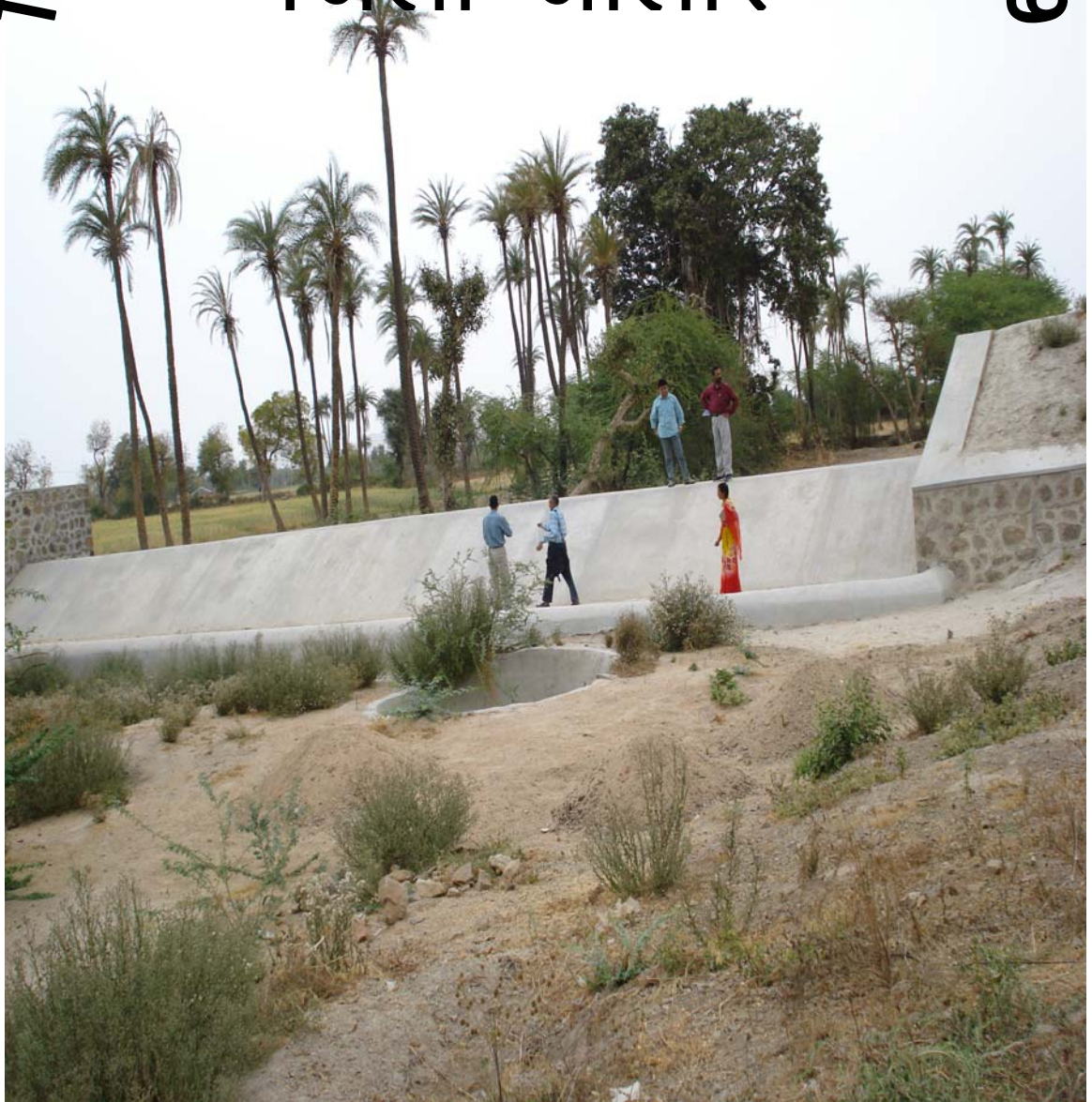


राजस्थान-सरकार

जिला मानव विकास प्रतिवेदन-2006

जिला जालोर



अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या	
	प्राक्कथन कृतज्ञता मानव विकास की अवधारणा		
1	जिले का परिचय	1.09	
2	शिक्षा	10.25	
3	स्वास्थ्य	26.62	
4	आजीविका	63.115	
	4.1 रोजगार एवं श्रम शक्ति		63.66
	4.2 नर्मदा परियोजना		67.77
	4.3 डेयरी		78.84
	4.4 उद्योग		85.90
	4.5 कृषि एवं उद्यानिकी		91.102
	4.6 पशुपालन		103.105
	4.7 महिला एवं बाल विकास		106.107
	4.8 ग्रामीण विकास एवं भाहरी विकास		108.113
	4.9 पर्यटन		114.115
5	जेण्डर	116.118	
6	सारांश एवं भावी रणनीति स्रोत	119.124	

केवल कुमार गुप्ता

जिला कलेक्टर, जालोर

प्राक्कथन

भारतीय मूल के अर्थ शास्त्री श्री अमर्त्य सेन के अनुसार आर्थिक वृद्धि से यह आवेक नहीं कि सभी लोगो का कल्याण ही हो। उनके अनुसार मानव विकास का मूल उद्देश्य मनश्यों के पास उपलब्ध विकल्पों को बढ़ाना। मानव विकास वह है, जिसमें लोग अपनी पसन्द का जीवन जी सकें और इसके लिए उनके पास समान अवसर एवं दक्षता हो।

मानव विकास प्रतिवेदन जिले की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के चिन्तन एवं आत्मविलेखन करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जिले के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की भावी दिशाएँ तय की गयी हैं, जिससे लोगों की विशेषतः समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकें।

जालोर जिले का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। मानव विकास प्रतिवेदन जिले के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाता है एवं चुनौतियों की पहचान के लिए, जेण्डर एवं वंचित वर्गों की स्थिति पर विशेष दृष्टि रखकर, प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं महिला विकास का अध्ययन किया गया है। प्रतिवेदन को तैयार करने में विभिन्न सूचकों का गहन अध्ययन किया गया है, जिससे अब तक की स्थिति, कमी तथा चुनौतियों की जानकारी प्राप्त हुयी है। उपलब्ध सूचकों के आधार पर विकास सूचकांक की गणना कर पिछड़ी हुयी पंचायत समिति एवं अन्तिम छोर पर ग्राम पंचायत तक की पहचान की गयी है जो कि अपने आप में एक सर्वोच्च प्रयास है।

मैं आशा करता हूँ कि मानव विकास प्रतिवेदन समय-समय पर तैयार करने की कार्यवाही चलती रहनी चाहिए ताकि आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए परिवर्तन का आंकलन किया जा सके। यह जिले का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अथक मार्गदर्शन से तैयार किया गया है। मुझे आशा है कि यह प्रतिवेदन जालोर जिले के विकास के लिए आने वाले नियोजनों में एक नई पहल प्रदान करेगा तथा यह प्रतिवेदन आमजन की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करेगा। जिले के विकास के लिए सभी मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों में एक नई सोच एवं नई दिशा तय करेंगे।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में श्री सुनील कान्त गौतम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालोर श्री जे.पी.महावर (सहायक परियोजना अधिकारी स्वरोजगार, मुख्य आयोजना अधिकारी), एवं जिला सांख्यिकी अधिकारी, जालोर श्री पदमाराम, निजी सहायक मुख्य आयोजना अधिकारी, जालोर तथा स्वास्थ्य का विशयांक तैयार करने में श्री डा. अम्बिका प्रसाद जांगिड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर सफलतापूर्वक कार्य किया है। अतः मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।

(केवल कुमार गुप्ता)

जे. पी.महावर,
सहायक परियोजना अधिकारी (स्वरोजगार)
जिला सांख्यिकी अधिकारी
एवं मुख्य आयोजना अधिकारी, जालोर

कृतज्ञता

जालोर जिले का प्रथम विकास प्रतिवेदन जिला स्तर पर ही तैयार करने का मुझे प्रथम सर्वोच्च अवसर प्राप्त हुआ जिसकी मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है।

मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने में राज्य स्तर से श्री सुरजमल रेगर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर का समय-समय पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा जिनका मैं अत्यन्त आभारी हूँ।

श्रीमान जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री केवल कुमार गुप्ता ने जिले में प्रतिवेदन तैयार करने की योजना एवं अधिकारियों के आमुखीकरण में मार्गदर्शन प्रदान कर इस कार्य को नई दिशा प्रदान की, जिनका मैं अत्यन्त आभारी हूँ।

इस प्रतिवेदन को तैयार में मेरे निजी सहायक श्री पदमाराम कार्यालय मुख्य आयोजना अधिकारी एवं श्री गोरधन भार्मा, सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय ने विशेष सहयोग प्रदान किया। मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला सांख्यिकी स्टाफ का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समय-समय पर सूचनाएँ उपलब्ध करवाई।

प्रतिवेदन को तैयार करने में जिला स्तरीय अधिकारियों विकास अधिकारियों ने समय-समय पर मानव विकास प्रतिवेदन का विशयांक तैयार करने में सहयोग दिया है जिनका मैं आभारी हूँ।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह प्रतिवेदन जालोर जिले के विकास के लिए आने वाले नियोजनों में एक नई पहल प्रदान करेगा तथा यह प्रतिवेदन आमजन का जिले की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करेगा एवं जिले के विकास के लिए सभी मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों में एक नई सोच एवं एक नई दिशा तय करेंगे।

(जे.पी. महावर)

मानव विकास की अवधारणा

भारतीय मूल के अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन के अनुसार आर्थिक वृद्धि से यह आशयक नहीं कि सभी लोगों का कल्याण ही हो। उनके अनुसार मानव विकास का मूल उद्देश्य मनुष्यों के पास उपलब्ध विकल्पों को बढ़ाना। मानव विकास वह है, जिसमें लोग अपनी पसन्द का जीवन जी सकें और इसके लिए उनके पास समान अवसर एवं दक्षता हो। मानव विकास, के सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मानव की रुचियों, अवसरों तथा क्षमताओं के विस्तार पर बल देता है। मानव विकास एक मुक्त निरन्तर एवं सैद्धान्तिक तौर पर कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है।

मूलभूत रूप से मानव विकास के चार मुख्य स्तम्भ हो सकते हैं—

शिक्षा

स्वास्थ्य

आजीविका—मूलभूत भौतिक संसाधन जो उत्तम जीवन स्तर के लिए आवश्यक है।

महिला विकास— सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता एवं एकजुट होकर कार्य करने की संभावना।

जालोर जिले में मानव विकास :-

जिले का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए मानव विकास को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्याएं, उनके निवारण हेतु उपलब्ध संसाधन एवं आवश्यकता हेतु सुझाव तथा जटिल क्षेत्र के चिन्हीकरण एवं उनके विकास हेतु मुख्य बिन्दुओं पर प्रस्ताव/सुझाव तथा जिले की वर्तमान स्थिति का वर्ष 2001 से तुलना करते हुए वर्ष 2015 तक की संभावनाओं का विश्लेषण विभागीय अधिकारियों, पंचायत समिति स्तर के कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं महिला विकास पर विशेष बल दिया गया है। जिले में शिक्षा क्षेत्र में 6 से 14 आयु तक के सभी बालक बालिकाओं को 2015 तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तथा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे – बालिका नामांकन कैसे बढ़ाया जायें, प्राथमिक शिक्षा का सुदृढीकरण कैसे हो, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति कैसे सुनिश्चित हो एवं शिक्षा को रोजगारपरक कैसे बनाया जायें।

जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंगानुपात, टीकाकरण आदि मामलों में प्रगति की ओर समग्र प्रयास किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक छत के नीचे लाकर उनके क्रियान्वयन के लिये समन्वित प्रयासों से और अधिक गति दी जा रही है। इस मिशन के तहत आम आदमी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने जिले में धनवन्तरी एम्बुलेंस 108 सेवा संचालन किया है, जिससे किसी भी आकस्मिक घटना में गंभीर रूप से घायल तथा गंभीर बीमारी से आकस्मिक घटना/हृदयघात के कारण या आकस्मिक प्रसव वेदना में

महिला को तुरन्त अस्पताल पहुँचाना संभव हो। जिले में आधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षित कुशल चिकित्सक के अभाव में लोगों का पड़ोसी राज्य गुजरात की ओर हो रहा पलायन अहम चिन्ता का विषय है। अतः जिले को पर्याप्त अत्याधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन युक्त सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों को विकसित कर लोगों का गुजरात की ओर पलायन रोकने की भावी रणनीति 2015 तक होगी।

जिले में सिंचाई का अभाव होने से पर्याप्त मात्रा में अकृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाकर कृषि योग्य बनाना। वर्तमान में जालोर जिला ग्रेनाईट सिटी के नाम से विख्यात है। जिले में विस्थापित लघु एवं वृहद उद्योगों में वर्तमान कमियों को दूर कर जिले को आद्योगिक जिला घोषित करने की भावी रणनीति तय करनी है, जिससे रोजगार की तलाश में अन्य राज्य की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सके। महिला विकास में नई जागृति उत्पन्न करने संबंधी सुझाव एवं निराकरण की भावी रणनीति तय करने के विशेष सुझावों का समावेश इस प्रतिवेदन में किया गया है।

जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए

जालोर जिले में निम्न प्रक्रिया अपनायी गयी :-

राज्य स्तर पर दिनांक 22 से 24 जून 2009 तक कार्य जाला आयोजित कर जिला स्तर पर मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया स्पष्ट की एवं

मार्ग-दर्शन प्रदान किया गया। जिला स्तर पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए राज्य स्तर से यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवेदन जिला कलेक्टर के नेतृत्व में तैयार किया जायेगा। जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर एक मानव विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया तथा कोर कमेटी का गठन किया गया।

मुख्य आयोजना अधिकारी, जालोर को जिला मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया।

जिला स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में दिनांक 15.7.09 को एक दिवसीय कार्य जाला आयोजित की गयी। इस कार्य जाला में राज्य स्तर से श्री मनोज राउत, कन्सल्टेन्ट डेमाग्राफर, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर एवं जिला स्तरीय अधिकारीगण ने भाग लिया। कार्य जाला में प्रतिवेदन तैयार करने के प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा की। कार्य जाला में यह निर्णय लिया गया कि यह जिला ग्रेनाईट नगरी के नाम से विख्यात है तथा नर्मदा परियोजना इस जिले के लिए जीवनदान है। अतः इस पर एक विशेष नोट तैयार किया जावे।

कोर कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं महिला विकास विषयांक पर एक नोट तैयार करने के लिए टीम लीडर नियुक्त किये गये। जो तालिका संख्या 1.1 अनुसार है-

तालिका संख्या : 1.1

विषयांक	टीम लीडर
शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी
स्वास्थ्य	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर
आजीविका	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
महिला विकास	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास अधिकारी

टीम लीडरों द्वारा समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया गया। इस जिले से संबंधित मुद्दों पर जिला मुख्य समन्वयक (मुख्य आयोजना अधिकारी) के साथ विचार विमर्श कर प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया।

जिला स्तर पर श्रीमान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 12.10.09 को आयोजित बैठक में प्रतिवेदन पर समीक्षा की गयी। प्राप्त सुझाव को सम्मिलित कर प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा श्रीमान निदेशक एवं उप ग्रासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को प्रेषित किया गया।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में 31 मार्च 2009 तक की अधिकृत सूचनाओं को ही सम्मिलित किया गया। इस जिले में विशय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रयास कर इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सफल प्रयास किया है।

अध्याय—८

जालोर जिला एक परिचय

1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

महर्षि जाबालि की तपोभूमि होने के कारण जिले के प्रमुख नगर का नाम जाबालिपुर तथा कालान्तर में जालोर हुआ जो वर्तमान जिला जालोर मुख्यालय है। यहां के प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राज्य सीमाओं का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी (सिन्ध से बंगाल) तक किया। राष्ट्रभक्ति और आन-बान के लिये समर में मर-मिटने वाले सोनगरा चौहानों ने परमारों से छीनकर इसे अपनी राजधानी बनाया। जिले के तीन प्रमुख नगरों जालोर, भीनमाल तथा सांचौर पर प्राचीनकाल में क्षत्रियों के प्रतिहार परमार, चौहान, पठान, मुगल तथा राठौड़ राजवंशों ने शासन किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वर्तमान जालोर जिला तत्कालीन जोधपुर रियासत का एक भाग था। 30 मार्च, 1949 को राजस्थान राज्य बना तो जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय हो गया। राजस्थान में विभिन्न जिलें बनाये गये तो जालोर जिला अपने अस्तित्व में आया।

भौगोलिक स्थिति

यह जिला राजस्थान राज्य के दक्षिण-पश्चिम भाग में 24°37' उत्तरी अक्षांश से 25°49' उत्तरी अक्षांश तथा 71°11' पूर्वी देशान्तर से 73°05' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल सर्वे ऑफ इण्डिया के अनुसार 10640 वर्ग किलोमीटर है, (जबकि जिला कलेक्टर भू अभिलेख के अनुसार जिला का कुल क्षेत्रफल 10566 वर्ग किलोमीटर है) जो कि राज्य का 3.11 प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है। क्षेत्रफल दृष्टि से जिले का 12 वां स्थान है। जिले की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर जिला जोधपुर, उत्तर पूर्वी सीमा पर जिला पाली, दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर जिला बाडमेर, दक्षिणी पूर्वी सीमा पर जिला सिरौही एवं दक्षिणी सीमा पर गुजरात राज्य स्थित है।

टोपोग्राफी एवं जलवायु

भूगर्भिक संरचना एवं मिट्टी – जिले का अधिकांश भाग चतुर्थ युगीन व अभिनूतन कालीन जमावों से आच्छादित है। ये जमाव वायु परिवहित वायु रेत (बालू), नवीन कछारी मिट्टी, प्राचीन कछारी मिट्टी तथा ग्रिट के रूप में जिले के अधिकांश धरातल पर दृष्टिगोचर होते हैं। चट्टानों में मालानी ज्वालामुखी तथा जालोर ग्रेनाइट प्रमुख है। जिले की मिट्टी अनुसार क्षेत्रफल निम्नानुसार है—

दोमट—107096 हैक्टर

बलुई दोमट— 663745 हैक्टर

काली मिट्टी— 94545 हैक्टर

खण्डी— 191216 हैक्टर

पहाडियों – भीनमाल तहसील के दक्षिण-पूर्वी भाग में जिले की सबसे ऊंची पहाडियों जसवंतपुरा की पहाडियां हैं। जिसकी सबसे ऊंची चोटी सुन्धा 991 मीटर (3252 फीट) ऊंची है। यह जिले की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जिले में अन्य भी छोटी-छोटी पहाडियां हैं जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा हैं। आहोर, भीनमाल, लाखावास, जालोर तथा जसवंतपुरा के पास अरावली की पहाडियां ही हैं जिनकी समुन्द्रतल से उचाई 173.73 मीटर है।

नदियाँ – सम्पूर्ण जिला लूनी बेसीन का एक भाग है। अतः लूनी नदी तथा उसकी सहायक जवाई, सूकडी, खारी, बाण्डी तथा सागी नदियां जिले के प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। सभी नदियां बरसाती हैं, जो मानसून के बाद सूख जाती हैं। जिले में कोई बाराहमासी नदी नहीं है।

जलवायु एवं वर्षा – जिले का सम्पूर्ण भू-भाग उच्च तापक्रम, न्यून आर्द्रता तथा अल्प व अनियमितता वर्षा वाले क्षेत्र में गिना जाता है जिले की जलवायु शुष्क है और अधिकांश भाग में रेगिस्तान फैला हुआ है। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 43 सेमी. है तथा अधिकतम औसत तापमान 42 डी.सी. है जो कभी-कभी 48 डी.सी. तक भी पहुंच जाता है। न्यूनतम औसत तापमान 6.25 डी.सी. है जो कभी-कभी 0 डी.सी. तक भी हो जाता है। जिले में विगत वर्षों में हुई वर्षा का तहसीलवार विवरण तालिका संख्या 1.2 में दर्ज है।

तालिका संख्या : 1.2

वर्षावार वर्षा

तहसील	वर्षा (मिमी)	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
अमृतहम	300 ⁰⁵	385 ⁰⁸	172 ⁰⁹	657 ⁰⁷	200 ⁰⁴	286 ⁰⁹	399 ⁰⁶	292 ⁰⁷	367 ⁰⁵	341 ⁰¹		189 ⁰⁹	
शंखवल्लभ	311 ⁰⁴	340 ⁰⁸	171 ⁰⁹	660 ⁰⁶	314 ⁰²	320 ⁰⁶	713 ⁰²	368 ⁰⁵	343 ⁰⁶			198 ⁰⁶	
शंखवल्लभ	311 ⁰⁴	340 ⁰⁸	171 ⁰⁹	660 ⁰⁶	314 ⁰²	320 ⁰⁶	713 ⁰²	368 ⁰⁵	343 ⁰⁶			198 ⁰⁶	405 ³⁰
दीपतम	293 ⁰⁴	333 ⁰⁸	126 ⁰⁹	727 ⁰⁸	342 ⁰⁵	440 ⁰⁶	699 ⁰⁵	412 ⁰⁵	261 ⁰⁶			149 ⁰⁶	
ठीपदउंस	384 ⁰³	296 ⁰⁸	141 ⁰⁹	717 ⁰⁴	335 ⁰⁵	484 ⁰⁴	1031 ⁰⁴	455 ⁰⁵	383 ⁰⁶			216 ⁰⁰	
श्रनूंदजचनतं	285 ⁰⁵	602 ⁰⁸	363 ⁰⁹	630 ⁰⁷	225 ⁰⁵	615 ⁰⁶	933 ⁰⁴	482 ⁰⁴	466 ⁰⁶			180 ⁰⁰	
तंदपूकं	244 ⁰⁰	505 ⁰⁸	171 ⁰⁹	762 ⁰⁷	395 ⁰⁵	457 ⁰⁶	935 ⁰⁴	398 ⁰⁵	467 ⁰⁶			239 ⁰⁰	
दबीवतम	285 ⁰⁵	238 ⁰⁸	65 ⁰¹	840 ⁰⁷	249 ⁰⁵	352 ⁰⁶	810 ⁰⁴	332 ⁰⁵	332 ⁰⁶			108 ⁰⁰	
लंसं	0 ⁰⁰	0 ⁰⁰	0 ⁰⁰	323 ⁰⁷	239 ⁰⁵	255 ⁰⁸	565 ⁰⁶	218 ⁰⁵	203 ⁰⁶			222 ⁰⁸	

;वनतबम कपेज ब्वससमबजवण श्रंसवतमद्ध

खनिज सम्पदा –खनिज सम्पदा की दृष्टि से यह जिला पिछडा हुआ हैं। ग्रेनाइट, फलोसपार व जिप्सम के अलावा अन्य कोई खनिज प्रमुखता से उपलब्ध नहीं हैं। पिक किस्म का ग्रेनाइट जालोर कस्बे के पास केशवना, सियाना व अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। फलोसपार की चट्टान करारा क्षेत्र में है। ग्रेनाइट ने जिले को प्रदेश के खनिज उत्पादन करने वाले जिलों में दर्शाया है। फलोसपार स्टील व अन्य उद्योगों में काम करने वाला महत्वपूर्ण खनिज हैं।

जिले में उत्पादित ग्रेनाइट जालोर से ताईवान, चीन, नाईजीरिया कतार, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिश्र, कनाडा, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इटली, इण्डोनेशिया, जापान आदि देशों को कांडला बन्दरगाह (गुजरात) से निर्यात किया जाता है। जिले में कुल खान 537 है। जिनमें प्रधान खनिज की 5 व अप्रधान खनिज की 532 है।

वन सम्पदा – जिले में कुल वन क्षेत्र 45068 हेक्टेयर है, जिसमें 12223.82 हेक्टेयर, आरक्षित वन क्षेत्र, 29804.92 हेक्टेयर रक्षित वन क्षेत्र तथा 3231.74 हेक्टेयर अवर्गीकृत वन क्षेत्र हैं। जिले में उपलब्ध पेड मुख्यतया जाल , रोहिडा , खेजडी , बबूल , कुमद , नीम , केर आदि हैं। जसवंतपुरा वन क्षेत्र में औषधियां वाले पौधे भी उपलब्ध हैं।

1.4 प्रशासनिक संरचना

प्रशासनिक दृष्टि से जालोर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कार्यालय तथा विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालय स्थित है। जिले को पांच विधान सभा क्षेत्र एवं उन्ही को पांच उपखण्डों जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, सांचौर में विभक्त किया गया हैं। राजस्व प्रशासन के लिए जिले को सात तहसीलों जालोर, भीनमाल, रानीवाडा, सांचौर, सायला, बागौडा एवं आहोर तथा सात विकास खण्डों में अर्थात जालोर, भीनमाल, आहोर, सायला, रानीवाडा, जसवंतपुरा व सांचौर में विभाजित कर सात पंचायत समिति कार्यालय विकास अधिकारी के नाम से स्थापित किये गये। जिले में तीन नगर पालिका क्षेत्र जालोर, भीनमाल एवं सांचौर हैं। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस प्रशासन हेतु जिला मुख्यालय पर एक पुलिस अधीक्षक, एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा तीन उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय जालोर, भीनमाल व सांचौर में स्थित हैं। उनके अधीन 15 पुलिस थाने एवं 8 चौकी है। जिले में जालोर, भीनमाल एवं सांचौर तीन उपखण्ड मुख्यालयों पर उपकारागृह है। जिले में राजस्व ग्राम 793, आबाद ग्राम 786, गैर आबाद 7, ग्राम पंचायतें 264, पटवार मण्डल 301, भू-निरीक्षक मण्डल 34 हैं तथा जिले संबंधित सामान्य सूचना इन सभी का विवरण तालिका संख्या 1.3, 1.4 एवं 1.5 में दिया गया है।

तालिका संख्या : 1.3

प्रशासनिक इकाईयाँ उपखण्ड व तहसीलवार –

क्रस	उपखण्ड	तहसील	नगर/कस्बा	गांवों की संख्या			जनसंख्या
				आबाद	गैरआबाद	योग	
1	जालोर	जालोर	जालोर	73	1	74	219381

		सायला	—	50	0	50	137804
2	आहोर	आहोर	—	135	3	138	207961
3	भीनमाल	भीनमाल	भीनमाल	103	2	105	221546
		बागोडा	—	57	—	57	130895
4	सांचौर	सांचौर	सांचौर	273	1	274	368004
5	रानीवाडा	रानीवाडा	—	95	—	95	163349
योग	5	7	3	786	7	793	1448940

(क्पेज ब्वससमबजवत स्प्ट 2009)

जालोर जिले में कुल 7 गैर आबाद ग्राम है, जिसमें तहसील जालोर में चक सामतीपुरा, तहसील आहोर में खेडा सुलिया, खेडा सांवरी एवं मोरी टोकरीया, तहसील भीनमाल में चक चांदणा एवं चक चांदपान तथा तहसील सांचौर में रणखार है।

तालिका संख्या : 1.4

प्र गासनिक इकाईयाँ उपखण्ड व पंचायतीराज / स्थानीय निकायवार —

क्रस	उपखण्ड	पं.समिति	ग्रा.प.संख्या	जनसंख्या	न.पा.	जनसंख्या
1	जालोर	जालोर	28	131827	जालोर	44830
		सायला	38	211147		
2	आहोर	आहोर	41	177342		
3	भीनमाल	भीनमाल	35	184751	भीनमाल	39280
		जसवंतपुरा	29	128410		
4	सांचौर	सांचौर	63	342120	सांचौर	25884
5	रानीवाडा	रानीवाडा	30	163349		
योग	5	7	264	1338946	3	109994

(क्पेज ब्वससमबजवत स्प्ट 2009)

1.5 जिले की सामान्य सूचनायें —

तालिका संख्या : 1.5

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	कुल जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणनानुसार)	1448940
2.	पुरुश सख्या प्रति त	737880
		50 ^९ 93

3	स्त्री	सख्या	711060
		प्रति 100	49 ^० 7
4	ग्रामीण	सख्या	1338946
		प्रति 100	92 ^५ 41
5.	भाहरी	सख्या	109994
		प्रति 100	7 ^५ 9
6	अनु.जाति	सख्या	261315
		प्रति 100	18 ^० 03
7	अनु.जनजाति	सख्या	126799
		प्रति 100	8 ^५ 75
8.		जनसंख्या वृद्धि दर (वर्ष 1991-2001)	26 ^५ 81
9.		जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किलोमीटर)	136
10.		स्त्री पुरुष अनुपात	964
11.		कुल परिवार	244908
12.		बी.पी.एल. परिवार	83157
13.		व्यवसायिक कार्यों में कुल कार्यशील जनसंख्या	727209
14.		मुख्य कार्यशील	506324
15.		कृषक	482684
16.		कृषि श्रमिक	80673
17.		गृह उद्योग कामगार	23529
18.		अन्य कामगार	140323
19.		सीमान्त कामगार	220885

(स्रोत जनगणना 2001)

जिले में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की राष्ट्र एवं राज्य स्तर से तुलनात्मक स्थिति तालिका अनुसार है -

तालिका संख्या : 1.6

क्र.	संकेतांक	जिला स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1	<u>शिक्षा</u> 1. साक्षरता दर	46 ^५ 49	60 ^५ 41	64 ^५ 80
	2. महिला साक्षरता दर	27 ^५ 80	43 ^५ 85	53 ^५ 70

	3. पुरुष साक्षरता दर	64 ^७ 72	75 ^७ 70	75 ^७ 30
	4. नामांकन दर	96 ^७ 92	.	.
	5. शिक्षक छात्र अनुपात	48 रू 1	.	.
2	<u>स्वास्थ्य</u> 1. शिशु मृत्यु दर	88	79	54
	2. अशोधित जन्म दर	24 ^७ 01	.	.
	3. अशोधित मृत्यु दर	5 ^७ 90	7 ^७ 60	.
	4. स्त्री-पुरुष अनुपात	964	921	.
	5. दम्पति संरक्षा दर	47 ^७ 02	43 ^७ 90	.
	6. कुल प्रजनन दर	3 ^७ 00	3 ^७ 01	.
	7. मातृ मृत्यु दर	650	677	.
	8. संस्थागत प्रसव दर	20 ^७ 40	31 ^७ 52	.

1.7 जिले के संसाधनों का वि लेशन

1.7.1 जनसंख्या

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1448940 है। इसका पंचायत समिति, नगर पालिका एवं तहसील वार अनुजाति एवं जनजाति की जनसंख्या विवरण तालिका संख्या 1.7 एवं 1.8 के अनुसार है—

तालिका संख्या : 1.7

पंचायतराज/स्थानीय निकायवार कुल, अनुजाति व जनजाति की जनसंख्या व बीपीएल परिवार—

क्रस	प.स./न.पालिका	जनसंख्या	अनुजाति	अनुजनजाति	बीपीएल परिवार
1	प.स.जालोर	131827	26097	13588	5108
2	प.स. सायला	211147	42426	15891	9062
3	प.स. आहोर	177342	34585	21124	5142
4	प.स.भीनमाल	184751	23405	18793	11692
5	प.स.जसवंतपुरा	128410	20653	13355	4768
6	प.स.सांचौर	342120	61350	15330	33973
7	प.स.रानीवाडा	163349	31736	23229	9994
योग ग्रामीण		1338946	240252	121310	78729
8	न.पा.जालोर	44830	8285	2426	1552
9	न.पा.भीनमाल	39280	6406	2203	1425
10	न.पा.सांचौर	25884	6372	860	1451
योग नगर		109994	21063	5489	4428
कुल योग		1448940	261315	126799	83157

(स्त्रेात जिला परिषद (ग्राविप्र) जालोर 2009)

अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या का विवरण—

तालिका संख्या : 1.8

क्रस	तहसील	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	जालोर	36818	8285	45103	18897	2426	21323
2	आहोर	40031	0	40031	24009	0	24009
3	सांचौर	61350	6372	67722	15330	860	16190
4	भीनमाल	30233	6406	36639	18947	2203	21150

5	रानीवाडा	31736	0	31736	23246	0	23246
6	सायला	26256	0	26256	7680	0	7680
7	बागोडा	13828	0	13828	13201	0	13201
योग		240252	21063	261315	121310	5489	126799

1.7.2 जनसंख्या विलेखण

जिले की जनसंख्या की उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि जिले में भाहरी आबादी बहुत कम मात्र 7.59 प्रति त है। जबकि ग्रामीण आबादी 92.41 प्रति त है। यह इससे भी स्पष्ट है कि जिले में राज्य की कुल 0.83 प्रति त भाहरी आबादी ही रहती है। जबकि राज्य की ग्रामीण आबादी का 3.09 प्रति त भाग निवास करता है। जिले में भाहरी आबादी का कम होना जिले में गरीबी को स्पष्ट दर्शाता है। क्योंकि ग्रामीण आबादी अधिक होने से स्पष्ट है कि अधिकतर लोग अभी भी कृषि या उसकी सहायक गतिविधियों से ही अपना जीवनयापन करते हैं। ग्रामीण आबादी में शिक्षा का स्तर भी भाहरी आबादी की तुलना में काफी कम है। जिले में राज्य के क्षेत्रफल के अनुपात में जिले की आबादी कम है। जहाँ राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर 165 है, वहीं जिले का घनत्व 136 ही है। जो यह दर्शाता है कि जिले में प्रति व्यक्ति राज्य के औसत से अधिक भूमि उपलब्ध है। जिले में भी रानीवाडा क्षेत्र में घनत्व अधिक है, जबकि सांचौर क्षेत्र में घनत्व काफी कम है।

1.7.3 जनसंख्या वृद्धि दर

जिले में वर्ष 1991 में जनसंख्या 1142563 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 1448940 हो गई। इस प्रकार 1991-2001के दशक में जनसंख्या में कुल वृद्धि 26.81 प्रति त रही। जिसका विवरण वार तालिका संख्या 1.9 में अंकित की गयी है।

तालिका संख्या : 1.9

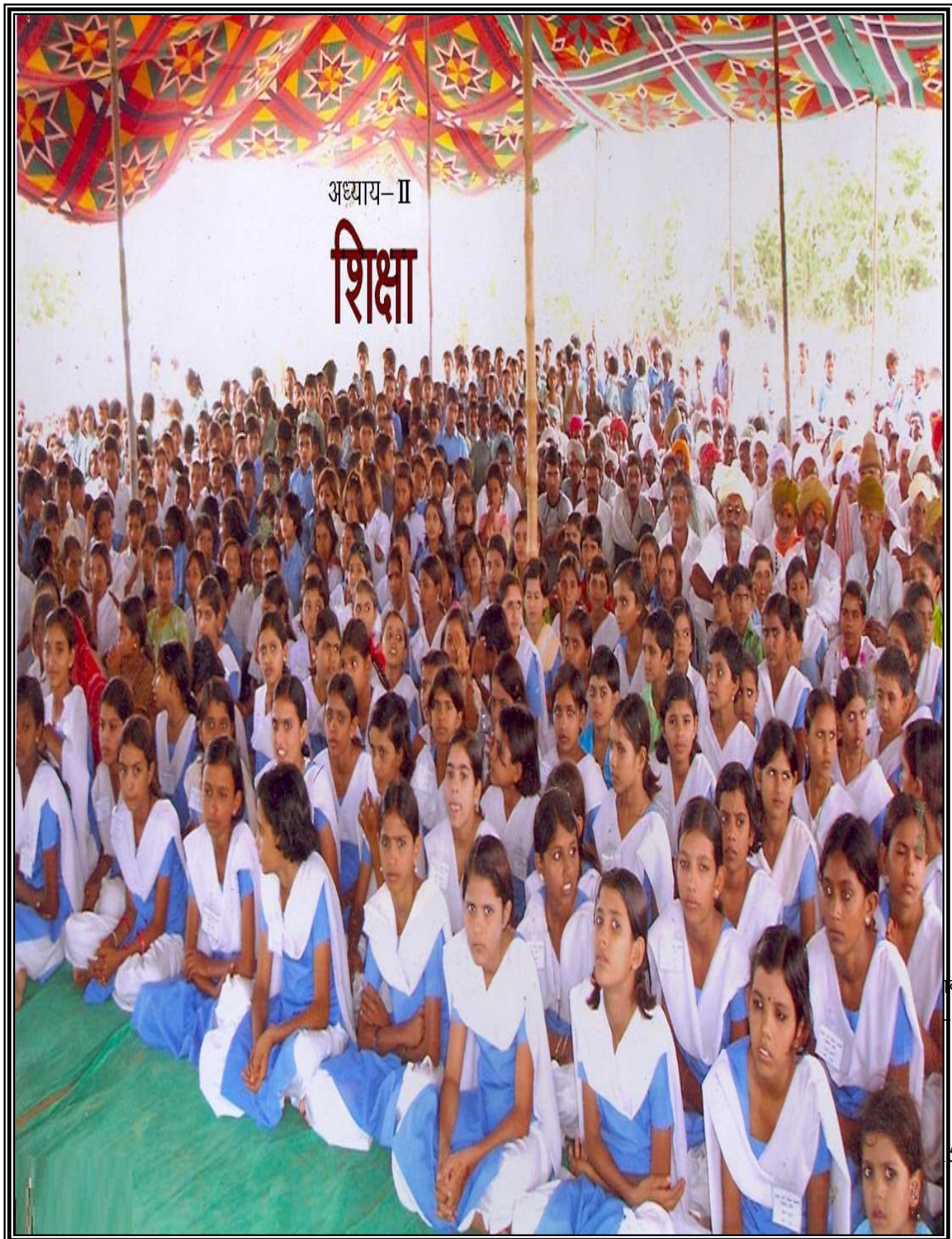
जनसंख्या वृद्धि दर

वर्ष	जनसंख्या	10वर्षों का अंतर	प्रति त/कमी/वृद्धि
1971	667950	120878	+ 22.10
1981	903073	235123	+ 35.20
1991	1142563	239490	+ 26.52
2001	1448940	306377	+ 26.81

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले में वर्ष 1991 में जनसंख्या 1142563 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 1448940 हो गई। इस प्रकार 1991-2001के दशक में जनसंख्या में कुल वृद्धि 26.81 प्रति त रही। जिसका विवरण वार तालिका संख्या 1.10 में अंकित की गयी है।

इससे पूर्व के दशक 1981-91 में यह वृद्धि दर 26.52 तथा उससे पूर्व के दशक 1971-81 में यह वृद्धिदर 35.20 थी। इससे स्पष्ट है कि 1971-81 के मुकाबले 1981-91 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर में काफी कमी

आयी लेकिन 1981-91 के मुकाबले 1991-2001 में जनसंख्या वृद्धि दर में मामूली वृद्धि हुई अर्थात पिछले लगभग 20 वर्षों से जिले में लगभग 2.6 प्रति शत प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासों का इस पर कोई असर दिखायी नहीं दे रहा है।



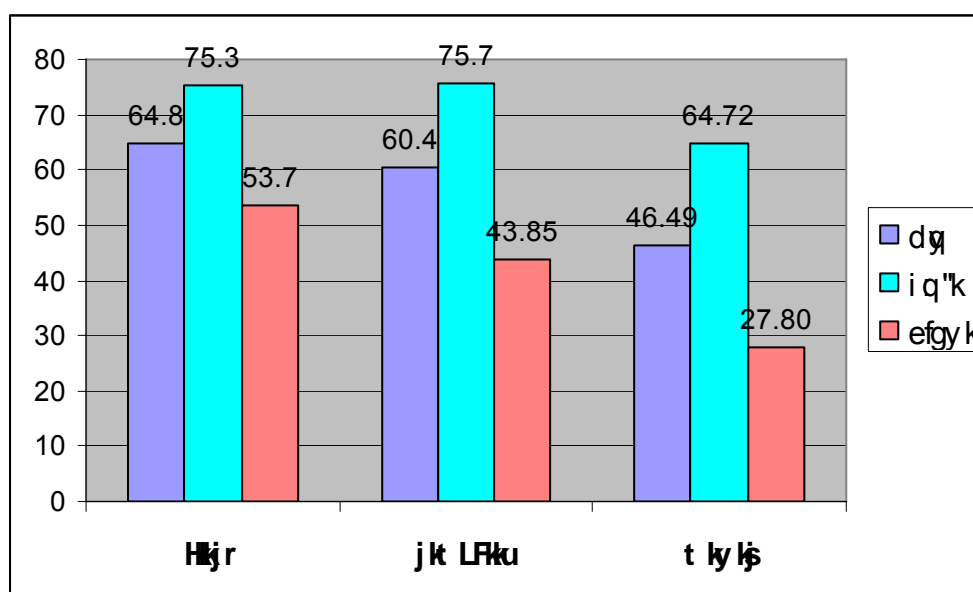
जालोर जिला प्राचीनकाल से शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थिति पर था। जिले में जहां आजकल तोपखाना हैं, वह वस्तुतः परमार राजा भोज द्वारा बनाई गयी संस्कृत पाठशाला है। भीनमाल तहसील में कवि माघ संस्कृत विद्वान रहे हैं, जिनकी ख्याति विद्वानों में विख्यात रही है।

2.1.1 साक्षरता की ऐतिहासिक भौक्षिक पृष्ठभूमि

जालोर जिला राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र के अन्तिम छोर पर स्थित है। जनगणना 2001 के अनुसार जिले की साक्षरता दर 46.49 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 64.72 एवं महिला की साक्षरता 27.80 प्रतिशत है। साक्षरता की दृष्टि से जालोर जिला राजस्थान में 31वें स्थान पर है। इस जिले की साक्षरता की स्थिति चित्र संख्या 2.1 में दर्शायी गयी है।

चित्र संख्या 2.1

साक्षरता दर



संकेतित बम देने

2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जालोर जिले की महिला साक्षरता दर राज्य एवं राष्ट्रीय साक्षरता दर से क्रमशः 16.05 : एवं 25.9 : कम है एवं पुरुष साक्षरता दर राज्य एवं राष्ट्रीय साक्षरता दर से क्रमशः 10.98 : एवं 10.58 : कम है।

2.1.2 साक्षरता की स्थिति –

जिले की चार दशकों में 1971 से 2001 तक साक्षरता दर 36.37 प्रतिशत वृद्धि हुयी है जो सराहनीय कदम है। साक्षरता की दृष्टि से जिले का राजस्थान में 31 वां स्थान है।

दशकवार स्थिति तालिका संख्या 2.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका संख्या 2.1

साक्षरता की स्थिति

दशक	व्यक्ति	पुरुष	महिला
-----	---------	-------	-------

1971	10 ^० 03	16 ^५ 53	3 ^२ 27
1981	13 ^७ 7	22 ^५ 43	4 ^५ 43
1991	23 ^७ 7	38 ^९ 97	7 ^७ 5
2001	46 ^५ 49	64 ^७ 72	27 ^७ 80

वर्तमान बरम्बर – वर्तमान श्रंसवतत उंतबी 2009

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1971 से 2001 के दशक में जालोर जिले में महिला साक्षरता में 24.53 व पुरुष साक्षरता में 58.02 प्रतिशत सराहनीय वृद्धि हुई है।

2.1.3 साक्षरता का विशेषण

भाषा आधारित भौक्षणिक स्थिति :-

जालोर जिले की सम्पूर्ण आबादी की मातृभाषा प्रायः मारवाडी है, जो राजस्थानी भाषा की मुख्य बोली है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले की सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाओं में प्रायः हिन्दी माध्यम से अध्यापन कार्य हो रहा है। वर्तमान में समय की मांग को देखते हुए निजी शिक्षण संस्थाओं में जालोर, भीनमाल व सांचौर में दो-दो विधालय माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से भी उपलब्ध करवाई जाती है।

जातीय आधार पर स्थिति :-

जालोर जिले में प्रायः प्रत्येक जाति बिरादरी की सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएँ एवं संगठन शिक्षा को बढ़ावा देने में अपनी क्षमता व आवकता के आधार पर छात्रावास व शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन छोटे-बड़े स्तर पर करते हैं। वर्तमान समय में जालोर जिले में शिक्षा एवं साक्षरता के दृष्टिकोण से विभिन्न जाति सबसे अग्रणी है। जालोर जिले में बहुसंख्यक आबादी अनुसूचित जातियों में मेघवाल, अनुसूचित जनजातियों में भील, अन्य पिछड़ा वर्ग में रेबारी, कलबी, स्वर्ण जातियों में भोमिया राजपुत एवं अल्प संख्यक समुदाय में मुसलमानों में साक्षरता दर सबसे कम है। इन जातियों में बालिका शिक्षा अनुमानित मात्र 10 से 20 प्रतिशत तक ही है। इसी वजह से जालोर जिले की कुल साक्षरता 2001 की जनगणना के अनुसार मात्र 46.49 प्रतिशत ही है।

धार्मिक समूह आधारित भौक्षणिक स्थिति :-

जालोर जिले में शिक्षा एवं साक्षरता के दृष्टिकोण से बहुसंख्यक हिन्दू आबादी का शैक्षणिक एवं साक्षरता का प्रतिशत जिले की शिक्षा एवं साक्षरता प्रतिशत के बराबर है। इस जिले में मुसलमान, सिख, ईसाई समुदाय की आबादी कम है। मुसलमान अपने बच्चों को उर्दू माध्यम से मदरसों में भी शिक्षा देने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन अधिकतर मुसलमान हिन्दी माध्यम से ही राजकीय शिक्षण – संस्थाओं में अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। मुसलमानों में बालिका शिक्षा मात्र 10 से 20 प्रतिशत ही पायी जाती है। सिख, ईसाई समुदाय के कुछ परिवार जालोर जिले में रहते हैं, जिनमें शिक्षा विभाग के आकलन के अनुसार अनुमानित साक्षरता का स्तर 80 प्रतिशत के लगभग है।

2.2 विद्यालयों की स्थिति-

2.2.1 विद्यालयों की संख्या-

जिले में सन् 2001 तक प्राथमिक विद्यालय एवं उच्चतर विद्यालयों की स्थिति तालिका संख्या 2.2 में दर्शायी गयी है।

तालिका संख्या : 2.2

विद्यालय की संख्या

वर्ष	विद्यालयों की संख्या			
	प्राथ.विधा.	उच्चप्राथ.वि	माध्य.वि	उच्च माध्यवि
2001	926	309	84	33
2009	1364	746	173	66

संस्करण - मसम श्रंसवतम उंतबी 2009

उपरोक्ता तालिका से स्पष्ट है 2001 की तुलना में 2009 में विद्यालयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुयी है।

2.2.2 शिक्षा सुविधाएं -

जिले में गांवों से दूरी के संबंध में मानदण्ड की स्थिति तालिका संख्या 2.3 में दर्शायी गयी है।

तालिका संख्या 2.3

शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच 2009

स्तर	मानदण्ड	स्थिति
प्राथमिक	एक किलो मीटर की सीमा में	86.5 (232 वासस्थान में सुविधा नहीं)
उच्च प्राथमिक	तीन किलो मीटर की सीमा में	90.7 (96 वासस्थान में सुविधा नहीं)
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	पांच किलो मीटर की सीमा में	68.34 (76 वासस्थान में सुविधा नहीं)

संस्करण - मसम श्रंसवतम उंतबी 2009

श्रंसवतम उंतबी 2009

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग के मानदण्ड के अनुसार प्राथमिक विद्यालय एक किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। जिले में अभी भी 232 वासस्थान क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ प्राथमिक स्तर का विद्यालय होना जरूरी है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय भी तीन किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए परन्तु 96 वास स्थान क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति सोचनीय है।

2.3 नामांकन-

जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामांकन 2008 - 2009 में कक्षा वार स्थिति तालिका संख्या 2.4 में अंकित की गयी है।

तालिका संख्या : 2.4

कक्षावार नामांकन

कक्षा	छात्र	छात्रा	योग
1 से 5	158205	126310	284515
6 से 8	63303	35288	98591
9से 10	21520	7070	28590
11 से 12	5400	1787	7187
योग	248428	170455	418883

वर्तमान वर्ष - मसम श्रंसवतम उंतबी 2009द

2.3.1 नामांकन अनुपात

जिले में नामांकन की स्थिति तालिका संख्या 2.5 के अनुसार है।

तालिका संख्या 2.5.1

समस्त नामांकन						
स्तर		कुल नामांक			अनुपात	
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा
प्राथमिक	प्राथमिक स्तर	158205	126310	284515	55 ^प 61	44 ^प 39
	उच्च प्राथमिक स्तर	63303	35288	98591	64 ^प 21	35 ^प 79
	योग	221508	161598	383106	57 ^प 82	42 ^प 18
माध्यमिक	माध्यमिक स्तर	21520	7070	28590	75 ^प 27	24 ^प 73
	उच्च माध्यमिक स्तर	5400	1787	7187	75 ^प 14	24 ^प 86
	योग	26920	8857	35777	75 ^प 24	24 ^प 76
कुल योग		248428	170455	418883	59 ^प 31	40 ^प 69

तालिका संख्या 2.5.2

अनुसुचित जाति नामांकन	उच्च माध्यमिक स्तर	1073	203	1276
	योग	4962	1398	6360
कुल योग	कुल नामांक	49580	34376	83956
	छात्र		छात्रा	योग
प्राथमिक	प्राथमिक स्तर	33295	26110	59405
	उच्च प्राथमिक स्तर	11323	6868	18191
	योग	44618	32978	77596
माध्यमिक	माध्यमिक स्तर	3889	1195	5084

तालिका संख्या 2.5.3

अनुसूचित जन जाति नामांकन				
स्तर		कुल नामांक		
		छात्र	छात्रा	योग
ॐ।	प्राथमिक स्तर	18261	12106	30367
	उच्च प्राथमिक स्तर	4135	1417	5552
	योग	22396	13523	35919
तुडै।	माध्यमिक स्तर	854	124	978
	उच्च माध्यमिक स्तर	148	24	172
	योग	1002	148	1150
कुल योग		23398	13671	37069

तालिका संख्या 2.5.4

अन्य पिछडा वर्ग नामांकन				
स्तर		कुल नामांक		
		छात्र	छात्रा	योग
ॐ।	प्राथमिक स्तर	73511	61150	134661
	उच्च प्राथमिक स्तर	34024	17855	51879
	योग	107535	79005	186540
तुडै।	माध्यमिक स्तर	12279	4072	16351
	उच्च माध्यमिक स्तर	2977	1101	4078
	योग	15256	5173	20429
कुल योग		122791	84178	206969

;।ससैवनतबम क्मैमब – म्मम श्रंसवतमद्ध

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले में छात्राओं का अनुपात 40.69 है जो छात्रों की अपेक्षा पर्याप्त से कम है।

2.4 जेण्डर गेप

जालोर जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की संख्या शिक्षा की ओर छात्रों के तुलनात्मक पर्याप्त है तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की ओर निरन्तर कमी होती जा रही है इनमें विशेष कर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं में की संख्या अत्यधिक है। नामांकन में जेण्डर गेप की स्थिति निम्न तालिका 2.6 के अनुसार है।

तालिका संख्या 2.6

जेण्डर गेप

विद्यालय स्तर	विद्यार्थी		कुल जेण्डर गेप	अनुसूचित जाति	अनुजन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अल्प संख्यक
	छात्र	छात्रा					
प्राथमिक	158205	126310	11 ^१ 11	12 ^१ 71	16 ^१ 47	7 ^१ 81	17 ^१ 37
उच्च प्राथमिक	63303	35288	28 ^१ 41	18 ^१ 91	39 ^१ 67	15 ^१ 77	18 ^१ 07
माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक	26920	8857	50 ^१ 49	41 ^१ 86	68 ^१ 10 ^१	39 ^१ 85	47 ^१ 56

स्रोत: जनसंख्या विवरण, 2011

संकेत - स्तम्भ संश्लेषण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले में छात्रों की तुलना में छात्राओं का जेण्डर गेप प्रति शैक्षणिक स्तर अत्यधिक है।

2.4.1 ड्रॉप आउट-

जिले में छात्र-छात्राओं का विद्यालय से ड्रॉप आउट प्रति शैक्षणिक स्तर अत्यधिक है, जिसके कारण तालिका संख्या 2.7 के अनुसार है-

ड्रॉप आउट के कारण

तालिका संख्या : 2.7

क्र.सं.	विवरण
1	अभिभावकों की कमजोर आर्थिक स्थिति
2	ग्रामीण क्षेत्र में परम्परागत सोच के आधार पर बड़ी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजने की मानसिकता
3	महिला शिक्षकों की कमी
4	स्वयं के गांव में या पांच किमी की परिधी में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय का नहीं होना।
5	ग्रामीण क्षेत्र में परम्परागत सोच के आधार पर बड़ी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजने की मानसिकता।

2.5 मानव संसाधन की स्थिति

2.5.1 छात्र शिक्षक अनुपात

जालोर जिले में राजकीय विद्यालयों में औसत नामांकन, छात्र शिक्षक अनुपात एवं प्रति विद्यालय औसत शिक्षक उपलब्धता का विवरण तालिका संख्या-2.2.1 अनुसार है :-

तालिका संख्या-2.8

विद्यालय का स्तर	प्रति विद्यालय औसत नामांकन	औसत छात्र शिक्षक अनुपात	प्रति विद्यालय औसत शिक्षक उपलब्धता
प्राथमिक	67.2	42 : 1	1.6
उच्च प्राथमिक	174.4	51 : 1	3.9
माध्यमिक, उच्च माध्यमिक	216.6	46 : 1	4.7

सर्वोत्तम कर्मियों - मसम श्रंसवतमद्ध

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जालोर जिले में प्राथमिक स्तर के विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के लिये 1.6 शिक्षक उपलब्धता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के लिये मात्र 3.9 औसत शिक्षक उपलब्धता है। इसी का परिणाम है कि शिक्षकों की अत्यधिक कमी के कारण जालोर जिला शिक्षा के क्षेत्र में पिछडा हुआ है। जब तक जिला केडरवार शिक्षक भर्ती के माध्यम से शिक्षकों का स्थाई पदस्थापन नहीं होगा तब तक इस स्थिति में विशेष सुधार की गुंजाई कम ही रहती है।

2.5.2 एकल अध्यापक

जिले में ब्लाकवार एकल अध्यापक की विद्यालय स्तर पर स्थिति तालिका संख्या 2.9 के अनुसार है -

तालिका संख्या 2.9

ब्लॉक	विद्यालय का स्तर			
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	योग
आहोर	7	2	0	9
भीनमाल	51	5	0	56
जालोर	12	4	1	17
जसवन्तपुरा	31	0	0	31
रानीवाडा	99	2	0	101
सांचौर	211	3	1	215
सायला	124	3	1	128
योग	535	19	3	557

सर्वोत्तम कर्मियों रंसवतम द्द

2.5.3 रिक्त पदों की स्थिति-

शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त पदों का विवरण नीचे तालिका अनुसार दिया गया है

तालिका संख्या 2.10

गैर शैक्षणिक कार्मिक

विभाग	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तता :
माध्यमिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी मा.	1	0	1	100 ^० 00
	शैक्षिक प्र. अधिकारी	1	0	1	100 ^० 00
	प्रयोग शाला सहायक II	4	1	3	75 ^० 00
	पुस्तकालयाध्यक्ष II	21	13	8	38 ^० 10
	प्रयोग शाला सहायक III	17	14	3	17 ^० 65
	पुस्तकालयाध्यक्ष III	42	35	7	16 ^० 67
	कार्यालय अधीक्षक	1	1	0	0 ^० 00
	कार्यालय सहायक	13	8	5	38 ^० 46
	वरिष्ठ लिपिक	121	70	51	42 ^० 15
	कनिष्ठ लिपिक	91	67	24	26 ^० 37
	जमादार	12	5	7	58 ^० 33
	प्रयोग शाला सेवक	18	14	4	22 ^० 22
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	240	225	15	6 ^० 25
	कनिष्ठ लेखाकार	2	0	2	100 ^० 00
	सांख्यिकी निरीक्षक	1	0	1	100 ^० 00
सहायक लेखाधिकारी	2	2	0	0 ^० 00	
योग		587	455	132	

प्राथमिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा..	1	1	0	0 ^० 00
	अति जिशिअ कम बीईईओ	1	1	0	0 ^० 00
	बीईईओ	6	3	3	50 ^० 00
	एसडीआई	13	2	11	84 ^० 62

	कार्यालय सहायक	4	2	2	50 ^{००}
	कनिष्ठ लेखाकार	6	4	2	33 ^{३३}
	वरिष्ठ लिपिक	3	2	1	33 ^{३३}
	कनिष्ठ लिपिक	13	8	5	38 ^{४६}
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	13	0	0 ^{००}
योग		60	36	24	
सर्व शिक्षा	एडीपीसी	1	1	0	0 ^{००}
	एपीसी	4	4	0	0 ^{००}
	पीए	3	2	1	33 ^{३३}
	एएओ	1	0	1	100 ^{००}
	लेखाकार	1	1	0	0 ^{००}
	कनिष्ठ लेखाकार	7	1	6	85 ^{७१}
	सहायक अभियंता	1	1	0	0 ^{००}
	कनिष्ठ अभियंता	8	8	0	0 ^{००}
	वरिष्ठ लिपिक	1	1	0	0 ^{००}
	कनिष्ठ लिपिक	15	12	3	20 ^{००}
	बीआरसीएफ	7	3	4	57 ^{१४}
	सदर्भ व्यक्ति	21	10	11	52 ^{३८}
	सीआरसीएफ	83	59	24	28 ^{९२}
	मुख्य रसोइया	7	7	0	0 ^{००}
	सहायक रसोइया	8	6	2	25 ^{००}
चौकीदार	7	6	1	14 ^{२९}	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7	7	0	0 ^{००}	
योग		182	129	53	
कुल योग		829	620	209	

वेनतबम क्मब - म्मम श्रंसवतम-

श्रंसवतम उंतबी 2009द्ध

शैक्षणिक कार्मिक

विभाग	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तता :
माध्यमिक शिक्षा	प्रधानाचार्य एवं समकक्ष	65	40	25	38 ^{४६}
	प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष	148	34	114	77 ^{०३}
	व्याख्याता एवं समकक्ष	316	116	200	63 ^{२९}
	वरिष्ठ अध्यापक	733	545	188	25 ^{६५}

	शा.शि II	32	19	13	40 ^प 63
	अध्यापक III	250	203	47	18 ^प 80
	शाशि III	71	65	6	8 ^प 45
योग		1615	1022	593	
प्राथमिक शिक्षा	वरिष्ठ अध्यापक (प्र.अ)	865	734	131	15 ^प 14
	अध्यापक III	5541	3711	1830	33 ^प 03
	शाशि III	257	122	135	52 ^प 53
योग		6663	4567	2096	
सर्व शिक्षा	वार्डनर कम शिक्षिका	21	21	0	0 ^प 00
	प्रतिनियुक्ति स्टाफ	10	2	8	80 ^प 00
योग		31	23	8	
महायोग		8309	5612	2697	

वर्ष 2009-10 का आंकड़ा - मसम श्रंसवतम - 1

श्रंसवतम उंतबी 2009-10

2.5.4 जिले में महाविद्यालय स्तर के शिक्षण संस्थान -

महाविद्यालय स्तर के शिक्षण संस्थान

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर

राजकीय महिला महाविद्यालय जालोर

जी के गोवाणी राजकीय महाविद्यालय भीनमाल

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान

औद्योगिक शिक्षण संस्थान, जालोर

औद्योगिक शिक्षण संस्थान, रानीवाडा

शिक्षक शिक्षण संस्थान

जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान, जालोर

श्री शान्तिनाथ विद्याभारती शिक्षक शिक्षक महाविद्यालय, जालोर

लॉर्ड रिवा गल्स शिक्षक शिक्षक महाविद्यालय, भीनमाल

मुनिश्री कमलविजय मसा शिक्षक शिक्षक महाविद्यालय, भीनमाल

यु.के.एस.देवल शिक्षक शिक्षक महाविद्यालय, भीनमाल

सुन्धामाता महिला शिक्षक शिक्षक महाविद्यालय, भीनमाल

भगवान महावीर शिक्षक शिक्षक महाविद्यालय, सांचौर

विशेष आवासीय शिक्षा संस्थान

जवाहर नवोदय विधालय जसवन्तपुरा

डा. भीमराव अम्बेडकर बालिका आवासीय विधालय भैसवाडा (आहोर)

निष्क्रमणीय पुपालक राजकीय उ.मा. आवासीय विधालय हरियाली (आहोर)

महिला शिक्षण विहार जालोर

केजीबी विधालय :- 07

अन्य शिक्षण संस्थान

नर्सिंग शिक्षण संस्थान, जालोर

2.6 शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत पक्ष

2.6.1 शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता -

जालोर जिले में प्रति दस हजार आबादी पर उपलब्ध राजकीय प्राथमिक विधालय 10, उच्च प्राथमिक विधालय 7, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विधालय 1.5 है। जिले में वर्तमान विद्यालयों की संख्या तालिका संख्या 2.11 के अनुसार है।

तालिका संख्या 2.11

विद्यालय की संख्या

विद्यालय	राजकीय	निजी	योग
प्राथमिक विद्यालय	1364	262	1626
उच्च प्राथमिक विद्यालय	746	300	1046
माध्यमिक विद्यालय	173	83	256
उच्च माध्यमिक विद्यालय	66	31	97
योग	2349	676	3025

सर्वोत्तम कर्म - मसम श्रंसवतम द्व

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान में 3025 विद्यालय है, जिसमें राजकीय विद्यालयों की संख्या अधिक है। अतः इस जिले में राजकीय विद्यालय के प्रति जनता की रुझान अधिक है। रा.प्रा.एवं रा.उ.प्रा.विधालयो की स्थापना में पिछले दशक में सराहनीय वृद्धि हुई

तालिका संख्या : 2.12

वर्ष	विधालयो की संख्या			
	प्राथ.विधा.	उच्चप्राथ.वि	माध्य.वि	उच्च माध्यवि
2001	926	309	84	33
2009	1364	746	173	66

सर्वोत्तम कर्म - मसम श्रंसवतम द्व

(3) प्रा.एवं उ.प्रा.विधालयो के स्तर पर निजी सहभागिता में सराहनीय वृद्धि हुई।

तालिका संख्या : 2.13

वर्ष	विद्यालयों की संख्या			
	प्राथ.विधा.	उच्चप्राथ.वि	माध्य.वि	उच्च माध्यवि
2001	57	32	9	0
2009	262	300	83	31

वनतबम क्मब - म्म

श्रंसवतम द्द

2.6.2 िाक्षा के क्षेत्र में कमजोर पक्ष

(1) साक्षरता दर राष्ट्रीय एवं राज्य साक्षरता दर की तुलना में बहुत कम है। (वर्ष 2001)

तालिका संख्या : 2.14

	महिला	पुरुष	योग
भारत	53.7	75.3	64.8
राजस्थान	43.85	75.70	60.40
जालोर	27.80	64.72	46.49
अन्तर राष्ट्रीय	-25.90	-10.58	-18.31
अन्तर राज्य	-16.05	-10.98	-13.92

वनतबम क्मब - म्म श्रंसवतम द्द

(2) पर्याप्त विद्यालयों की उपलब्धता का अभाव

(3) राजकीय विद्यालयों में िाक्षकों की कमी

(5) छात्राओं के नामांकन में भी ब्लॉकवार अत्यधिक भिन्नता है - प्राथमिक, उच्च

प्राथमिक स्तर पर प्रति हजार नामांकन पर छात्राओं का नामांकन ब्लॉक सांचौर का 824.25 (प्रथम) है जबकि भीनमाल का 617.14 (नौ वां स्थान है)

(6) जिले में महाविद्यालय स्तर की िाक्षा के लिए केवल तीन राजकीय महाविद्यालय हैं, जो जनसंख्या की दृष्टि से अपर्याप्त हैं।

(7) जिले में व्यावसायिक िाक्षा के संस्थान भी अपर्याप्त हैं। यहां इंजीनियरिंग एवं पोलिटेक्निक कॉलेज पूरे जिले में एक भी नहीं हैं।

(8) छात्राओं में कक्षा 1 में प्रवे ि लेने वाली प्रत्येक 100 छात्राओं पर कक्षा 5 तक 59.5 प्रति ित कक्षा 10 तक 8.7 प्रति ित तथा कक्षा 12 तक 2.1 प्रति ित छात्राएं ही पहुंच पाती हैं। शेष छात्राएं बीच में ही अपना अध्ययन छोड़ देती हैं।

(9) छात्रों में कक्षा 1 में प्रवे ि लेने वाले प्रत्येक 100 छात्रों पर कक्षा 5 तक 61.8 प्रति ित , कक्षा 10 तक 19.8 प्रति ित तथा कक्षा 12 तक 5.0 प्रति ित छात्र ही पहुंच पाते हैं। शेष छात्र बीच में ही अपना अध्ययन छोड़ देते हैं।

2.7 भावी रणनीति संभावनाएं वर्ष 2015 तक

(1) वर्ष 2015 तक संभावित साक्षरता दर पुरुष-85 प्रति ित एवं महिला-58 प्रति ित

योग-71.5 प्रति आत

- (2) वर्ष 2015 तक 6 से 14 तक के सभी बालक-बालिकाओं को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कम से कम 500 प्राथमिक एवं 250 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता।
- (3) प्राथमिक शिक्षा प्राप्त बालक-बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु 150 माध्यमिक एवं 100 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना अपेक्षित है।
- (4) बालक - बालिकाओं के ड्रॉप आउट कम करने के लिए प्रति 5 कि.मी.की परिधि में या ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करनी अपेक्षित है।
- (5) प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक वर्ष 2015 तक लगभग तीन हजार महिला -पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन अपेक्षित रहेगा।
- (6) प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालयों पर कक्षा 12 तक के अध्ययन हेतु बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना।
- (7) प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) की स्थापना।
- (8) जिले में कम से कम चार इंजीनियरिंग एवं पोलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना।
- (9) जिले में एक केन्द्रिय विद्यालय की स्थापना।
- (10) 2015 तक विद्यालयों की संभावित उपलब्धता।

तालिका संख्या : 2.15

2015 तक विद्यालयों की संभावित उपलब्धता (10 हजार की आबादी पर) विद्यालय के प्रकार	विद्यालय की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	15
उच्च प्राथमिक विद्यालय	10
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक	5

वर्तमान कम्प्यूटर - मसम श्रंसवतम उत्तरी

2009-10



1.0 परिचय :

स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जब से आर्थिक विकास ने गति पकड़ी है, स्वास्थ्य तंत्र के विकास में भी तीव्रता आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 191 सदस्य राष्ट्रों में भारतीय स्वास्थ्य तंत्र का 118 वा स्थान है। सन् 1999 की मानव विकास रिपोर्ट में जालोर का 29 वा स्थान था। वर्तमान में भी 29 वा स्थान ही है। स्वास्थ्य स्तर के मूल्यांकन कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होती है जैसे जीवन सामर्थ्य, मां और बच्चे का कपोषण स्तर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य तंत्र की भूमिका इत्यादि ।

1.1 जालोर का जनसांख्यिकीय परिदृश्य –

प्रशासनिक दृष्टि से जालोर जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर कार्यालय तथा विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालय स्थित है। जिले को पांच विधान सभा क्षेत्र एवं उन्ही को पांच उपखण्डों जालोर, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, सांचौर में विभक्त किया गया है। राजस्व प्रशासन के लिए जिले को सात तहसीलों जालोर, भीनमाल, रानीवाडा, सांचौर, सायला, बागौडा एवं आहोर तथा सात विकास खण्डों में अर्थात् जालोर, भीनमाल, आहोर, सायला, रानीवाडा, जसवंतपुरा व सांचौर में विभाजित कर सात पंचायत समिति कार्यालय विकास अधिकारी के नाम से स्थापित किये गये। जिले में तीन नगर पालिका क्षेत्र जालोर, भीनमाल एवं सांचौर हैं।

1.2 जिले की ब्लॉकवार जनसंख्या

जिले में 7 तहसील, 7 पंचायत समिति, 3 नगरपालिका, 264 ग्राम पंचायत और 790 गाँव हैं। उपरोक्त तालिका से जालोर का जनसांख्यिकीय, जिला संबंधी सूचनायें, हाउस होल्ड स्टेट्स, स्वास्थ्य स्तर संबंधी सूचनायें प्रदर्शित है (जनसंख्या गणना 2001)।

जनसंख्या(लाखों में)–	1,449
दसकीय वृद्धि दर (1991–2001)–	26.8
लिंगानुपात –	964
शहरी जनसंख्या प्रतिशत–	7.6
अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत–	18.0
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत–	8.8
महिला साक्षरता दर (सात वर्ष से अधिक)–	27.80
पुरुष साक्षरता दर (सात वर्ष से अधिक)–	64.72

(स्रोत: डी.एल.एच-3, 2007-08, जनगणना 2001)

1.3 आयु-वितरण:

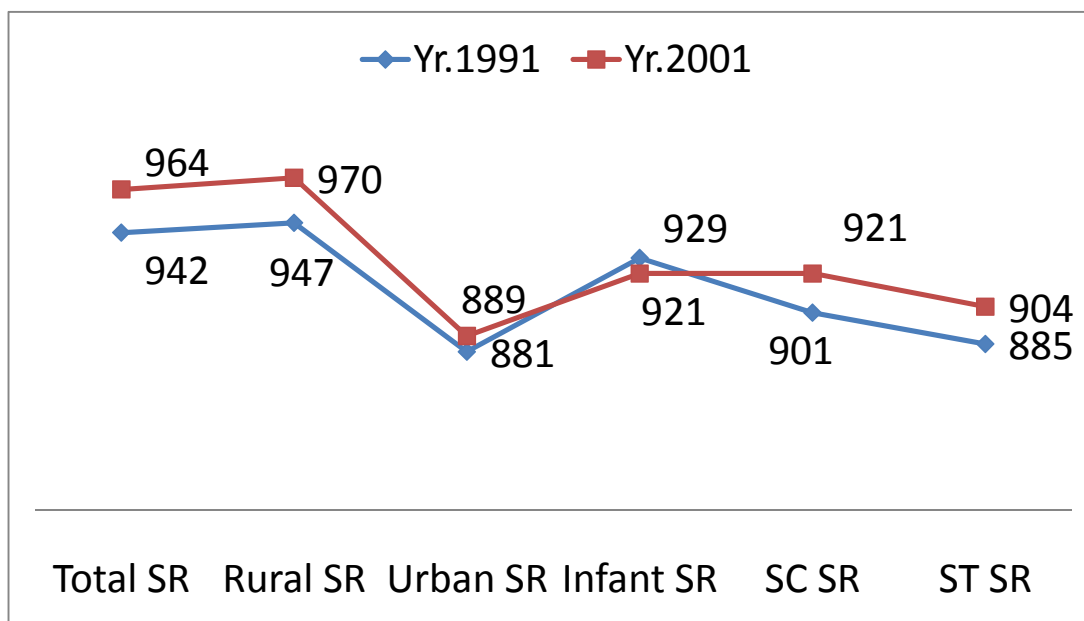
जिले में भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार 0 से 4 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या 2,12,461, 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या 4,21,813 एवं 15 से 69 वर्ष आयु वर्ग जनसंख्या 7,11,548 और 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या 103,118 थी (स्रोत: भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार)

1.4 जनसंख्या घनत्व एवं क्षेत्रफल

जनसंख्या 2001 के अनुसार जालोर का क्षेत्रफल 10640 वर्ग किलोमीटर हैं। एवं जनसंख्या घनत्व 136 प्रति वर्ग किलोमीटर है। (स्रोत: भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार)

1.4 लिंगानुपात:

“वनतबमरु च्चचनसंजपवदरु 2001



चित्र-1.4.1 लिंगानुपात

जिले में भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार (संलग्नक-7) कुल लिंगानुपात 1991 में 942 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 964 हो गया। इससे स्पष्ट है कि लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। ग्रामीण लिंगानुपात 1991 में 947 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 970 हो गया, शहरी लिंगानुपात 1991 में 881 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 889 हो गया। नवजात शिशु लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष) 1991 में 929 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 921 हो गया। इससे स्पष्ट है कि नवजात शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 1991 में 901 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 921 हो गया, एवं अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 1991 में 885 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 904 हो गया। 1991 में महिला कार्य सहभागिता दर 31.60 थी जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 46.09 हो गयी। इससे स्पष्ट है कि महिला सहभागिता दर में वृद्धि हुई है। जिले में विवाह की औसत आयु जनगणना 2001 के अनुसार भी 18.30 वर्ष है। जो कि संतोषजनक है।

1.5 जन्म एवं मृत्यु का स्तर:

शताब्दी विकास लक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिशु मृत्यु दर की स्थिति राजस्थान के सन्दर्भ में अधिक विकट है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व गुणवत्ता की प्राप्ति को इस सूचकांक के माध्यम से आंका जा सकता है। शिशु मृत्यु दर एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है जिस पर अधिकारिक आंकड़ों की उपलब्धता का भी अभाव है। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर गत दो दशक में स्थिर होने के साथ-साथ कमी की ओर अग्रसर है। जिले में शिशु एवं बाल मृत्यु दर के प्राथमिक आंकड़ों का अभाव है। यहां पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, मई 2008 के अनुसार जालोर की बाल एवं शिशु मृत्यु दर के द्वितीयक आंकड़ों का विवरण निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत है जो की चिन्ताजनक हैं

सारणी- 1.5.1 राजस्थान व भारत, जालोर शिशु मृत्यु दर 2001

	कुल	पुरुष	स्त्री
भारत	54	54	53
राजस्थान	79	78	81
जालोर	88	84	92

(स्रोत: पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, मई 2008)

सारणी-1.5.2 भारत, राजस्थान व जालोर, बाल मृत्यु दर 2001

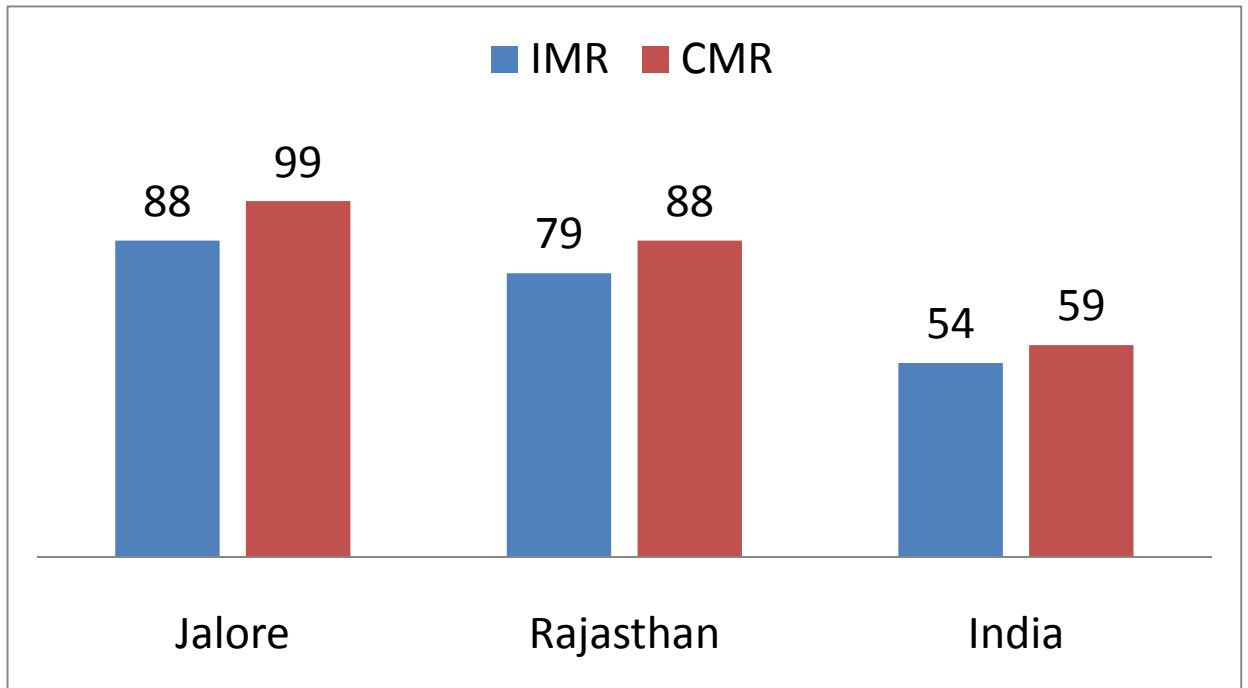
	कुल	पुरुष	स्त्री
भारत	59	58	61
राजस्थान	88	85	92
जालोर	99	94	104

(स्रोत: पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, मई 2008)

सारणी-1.5.3 जालोर कुल शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर

वर्ष	पुंरुष	बुडुत
1991	92	129
2001	88	99

(स्रोत: पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, मई 2008)



चित्र-1.5.1 तुलनात्मक आई.एम.आर., सी.एम.आर.

(स्रोत: पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, मई 2008)

2. जिले में स्वास्थ्य प्रणाली

2.1 ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र

अल्मा आटा के विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन (वर्ष 2000) में "सभी के लिए स्वास्थ्य" में "त्रिस्तरीय स्वास्थ्य तंत्र" स्वीकार किया गया, जिसको भारत में भी लागू किया गया। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य तंत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अन्तर्गत अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जैसे महामारी, मलेरिया, अन्धता निवारण, टी.बी. नियंत्रण, कुष्ठ निवारण, पोलियो निवारण, यॉस निवारण, स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम इत्यादि। स्वास्थ्य विभाग सामाजिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निरन्तर स्टाफ की भर्ती व रोगों की रोकथाम के लिए कार्य कर रहा है। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य तंत्र की संरचना

उप स्वास्थ्य केन्द्र (एस.सी.)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)

2.1.1 उप स्वास्थ्य केन्द्र

उपस्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना स्वास्थ्य मापदण्डों के अनुसार प्लेन क्षेत्र में 5000 की आबादी पर की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों एवं कठिन क्षेत्रों में 3000 की आबादी पर एक उपस्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली में उपकेन्द्र में समाज का प्रथम सम्पर्क बिन्दु होता है। प्रत्येक उपकेन्द्र पर एक प्रसाविका एवं एक पुरुष स्वास्थ्य अभिकता होता है। एक महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक छः उपकेन्द्रों का पर्यवेक्षण करती है। उपकेन्द्र के अंदर आधारभूत दवाईयों की व्यवस्था होती है और स्वास्थ्य संबंधी छोटी बिमारियां के उपचार की व्यवस्था होती है जो कि पुरुष, महिला एवं बच्चों से संबंधित होती है। जालोर में 366 उपस्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में संचालित है। (स्रोत:—सी.एम.एच.ओ., जालोर, मार्च 2009)

2.1.2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एक गांव के समाज व चिकित्सा अधिकारी का प्रथम सम्पर्क बिन्दु होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना स्वास्थ्य मापदण्डों के अनुसार 30000 की आबादी पर की जाती है। पहाडी क्षेत्रों व कठिन क्षेत्रों में 20000 की आबादी पर स्थापना की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बिमारियों के रोकथाम एवं उपचार की व्यवस्था होती है। और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक चिकित्सा अधिकारी एवं 14 पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था होती है। यह छः उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर एक रैफरल इकाई के रूप में कार्य करती है। इसमें रोगी के लिए चार से छः शैय्याओं की व्यवस्था होती है। जालोर जिले के अंतर्गत वर्तमान में 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। जिले में वर्तमान में चौदह 24*7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है जहां 24 घण्टे सहायता सेवाओं की उपलब्धता है। (स्रोत:—सी.एम.एच.ओ., जालोर, मार्च 2009)

2.1.3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना स्वास्थ्य मापदण्डों के अनुसार प्लेन क्षेत्र में 120000 की आबादी पर की जाती है। पहाडी एवं कठिन क्षेत्रों में 80000 की आबादी पर स्थापना की जाती है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 4 विशेष चिकित्सकों की व्यवस्था होती है जैसे शल्य चिकित्सक, फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ इत्यादी। इसके अलावा 21 अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था होती है। इसमें अंतरंग 30 शैय्याओं, एक ऑपरेशन थियेटर, एक एक्स रे कक्ष, एक प्रसव कक्ष एवं एक प्रयोगशाला होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिले में चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रैफरल इकाई की तरह कार्य करती है। जालोर में वर्तमान में आठ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। (स्रोत:—सी.एम.एच.ओ., जालोर, मार्च 2009)

2.2 जिले में स्वास्थ्य संस्थाएँ

2.2.1 ऐलोपैथिक संस्थाएँ

जिला स्तर पर वर्तमान में 427 स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है जिनमें जालोर सामान्य चिकित्सालय एक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 8 जिनमें दो सांचौर में, एक-एक जालोर, जसवंतपुरा, आहोर, भीनमाल, रानीवाडा, सायला; 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 366 उपस्वास्थ्य केन्द्र संचालित है।

सारणी-2.2.1.1 जालोर जिले में स्वीकृत एलोपैथिक स्वास्थ्य संस्थायें

ब्लॉक	कुल स्वास्थ्य संस्थायें	प्रा.स्वा.केन्द्र	सामु.स्वा.केन्द्र	उपकेन्द्र
आहोर	59	8	1	50
रानीवाडा	50	6	1	43
भीनमाल	58	6	1	51
जसवन्तपुरा	45	7	1	37
सांचौर	103	12	2	89
सायला	65	7	1	57
जालोर	46	6	1	39
योग	426	52	8	366

(स्रोत:-सी.एम.एच.ओ., जालोर, मार्च 2009)

2.2.2 आयुर्वेदिक संस्थाएँ

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि आयुर्वेदिक व स्वीकृत शैयाएँ की संख्या वर्ष 2002 से वर्ष 2008 तक स्थिर हैं।

सारणी-2.2.2.1 आयुर्वेद संस्थाओं में स्वीकृत शैयाएँ

वर्ष	आयुर्वेद संस्थाओं की संख्या			स्वीकृत शैयाएँ		
	अ-श्रेणी	ब-श्रेणी	होम्यो	अ-श्रेणी	ब-श्रेणी	होम्यो
2002	2	67	3	20	5	.
2003	2	67	3	20	5	.
2004	2	67	3	20	5	.
2005	2	68	3	20	5	.
2006	2	68	3	20	5	.
2007	2	68	3	20	5	.
2008	2	68	4	20	5	.

(स्रोत:-जिला आयुर्वेद अधिकारी, जालोर, मार्च 2009)

निम्न सारणी के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अ श्रेणी आयुर्वेद संस्थाओं में आयुर्वेद चिकित्सकों के 56: पद पूर्णतया खाली हैं जो कि चिन्ताजनक हैं।

सारणी-2.2.2.2 आयुर्वेद चिकित्सक स्वीकृत/रिक्त		
पद	स्वीकृत	रिक्त
अ- श्रेणी		
आयुर्वेद चिकित्सक	3	.
ब- श्रेणी		
आयुर्वेद चिकित्सक	68	30
होम्योपैथिक चिकित्सक	4	3

(स्रोत:-जिला आयुर्वेद अधिकारी, जालोर, मार्च 2009)

2.3 आधारभूत ढांचागत अंतराल

राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (आर.एच.एस.डी.पी.) को 2011 तक बढ़ाया है। इस कार्ययोजना में चयनित चिकित्सा संस्थानों को दवाईयां, हास्पिटल सामग्री, उपकरण उपलब्ध करवाना, आधारभूत संरचनाओं का सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं विस्तार करवाना, स्टाफ को नवीनतम तकनीक में प्रशिक्षित करना तथा कचरा निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था कर गुणवत्ता में सुधार करना प्रमुख कार्य है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध आकड़ों के अनुसार आधारभूत ढांचागत अंतराल में स्थिति संतोषजनक हैं।

2.4 जन स्वास्थ्य सेवाओं का उपभोग

सारणी-2.4.1 खण्ड में चिकित्सा सेवाओं का उपभोग- प्रति शैया रोगियों की सं. 2007.08

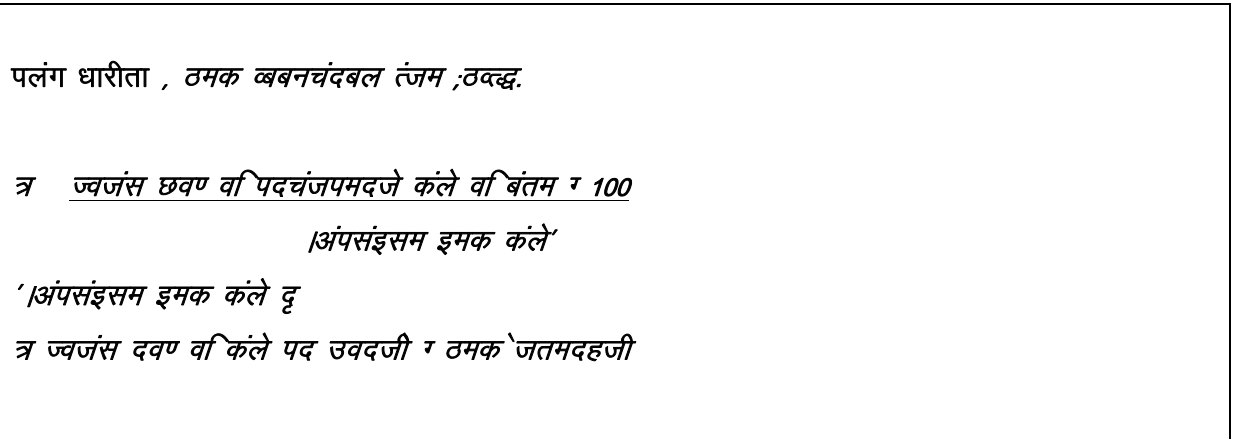
ब्लॉक	कुल शैयारें	कुल बहिरंग रोगी	कुल अन्तरंग रोगी	कुल रोगी	रोगी प्रति शैया
आहोर	92	143607	18161	161768	1758
भीनमाल	129	123371	11427	134798	1045
जलोर रु	224	314526	24172	338698	1512
जसवन्तपुरा	76	12488	2697	15185	200
रानीवाडा	70	28898	4143	33041	472
सांचोर	162	51377	5594	56971	352
सायला	80	39899	4674	44573	557

' वदसल बढ कर्ज पे नेमकए वनतबमरु त्वैक्चर बड-भ्व शंसवतम रुर्कजं वळिळमदमतंस भ्वेचपजंसए शंसवतम बपजल पे पदबसनकमक

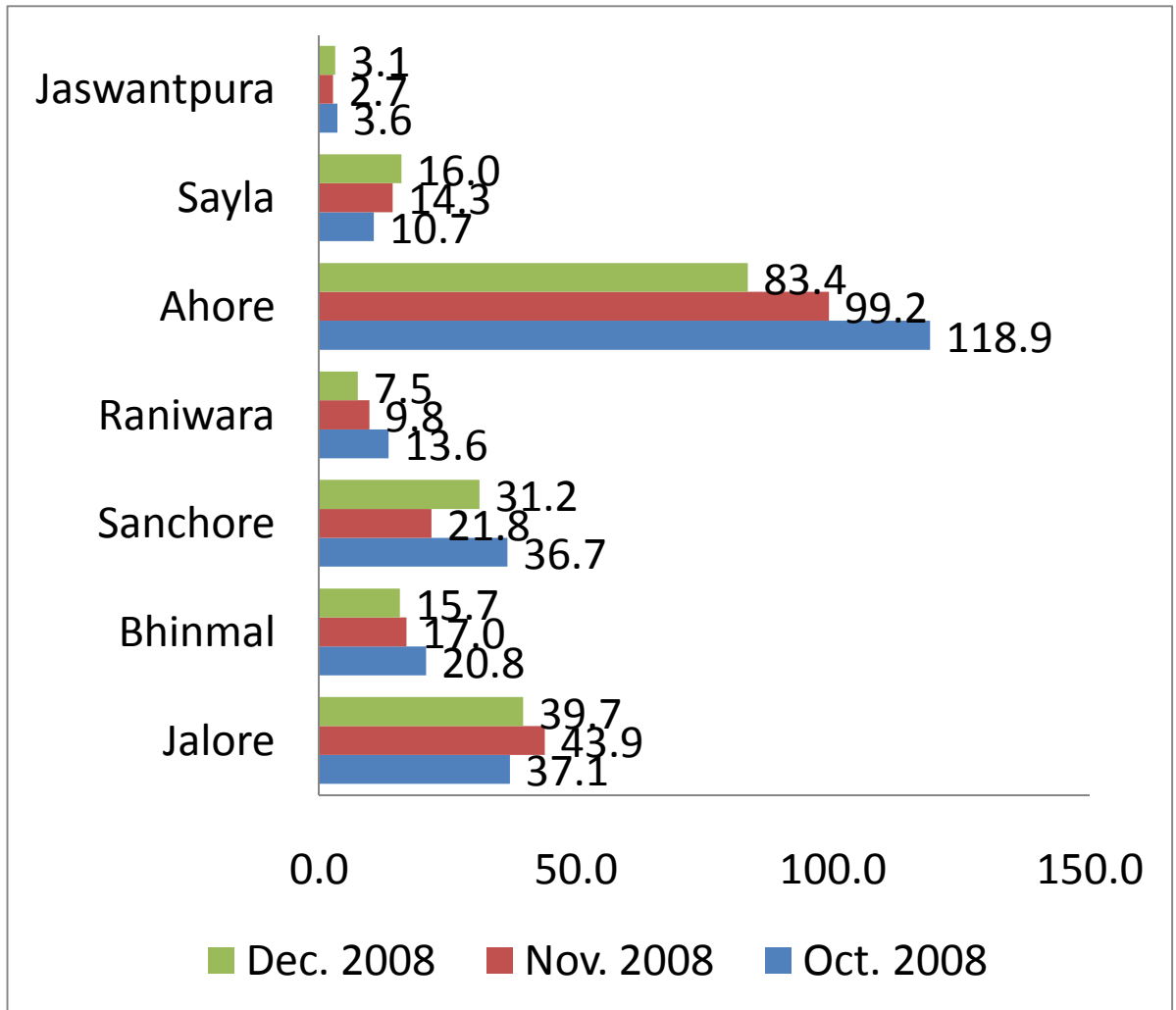
सारणी-2.4.2 प्रति चिकित्सा अधिकारी जनसंख्या

ब्लॉक	जनसंख्या 2001	चि.अधि.	प्रति चि.अधि. जनसंख्या
टाहोर	177312	8	25339
रानीवाडा	163349	6	31125
भीनमाल	224031	6	42688
जसवन्तपुरा	128410	7	20972
सांचौर	368004	12	35060
सायला	211147	7	34485
जलोर	176687	6	33664
योग	1448940	52	223333

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हैं कि वर्ष 2001 के जनसंख्या आकड़ों के अनुसार भीनमाल में सर्वाधिक जनसंख्या प्रति हजार चिकित्सा अधिकारी दर्ज कि गई। यह स्वास्थ्य संस्थाओं पर अतिरिक्त कार्यप्रभार को दर्शाता है।



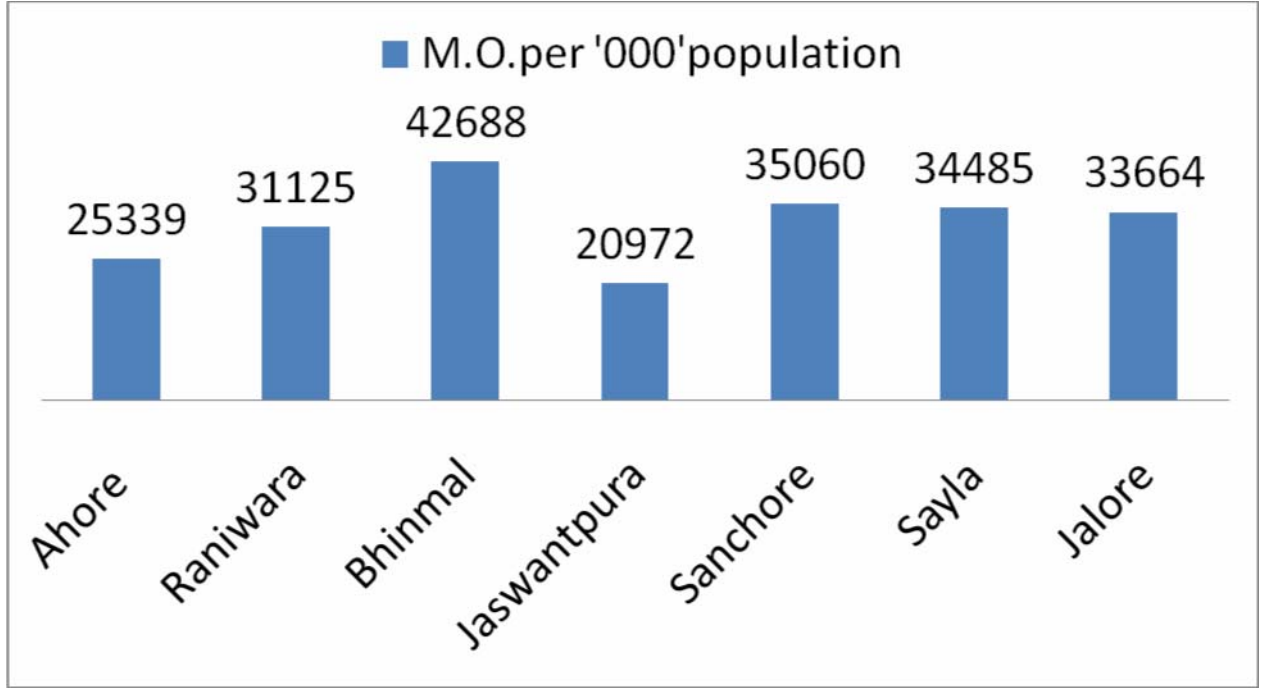
चित्र-2.4.1 पलंग धारीता



चित्र-2.4.2 खण्डवार पलंगधारित

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि वर्ष 2008 में आहोर ब्लॉक में सर्वाधिक पलंग धारीता सर्वाधिक रही । यह चिकित्सा संस्थाओ कि कार्य कुशलता दर्शाता है ।

चिकित्सा अधिकारीरू जनसंख्या (अनुपात). 1रू13932



चित्र-2.4.3 प्रति चिकित्सक जनसंख्या

सारणी-2.4.2 खण्डवार विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी

ब्लॉक	विशेषज्ञता					
	फिजीशियन	स्त्री रोग	निश्चेतन	शल्य	पैथोलोजिस्ट	शिशु
टाहोर	1	1	0	1	0	1
भीनमाल	0	1	0	1	0	0
जलोर	3	2	0	2	1	2
जसवन्तपुरा	0	0	0	0	0	0
रानीवाडा	0	0	0	0	0	0
संचोर	1	0	1	0	0	1
सायला	1	0	0	0	0	0
ज्वजंस	6	4	3	5	1	4

सारणी-2.4.4 फर्स्ट रेफरल ईकाइयां

छंउम वथिन्	भनउंद त्मेवनतबमे				ठै-				छमू ठवतद ब्वतदमत
	ळलदंम	चमकपं	नतह	दमेण	कळ	ठै-	ठै-	ठै- त्ववउ	
	ण	ण	ण		मज	ज्तंहण	स्पबमदेम		
ठपदउंस	ल	ल	ल	ल	ल	ल	चचसपम	न्दकमत	ल
वीवतम	ल	ल	ल	छ	ल	ल	चचसपम	ब्वउचसमजमक	ल
भंकमबीं	छ	छ	छ	छ	ल	ल	चचसपम	ब्वउचसमजमक	छ
श्रुंदजचनतं	छ	छ	छ	छ	छ	ल	चचसपम	न्दकमत	छ
तंदपूंतं	छ	छ	छ	छ	छ	ल	चचसपम	न्दकमत	छ
दबीवतम	छ	ल	छ	ल	छ	ल	चचसपम	ब्वउचसमजमक	छ
लसं	छ	छ	छ	छ	छ	ल	चचसपम	न्दकमत	छ
पलदं	छ	छ	छ	छ	ल	ल	चचसपम	न्दकमत	छ

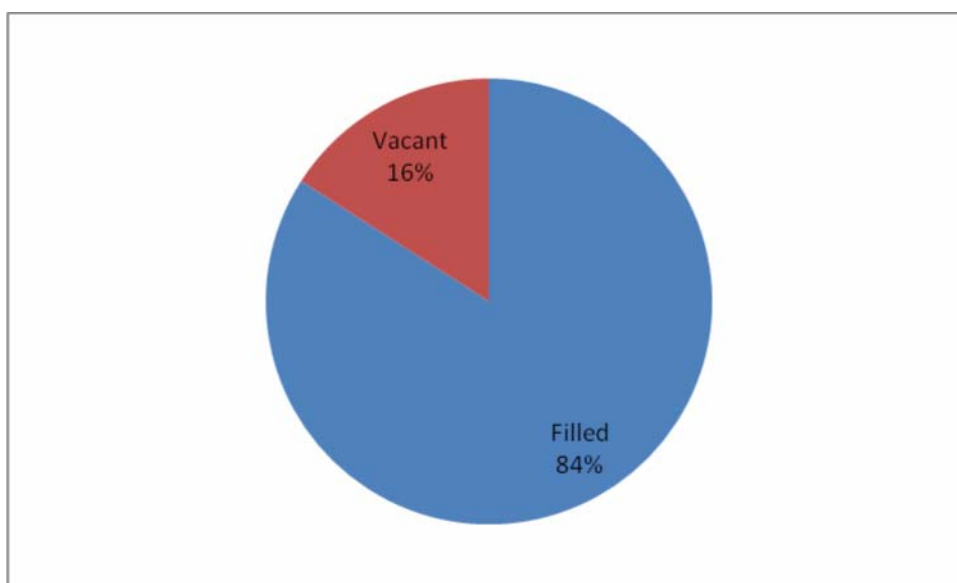
वनतबमरू क्चडन् ए श्रंसवतम

2.5 कार्मिक/मानव संसाधन

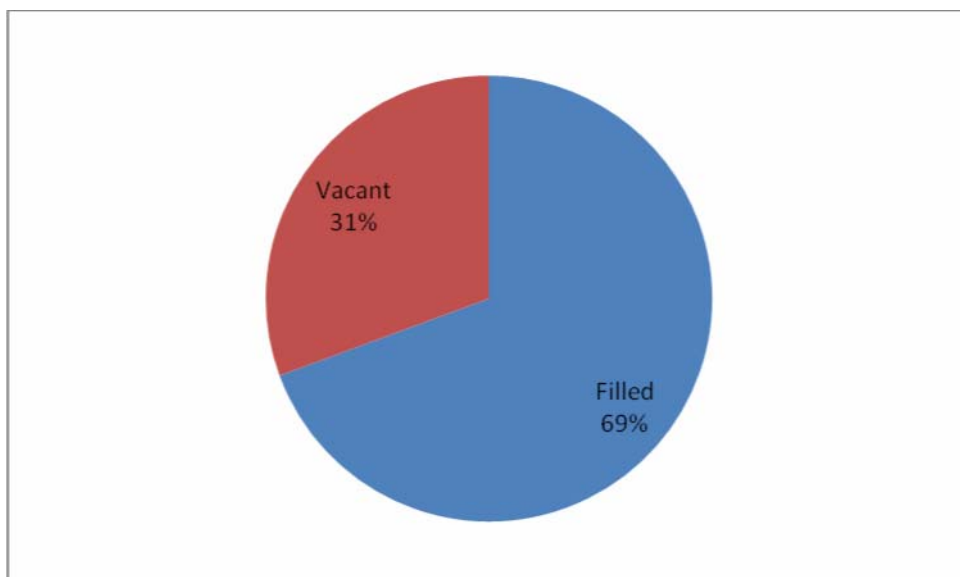
मानक व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए अपरिहार्य है। जिले में विेषज्ञ सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता है। प्रजनन एवं िाु स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक स्त्री रोग विेषज्ञ, बाल रोग विेषज्ञ तथा निश्चेतना रोग विेषज्ञ के अधिकांश पद रिक्त है। हालांकि पेरामेडिकल सेवाओं के स्तर पर स्थिति अपेक्षाकृत कम गभीर है।

जालोर में चिकित्सा एवं स्वा. विभाग अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कुल 1634 पद स्वीकृत है। वर्तमान में इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1373 पद भरे हैं तथा 260 रिक्त है। इस प्रकार जिले में 1:13932 अनुपात में राजकीय चिकित्सक उपलब्ध है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जिले में विभिन्न श्रेणी के चिकित्सकों के 15.91 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त है। जालोर में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के 7 पद स्वीकृत हैं जिनमें 5 कार्यरत व 2 रिक्त है। वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों के 7 स्वीकृत पदों में 5 कार्यरत है।

विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के 52: पद रिक्त हैं। इससे लोगो को विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है तथा कार्यरत चिकित्सकों के उपर कार्यभार अधिक होने से सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित है। यह ध्यान देने योग्य है कि पूरे जिले में कुल कार्यरत चिकित्सकों में मात्र 3 ही महिला चिकित्सक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रबन्धकीय दक्षता लाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर 7 ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक व के पद रिक्त है। (स्रोत: संलग्नक-1, सीएमएचओं,जालोर, मार्च 2009)



चित्र-2.5.1 जिले में चिकित्सा में स्वीकृत/रिक्त



चित्र-2.5.2 आयुर्वेद चिकित्सको के रिक्त एवं भरे पद

जिले में कुल कार्यरत चिकित्साधिकारियों में केवल 14.86% महिला चिकित्साधिकारी कार्यरत है, जो कि स्टाफ व्यवस्था में लैंगिक असमानता को दर्शाता है।

3.0 मातृ स्वास्थ्य

3.1 प्रसव पूर्व जांच

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के निर्धारक कारकों में प्रसव पूर्व जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भधारण के प्रथम 3 माह में पंजीकरण कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत 30.0 है जो जिले के प्रतिशत 30.2 से कम है (डी0एच0एच0एस0-3)। ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रसव पूर्व 3 जांच की सेवाएं प्राप्त हुईं का प्रतिशत 30.2 डी0एल0एच0एस0-2 की तुलना में (20.8) बढ़ा हुआ है।

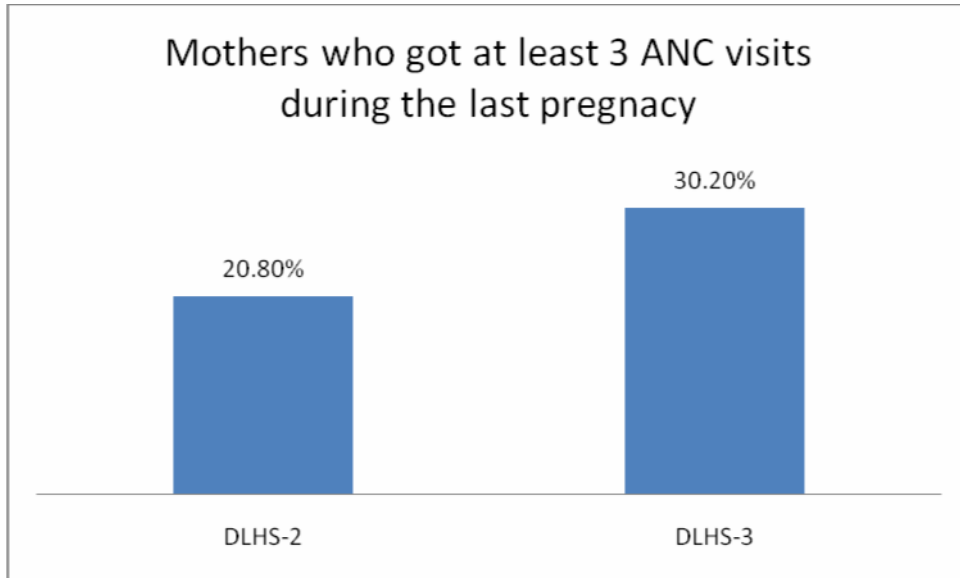


मातृत्व स्वास्थ्य, ;स्रोत: डीएलएचएस फेक्ट शीट 2007–2008

डी.एल.एच.एस –3

डी.एल.एच.एस –2

	कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण
अंतिम गर्भावस्था में कम से कम 3 ए.एन.सी. विजिट करने वाली माताएँ :	30.2	30.0	20.8	19.9
अंतिम जीवित जन्म के समय कम से कम एक टी.टी. इंजेक्शन लगवाने वाली गर्भव्य माताएँ :	62.8	61.9	43.3	41.2
डाक्टर या अन्य स्टाफ के द्वारा करायें गये घरेलू प्रसव का :	18.8	18.6	31.4	31.2
48 घण्टे के अन्दर, अंतिम प्रसव के समय प्रसव पश्चात देखभाल लेने वाली माताओं का :	35.6	34.9	—	—



चित्र- 3.1.2 अंतिम गर्भावस्था में कम से कम 3 ए.एन.सी. विजिट करने वाली माताएँ :

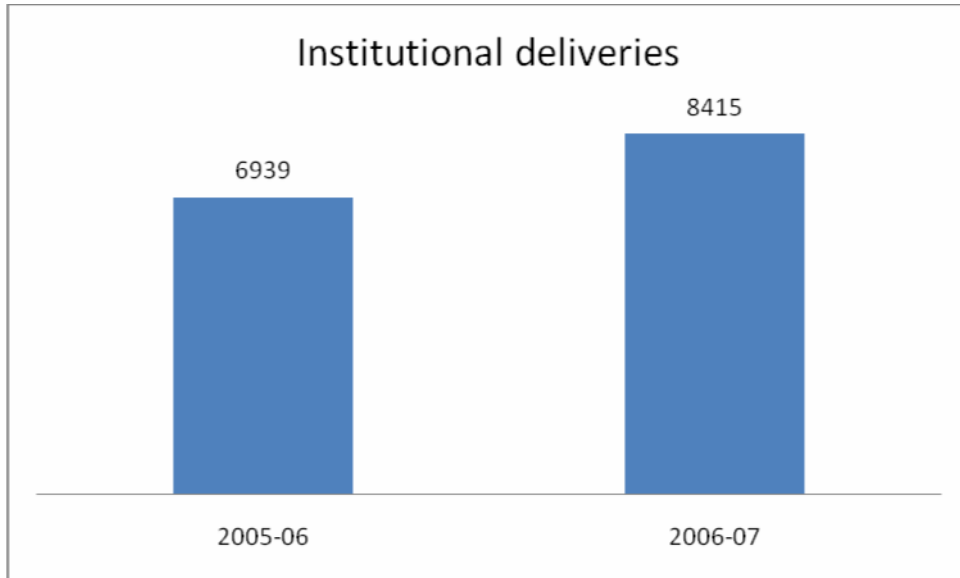
सारणी -3.1.1 आरसीएच-2 में 2011-12 तक लक्ष्य

सूचक	2011-12 तक लक्ष्य
आई.एम.आर	32
एम.एम.आर.	148
टीएफआर	271
सीबीआर	21
सीडीआर	7

स्रोत- आरसीएच-2 [पुदतीउण्हवअण्पदए](#) डंतबीए 2009

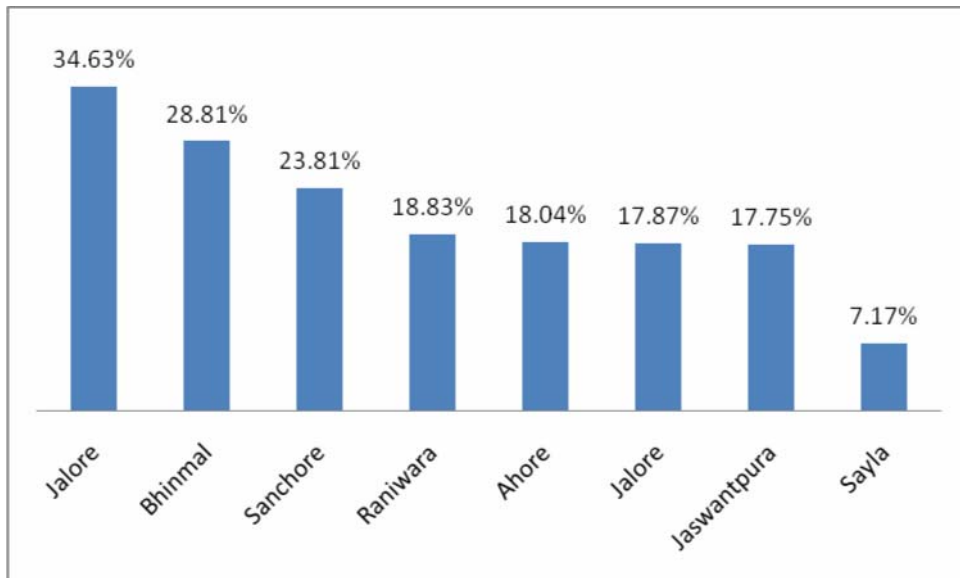
3.2 संस्थागत प्रसव एवं घरेलू प्रसव -

वर्ष 2005 में एन0आर0एच0एम0 के प्रारम्भ व जननी सुरक्षा योजना लागू होने के साथ ही संस्थागत प्रसव में पूरे देश में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। जननी सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व डी0एच0एच0एस0-2 के दौरान संस्थागत जन्म का प्रतिशत 16.4 था जो डी0एच0एच0एस0-3 के समय बढ़ कर 35.1 प्रतिशत दर्ज किया गया। जालोर जिले के चिकित्सा संस्थानों पर वर्ष 2007-08 व 2008-09 के दौरान हुए संस्थागत प्रसव का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जिले में कुल संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है।



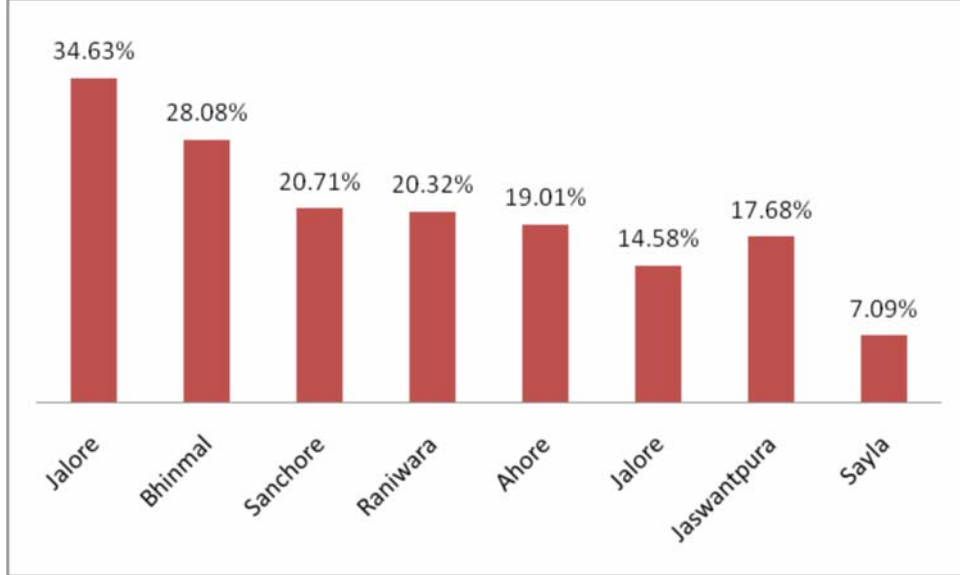
चित्र-3.2.1 खण्डवार संस्थागत प्रसव (स्रोत:-सी.एम.एच.ओ., जालोर, मार्च 2009)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियों को सुचारु क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर भी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है। मिशन का मूल उद्देश्य यौवन एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि लाना है। मिशन के अर्न्तगत जन समुदाय एवं स्वास्थ्य के बीच की कड़ी "आशा सहयोगिनी" प्रेरक रणनीति/प्रतिपूर्ति रणनीति पर नियुक्ति की गई है। वर्तमान में जिले में 490 आशा सहयोगिनी कार्यरत है।



चित्र-3.2.2 खण्डवार संस्थागत प्रसव, जुलाई 2009

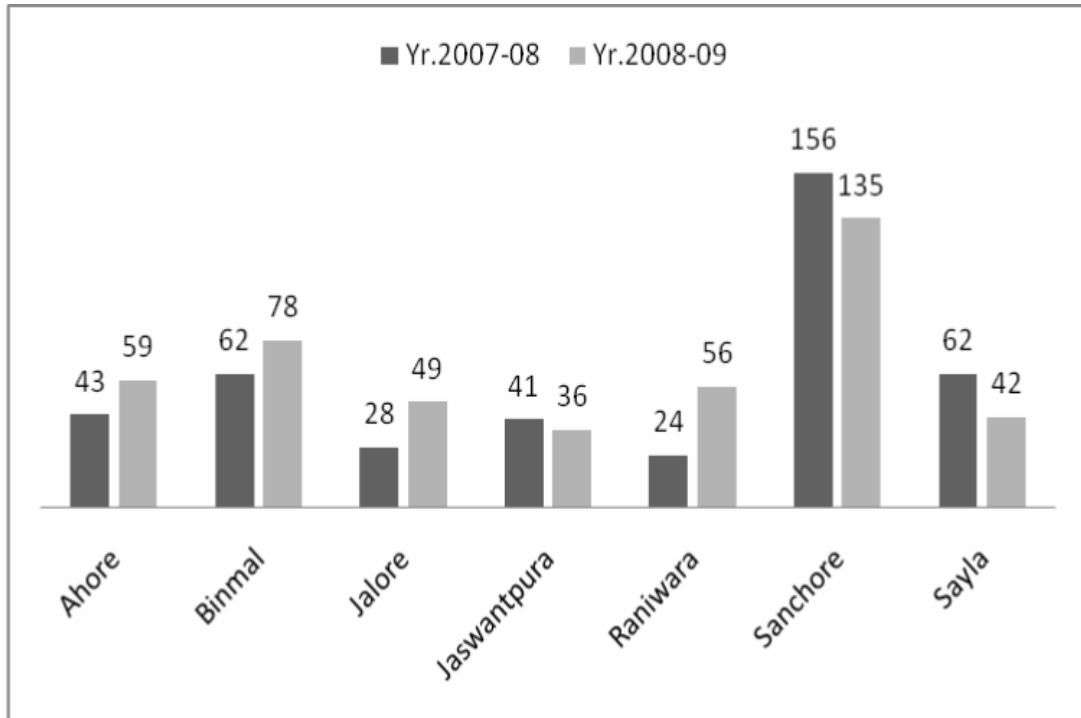
वनतबमरु वचन छत्तुए शंसवतम



चित्र-3.2.3 खण्डवार संस्थागत प्रसव, जुलाई ए 2009 (जननी सुरक्षा योजना)

‘वनतबमरु वड्डन् ए छत्तुए श्रंसवतम

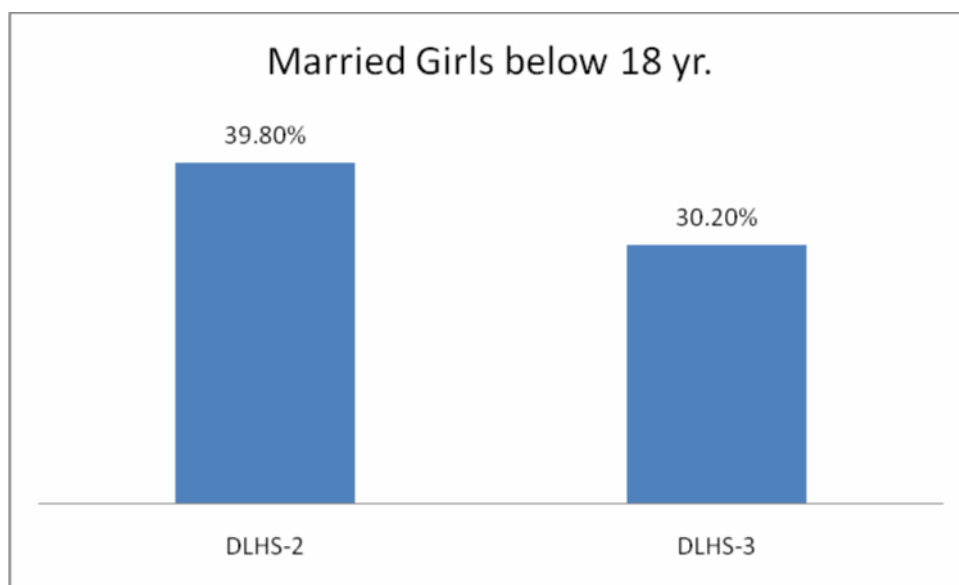
घरेलू प्रसव



चित्र-3.2.3 खण्डवार घरेलू प्रसव (संख्या में)

4.0 बाल विवाह

जिले में बाल विवाह एक प्रचलित सामाजिक समस्या है जो अन्ततः जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे, मातृ मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को बढ़ावा देती है। डीएचएस-3 के अनुसार जिले में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व विवाह करने वाली लड़कियों का कुल प्रतिशत 30.2 है जो कि डीएचएस-2 की तुलना (37.8) में घटा है।



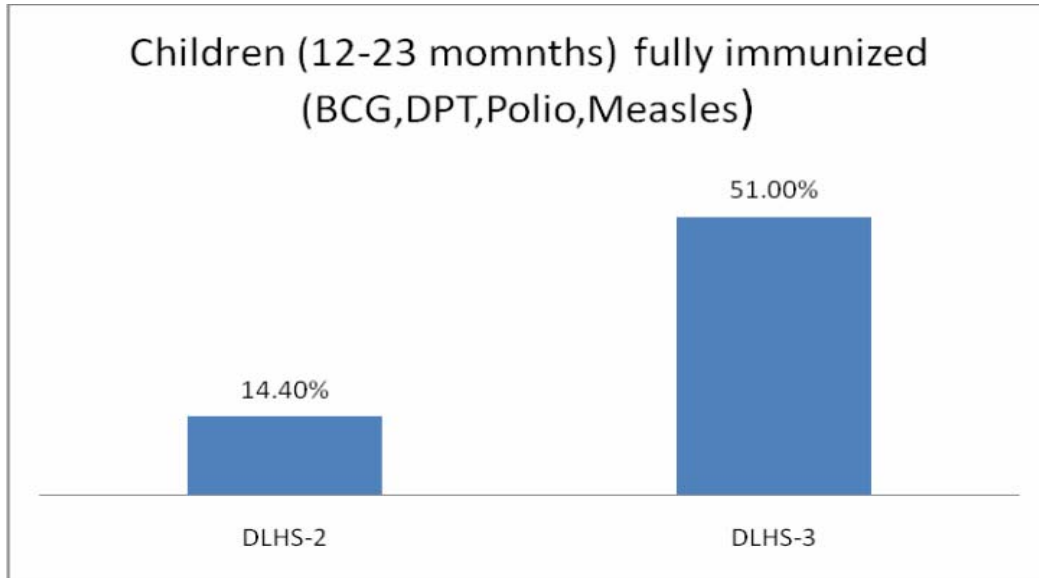
चित्र 4.1—18 वर्ष से कम आयु में विवाहित बालिका :

विवाह एवं फर्टिलिटी, जनवरी, 04 से 2007—08 ;स्रोत: डीएलएचएस फेक्ट शीट 2007—2008

	डी.एल.एच.एस -3		डी.एल.एच.एस -2	
	कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण
18 वर्ष से कम आयु में विवाहित बालिका :	2971	3778	3979	
3 या अधिक बर्थ आर्डर का :	123	118	—	—
2 या 2 से अधिक बर्थ आर्डर वाली महिलाए (आयु 20—24) :	56.8	56.4	—	—

5.0 टीकाकरण

बच्चों को 6 जानलेवा बिमारियों से बचाने के लिए विभाग द्वारा सघन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व डीएलएचएस से प्राप्त आंकड़ों में विरोधाभास देखने को मिलता है। पल्स पोलियों को अभियान के रूप में प्रारम्भ करने के बाद पोलियों खुराक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में महत्वपूर्ण इजाफा हुआ है। हालांकि पोलियों की खुराक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत डीपीटी के टीकों के साथ भी दी जाती है। पोलियों मुक्त देश के निर्माण हेतु इन वंचित बच्चों का कवरेज एक ज्वलन्त मुद्दा है।



चित्र-5.1 पूर्ण टीकाकृत बच्चे, 12-23 माह (ः)



सारणी-5.1 बाल टीकाकरण

बाल टीकाकरण

सूचक	जालोर				राजस्थान			
	डीएलएचएस.2		डीएलएचएस.3		डीएलएचएस.2		डीएलएचएस.3	
	कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण
बच्चों की संख्या (12-23 माह)	4183	3087	3411	2821
पूर्ण टीकाकृत बच्चे, 12-23 माह (ः)	14 ^{७4}	12 ^{७1}	51	48 ^{७9}	23 ^{७9}	18	48 ^{७8}	46 ^{७7}
अप्राप्त टीकाकृत बच्चे, 12-23 माह (ः)	.	.	.	४	29 ^{७6}	33 ^{७7}	14 ^{७3}	15 ^{७4}
3 बार डी.पी.टी.खुराक प्राप्त बच्चे, 12-23 माह (ः)	49 ^{७2}	45 ^{७5}	78 ^{७7}	78 ^{७2}	60	54 ^{७2}	82 ^{७8}	81 ^{७6}
3 बार पोलियो की खुराक प्राप्त बच्चे, 12-23 माह (ः)	21 ^{७9}	19 ^{७2}	60 ^{७1}	58 ^{७8}	35 ^{७2}	29 ^{७6}	63 ^{७9}	62 ^{७6}
मीजल्स वैक्सीन प्राप्त बच्चे, 12-23 माह (ः)	22 ^{७8}	21 ^{७2}	67 ^{७7}	66 ^{७6}	35 ^{७1}	29 ^{७1}	67 ^{७5}	65 ^{७7}
कम से कम 1 विटामिन-ए खुराक प्राप्त बच्चें आयु 9 माह और अधिक	.	.	59 ^{७1}	59 ^{७8}	21 ^{७6}	17 ^{७1}	50 ^{७8}	48 ^{७9}

स्रोत: डीएलएचएस फेक्ट शीट 2007-2008

6.0 बाल रोगों का उपचार

हमारे देश में डायरिया को जल मृत्यु दर के सर्वाधिक प्रभावी कारकों में से एक माना जाता है। डायरिया की स्थिति में ओ0आर0एस0 का घोल देना जल मृत्यु दर कम करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। डीएलएचएस-3 के सर्वेक्षण के समय अंतिम 2 सप्ताह में डायरिया से ग्रसित बच्चों का कुल प्रतिशत जिन्हें जीवन रक्षक घोल (ओ0आर0एस0) प्राप्त हुआ, 19.0 है। अधिकांश स्थितियों में डायरिया से ग्रसित बच्चों को ओ0आर0एस0 की त्वरित उपलब्धता नहीं है। घोल इन्हीं डायरिया ग्रसित बच्चों का कुल प्रतिशत, जिन्हें उपचार

दिया गया, 68.6 है। सर्वेक्षण के समय अंतिम 2 सप्ताह में एक्यूट रेस्पीरेटरी इन्फेक्शन/फीवर (तीव्र श्वसन रोग/बुखार) से पीडीत 87.0 प्रति 1000 बच्चों को ईलाज दिया गया, जों कि संतोषजनक है।



जिले में बाल रोगों का उपचार ;स्रोत: डीएलएचएस फेक्ट शीट 2007-2008

डी.एल.एच.एस -3

डी.एल.एच.एस -2

	कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण
पिछले दो सप्ताह में डायरियाग्रस्त बच्चों	19.0	20.1	17.1	15.2

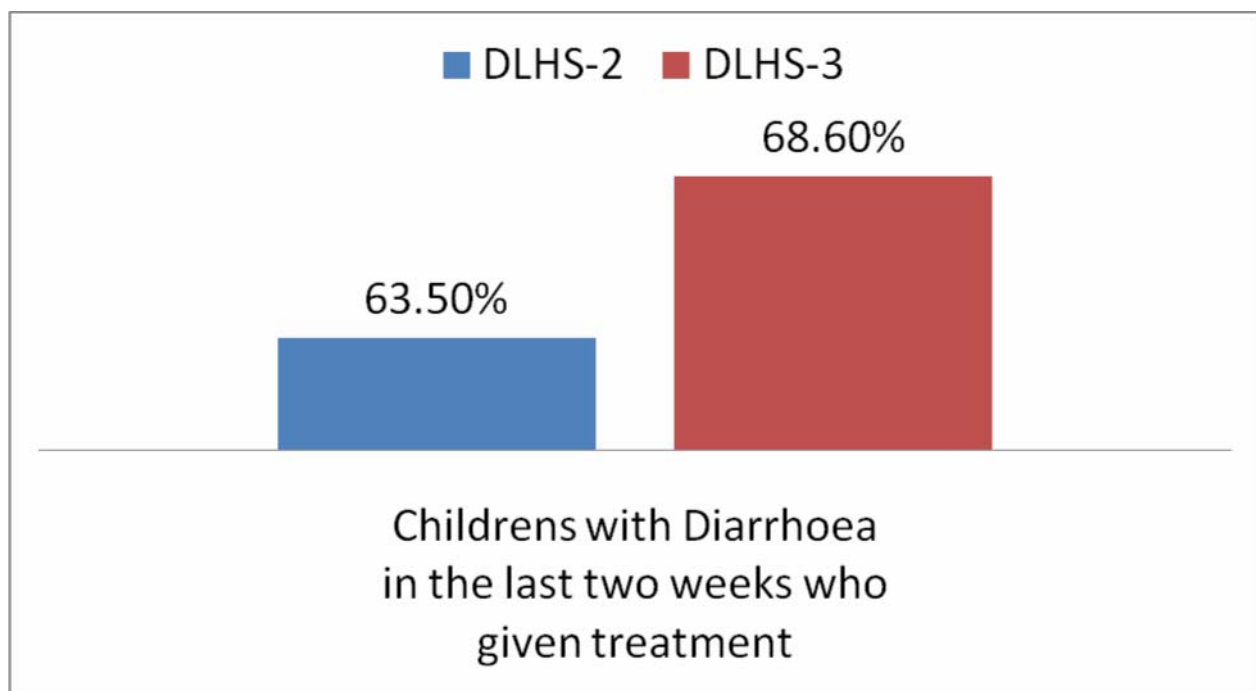
जिन्हाने ओ.आर.एस. घोल पिया :

पिछले दो सप्ताह में डायरियाग्रस्त बच्चें 68.6 66.8 63.5 61.7

जिन्हाने उपचार लिया :

पिछले दो सप्ताह में एक्यूट श्वास संक्रमण 87.0 85.0 — —

ग्रस्त बच्चें जिन्हाने उपचार लिया :



चित्र-6.1 पिछले दो सप्ताह में डायरियाग्रस्त बच्चें जिन्हाने उपचार लिया :

7.0 परिवार कल्याण

राज्य में जालोर जिला परिवार कल्याण के क्षेत्र में गत वर्षों में औसत रहा है। परिवार को सीमित रखने में समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। जिले में पुरुषों का नसबन्दी के प्रति तथा महिलाओं का अस्थाई तरीकों के प्रति कम प्रचलन। पुरुष नसबन्दी मात्र 0.4 प्रति 100 है तथा किसी भी तरीके का परिवार नियोजन का साधन अपनाने वाली महिलाओं का प्रति 100 56.9 है। नसबन्दी के स्थाई साधन के रूप में महिला नसबन्दी का अधिक प्रचलन है। आईयूडी (3.2 प्रति 100) व कण्डोम (8.4 प्रति 100) का उपयोग अब भी सीमित वर्ग द्वारा ही किया जा रहा है। गत 3 वर्षों से राज्य स्तर से दिये गए लक्ष्यों के विरुद्ध जिले की उपलब्धि उत्कृष्ट रही है।;स्रोत: डीएलएचएस फेक्ट शीट 2007-2008

सारणी-7.1 परिवार नियोजन

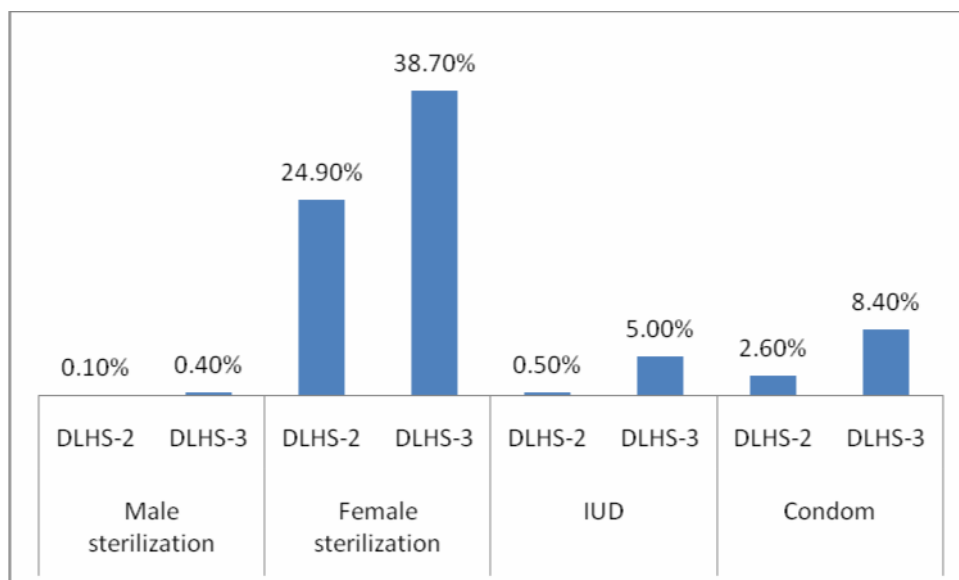
परिवार नियोजन; वर्तमान में विवाहित महिलाएँ, आयु 15-49, वर्तमान उपयोग

सूचक	जालोर		राजस्थान					
	डीएलएचएस.2	डीएलएचएस.3	डीएलएचएस.2	डीएलएचएस.3				
	कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण	कुल	ग्रामीण
अन्य साधन;:द्ध	30७5	28७9	56७9	56७5	45७9	42७2	57	55७5

अन्य आधुनिक विधि ;:द्व	29७7	28७8	55७7	55७3	41७4	38	54	52७7
महिला नसबंदी ;:द्व	24७9	24७6	38७7	38७7	31७2	31७4	40७5	41७3
पुरुष नसबंदी ;:द्व	0७1	0७1	0७4	0७4	0७6	0७5	0७5	0७5
आईयूडी ;:द्व	1७5	1७3	3७2	3७3	1७3	1	1७4	1७2
पिल्स;:द्व	0७5	0७3	5	4७9	2७6	1७9	3७2	2७8
कण्डोम ;:द्व	2७6	1७7	8७4	8	5७5	3७1	8७3	6७7
कुल अनमेट आवश्यकता;:द्व	17७6	17७4	17७2	17७5	22७1	23७5	17७9	18७5

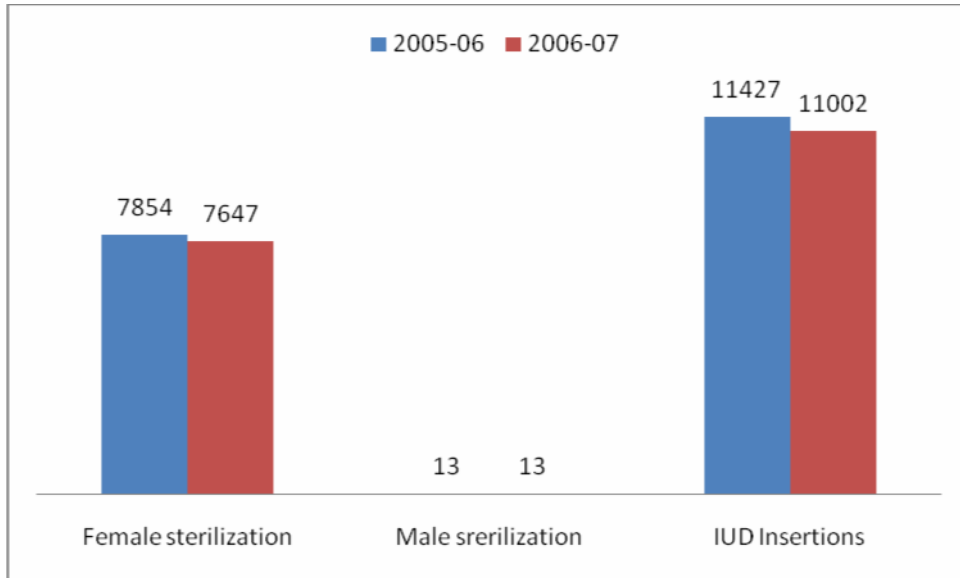
स्रोत: डीएलएचएस फेक्ट शीट 2007-2008

पुरुष नसबंदी ;:द्व महिला नसबंदी ;:द्व आईयूडी ;:द्व कण्डोम ;:द्व



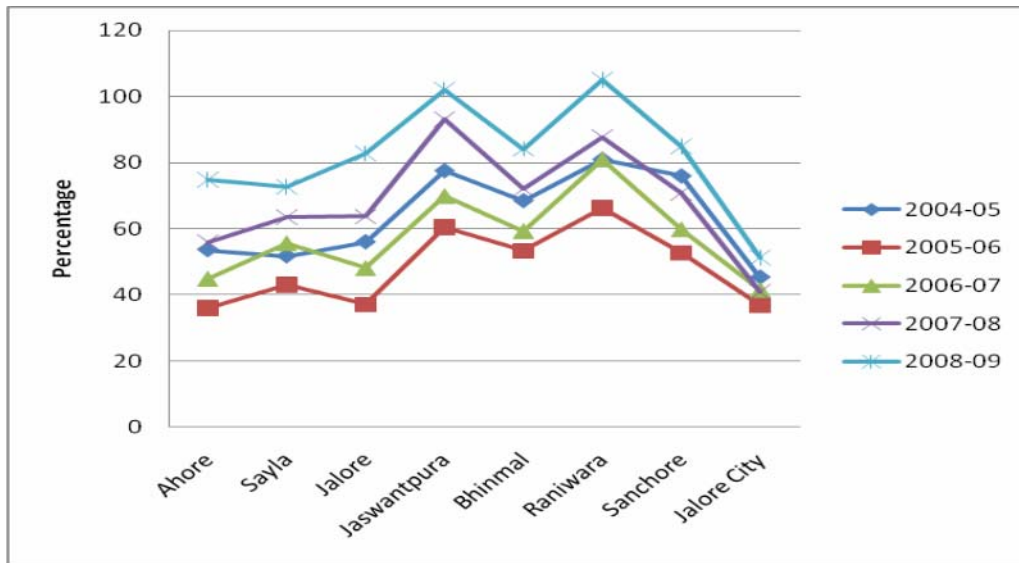
चित्र-7.1 पुरुष नसबंदी ;:द्व महिला नसबंदी ;:द्व आईयूडी ;:द्व कण्डोम ;:द्व;स्रोत सीएमएचओ,जालोर

परिवार कल्याण में डी.एल.एच.एस-2 एवं डी.एल.एच.एस-3 के आकड़ों के वि लेक्षण से स्पष्ट है कि महिला नसबंदी प्रति ात, आई.यू.डी. युजर्स प्रति ात एवं कण्डोम युजर्स प्रति ात बढ़ा है। अतः स्पष्ट हैं कि जिले में परिवार नियोजन संबंधी साधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है।(चित्र-7.1)



चित्र-7.2 परिवार कल्याण उन्नति

;स्रोत सीएमएचओ,जालोरद्व



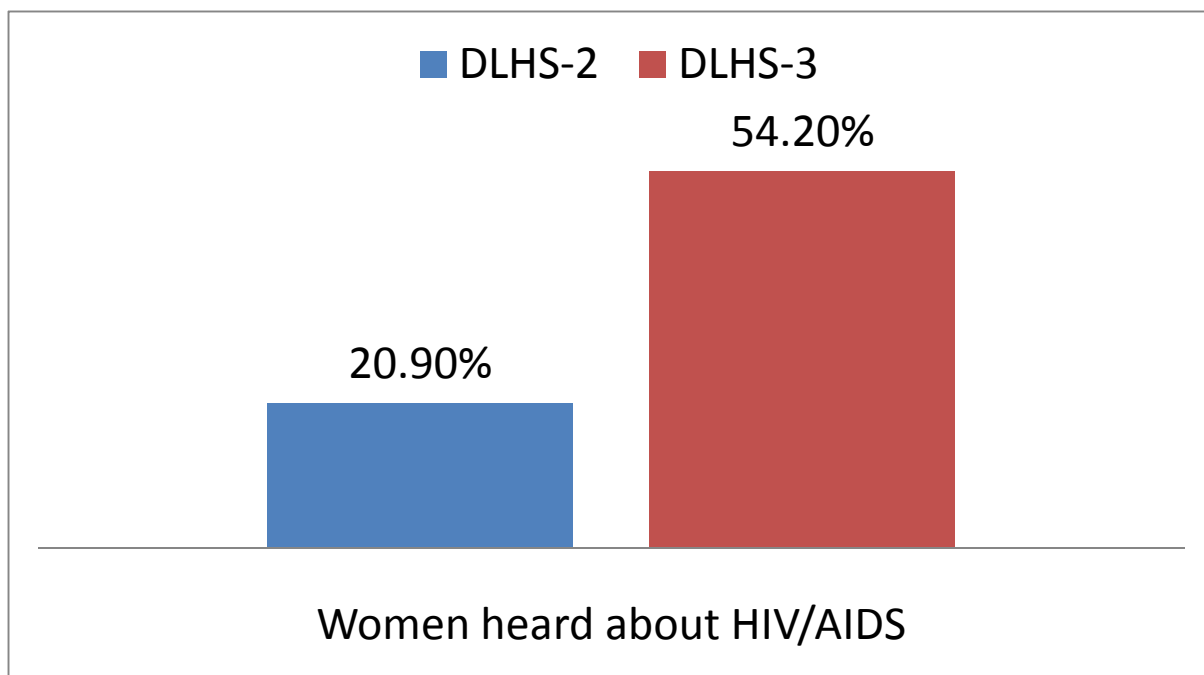
चित्र-7.3 परिवार कल्याण उन्नति

;स्रोत सीएमएचओ,जालोरद्व

8.0 एचआईवी/एड्स

जालोर में एचआईवी/एड्स के आकड़े गोपनीय दस्तावेज होने के कारण अप्राप्त हैं। फिर भी डीएलएचएस-3 के आकड़ों का विवरण प्रस्तुत है। इस संदर्भ में जालोर जिले के आहोर ब्लॉक की स्थिति चिन्ताजनक है। जिले में एकीकृत जांच एवं परामर्श केन्द्र की संख्या एक है जो कि जिला मुख्यालय चिकित्सालय में स्थित है, यहां एचआईवी/एड्स हेतु नि:शुल्क जांच एवं परामर्श सुविधा उपलब्ध है। यहां

गोपनीय माहौल में प्रशिक्षित परामर्शदाता एचआईवी/एड्स के बारे में जानकारी एवं परामर्श सुविधा प्रदान करते हैं। जिले में यौन रोग संबंधी सेवा केन्द्र की संख्या एक है। जून 2008 से मार्च 2009 तक एचआईवी पोजीटिव केस की संख्या 172 थी। अप्रैल 2009 में लाइन ए.आर.टी से लाभान्वित रोगियों की संख्या 50 है। चित्र 3 से स्पष्ट है कि डीएलएच-3 में रोग के बारे में जानकारी बढ़ी है।



चित्र-8.1 एचआईवी/एड्स से जागरूक महिलाएँ

सारणी-8.1 अविवाहित महिलाओं में एचआईवी/एड्स के प्रति ज्ञान, आयु 15-24

अविवाहित महिलाओं में एचआईवी/एड्स के प्रति ज्ञान, आयु 15-24

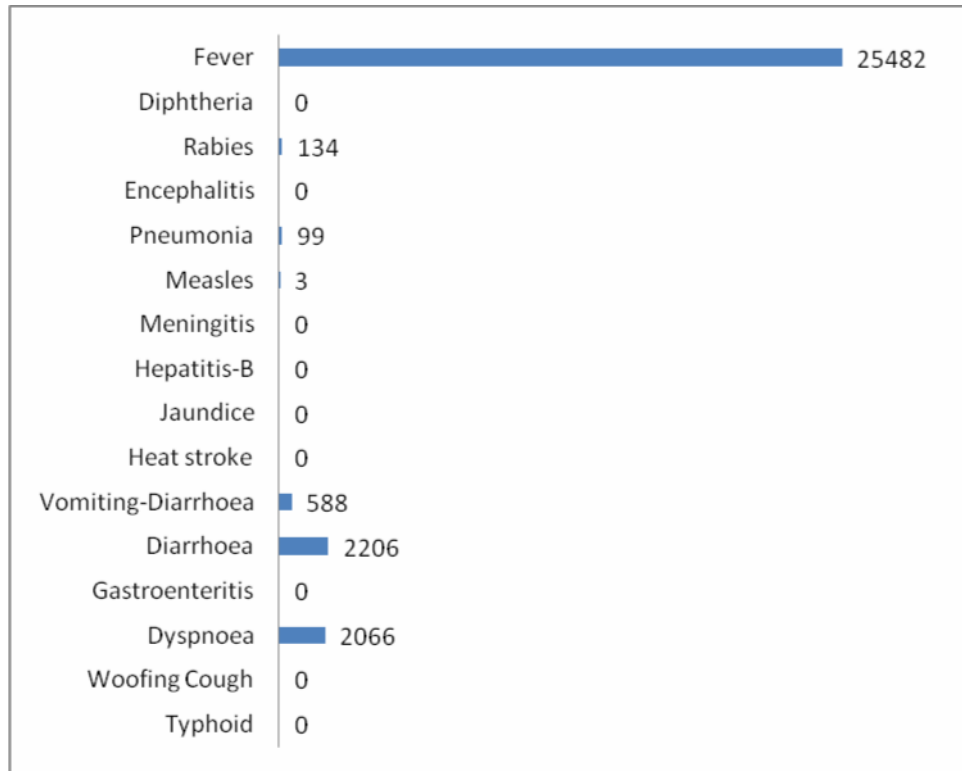
सूचक	जालोर		राजस्थान	
	डीएलएचएस.2 कुल	डीएलएचएस.3 ग्रामीण	डीएलएचएस.2 कुल	डीएलएचएस.3 ग्रामीण
आरटीआई/एसटीआई से अवगत महिलाएँ (ः)	.	.	24 ^{१५}	22 ^{१४}
एचआईवी/एड्स से अवगत महिलाएँ (ः)	.	.	70 ^{११}	70
एचआईवी/एड्स जांच की जगह से अवगत महिलाएँ (ः)	.	.	छ।	छ।
			छ।	छ।
			68 ^{१३}	64 ^{१२}

एचआईवी/एडस की जांच प्रक्रिया	0	0	छ।	छ।	0०2	0०2
से अवगत महिलाएँ (:)						
एचआईवी/एडस पूर्ण ज्ञान से	91०4	90०7	छ।	छ।	छ।	छ।
अवगत महिलाएँ (:)						

स्रोत: डीएलएचएस फेक्ट शीट 2007-2008

9.0 जिले में अन्य रोग-

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि जिले में बुखार की आवृत्ति सर्वाधिक है। और उसके बाद में उच्च भवास दर एवं डायरिया की आवृत्ति अधिक है।

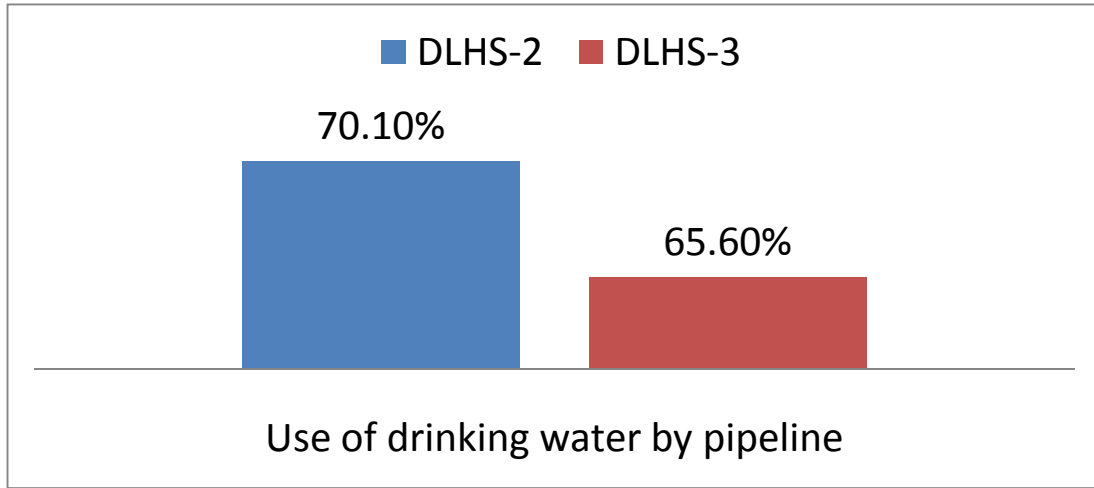


चित्र-9.1 जिले में अन्य रोग "वनतबमरू बड-भ्यु श्रंसवतमए डंतबीए 2009

10.0 जन स्वास्थ्य

10.1 पीने का पानी एवं सफाई व्यवस्था

जिले में पानी एवं सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। ग्राम स्वास्थ्य समितियों, और पेयजल समितियों का पेयजल शुद्धि एवं फ्लोरोसिस के लिए उचित रणनीति बनाने की आवश्यकता है। पेयजल से सम्बन्धित आकड़े अप्राप्त हैं। वर्तमान में जिले में 758 ग्रामीण स्वास्थ्य समितियां कार्यरत हैं। जिले में डीएलएचएस-3 2007-08 के अनुसार सुलभ सुविधा उपयोग का प्रतिशत 11.8 जो कि डीएलएचएस-2 के मुकाबले कम पाया गया। और पाईप से पेयजल के उपयोग का प्रतिशत 70.1 प्रतिशत था। जो कि डीएलएचएस-3 में कम होकर 65.6 प्रतिशत रह गया।



चित्र-10.1.1 पाईपलाइन से पेयजल का उपयोग :

10.2 फ्लोरोसिस समस्या

राजस्थान के 33 जिलों में से 18 जिलें फ्लोराईड एन्डेमिक घोषित किये गये हैं जालोर में फ्लोराईड के आंकड़ें कम उपलब्ध हैं फिर भी कुछ पूर्व अनुसंधान से आंकड़े लिये गये हैं इसमें गोपाल एट.एल. 1985 ने सर्वे के अन्तर्गत राजस्थान के 2700 पानी के नमूनों का फिजिको-केमिकल विश्लेषण किया, जिसमें जालोर के 165 पानी के नमूनों की फ्लोराईड सान्द्रता 14.2 मिली ग्राम/लीटर पाई गई जो कि चिन्ताजनक है। सर्वाधिक सान्द्रता राजस्थान के चुरू जिले में 30 मिली ग्राम/प्रति लीटर पाई गई।

औझा एट.एल. 2003 ने भी फ्लोराईड सान्द्रता का विश्लेषण किया जिसमें नागौर की सान्द्रता 34 मिली ग्राम/लीटर, पाली में 19 मिलीग्राम/लीटर और बाडमेर में 18 मिलीग्राम/लीटर पाई गई जो कि जालोर का पड़ोसी जिला है।

डाग्ली एट.एल. 2008 के ऐपिडेमियोलोजिकल सर्वे के अनुसार जालोर में पानी का स्तर 3.56 पी.पी.एम. से 4.07 पी.पी.एम. के बीच पाया गया। यहां जालोर में प्रमुख भोजन बाजरा व सरसों है जो कि कैल्सियम से भरपूर डाईट है। जालोर में डेन्टल फ्लोरोसिस की प्रवेलेंस 94.9 प्रति 100 है, 5-12 आयु वर्ग में 15 आयुवर्ग में 97.2 प्रति 100 व 35 से 44 आयु वर्ग में 95.8 प्रति 100 है। फ्लोराईड की सान्द्रता 1.5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक होती है तो दांतों पर भुरापन आ जाता है इस अवस्था को दांतों का फ्लोरोसिस कहते हैं और आगे की अवस्था में दांत काले एवं क्षीण हो जाते हैं।

फ्लोरोसिस को कम करने के लिए सुझाव:-

डीपलोरीडे तान के लिए कम खर्च वाली विधियां जैसे:- पॉली एलुमिनियम क्लोराईड एवं नालगोण्डा तकनीक का उपयोग ।

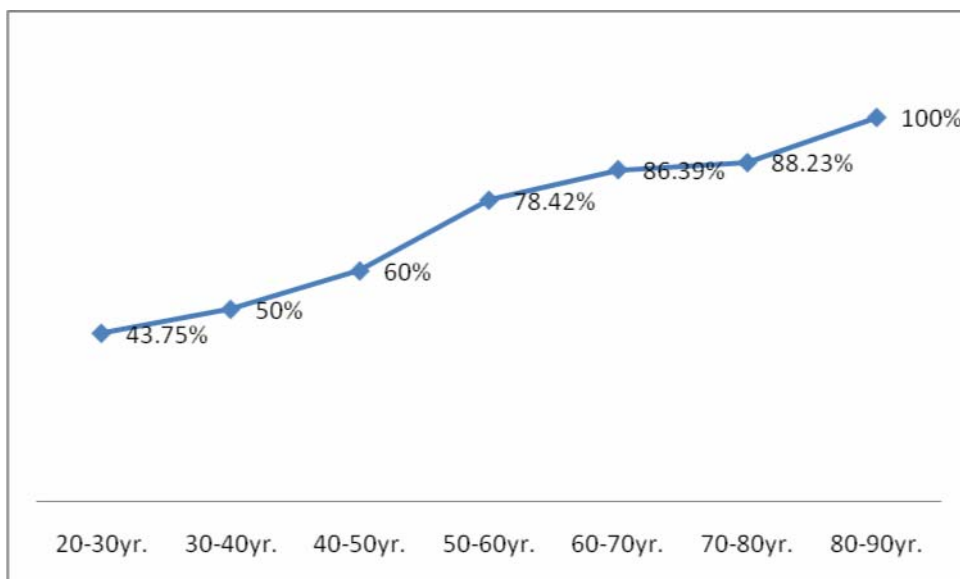
फ्लोराईड कमी वाले क्षेत्र में कुओं/ ट्यूबवेल्स का निर्माण करना ।

विटामिन –सी भरपुर डाईट का उपयोग ।

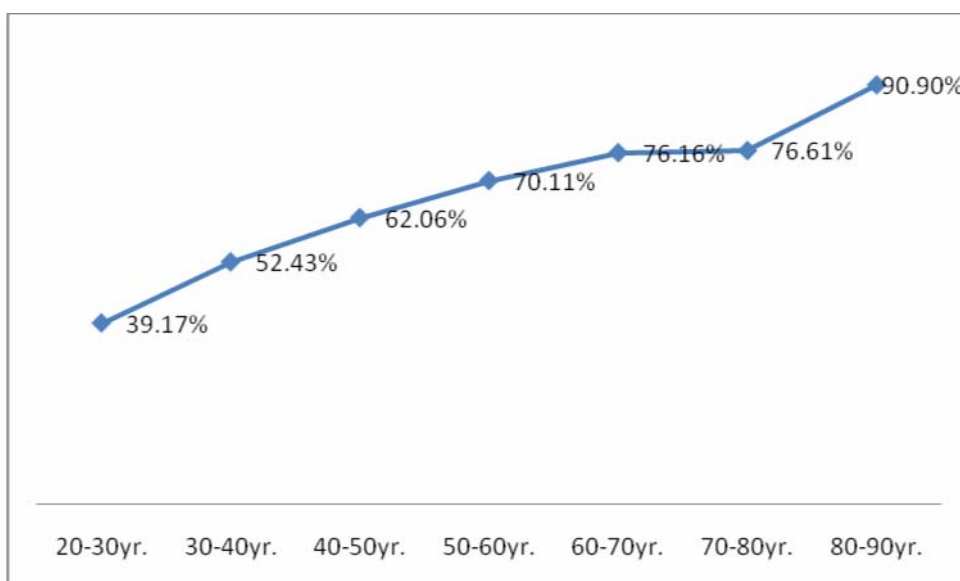
समय-समय पर फ्लोराईड एन्डेमिक क्षेत्रों में एपिडेमियोलोजिकल सर्वे करवाना ।

दूध पिलाती माताओं को फ्लोराईड रहित पानी पिलाने की सलाह देना ।

फ्लोराईड से भरपुर खाद्य (पान, सुपारी, टूथपेस्ट, माउथवाा, तम्बाकू, पान मसाल, गुटखा व चट्टानी नमक) का कम से कम उपयोग ।



चित्र-10.2.1 महिलाओं में ओस्टियोपोरोसिस एवं ओस्टोपिनिया



चित्र-10.2.1 पुरुष में ओस्टियोपोरोसिस एवं ओस्टोपिनिया

युवाओं में बढ़ रहा आस्टियोपोरोसिस

जिले में जवान हड्डियों पर फ्लोरोसिस की मार के अलावा मेडिकल साइंस में साइलेंट किलर के नाम से पहचाने वाले आस्टियोपोरोसिस की गिरफ्त बढ़ रही है। राजकीय चिकित्सालय में हुए हड्डी घनत्व जांच के शिविरों के आंकड़ों को टटोले तो कहना गलत नहीं होगा कि जिले की जवान हड्डियों को यह धीमा जहर खोखला कर रहा है। राजकीय चिकित्सालय में ओवरसीज, फारमेड, हिमालया व अर्गेनिक कम्पनियों की ओर से आए दो हजार रोगियों की स्थिति का अध्ययन किया गया। अधिकांशतया आस्टियोपोरोसिस 40 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है, लेकिन यहा स्थिति चौकाने वाली है। यहां 20 से 40 वर्ष तक के उम्रवाले युवाओं में से 7 प्रतिशत की हड्डियों में आस्टियोपोरोसिस है इसी उम्र वर्ग के 40 प्रतिशत लोग ऑस्टियोपीनिया से ग्रसित है।

जालोर में अधिकांश जगह फ्लोराईड की अधिकता होने के कारण समस्या दोगुनी है पिछले 18 माह में हुए 26 शिविरों में कुल 2030 मरीजों की जांच की गई, जिनमें 1190 पुरुष एवं 840 महिलाएँ थी। इनमें से 410 पुरुष एवं 259 महिलाएँ ही सामान्य पाए गए। बाकी सभी लोग आस्टियोपोरोसिस एवं ऑस्टियोपीनिया से ग्रसित थे। जालोर में युवाओं में तेजी से बढ़ रहा यह रोग काफी चिंताजनक है जिले में कुपोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव बड़ा कारण है।

सारणी- हड्डी घनत्व जांच के शिविरों के आंकड़े,

उम्र वर्ग	कुल जांच		सामान्य		ऑस्टियोपीनिया		आस्टियोपोरोसिस	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
20.30	97	80	59	45	33	32	5	3
30.40	164	112	78	56	70	48	16	8
40.50	232	200	88	80	96	88	48	32
50.60	348	241	104	52	184	101	60	88
60.70	214	147	51	20	85	50	78	77
70.80	124	51	29	6	54	14	41	31
80.90	11	9	1	0	2	0	8	9
कुल	1190	840	410	259	524	333	256	248

स्रोत:- राजकीय चिकित्सालय, जालोर, मार्च 2009

11.0 जिले में क्रियान्वित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

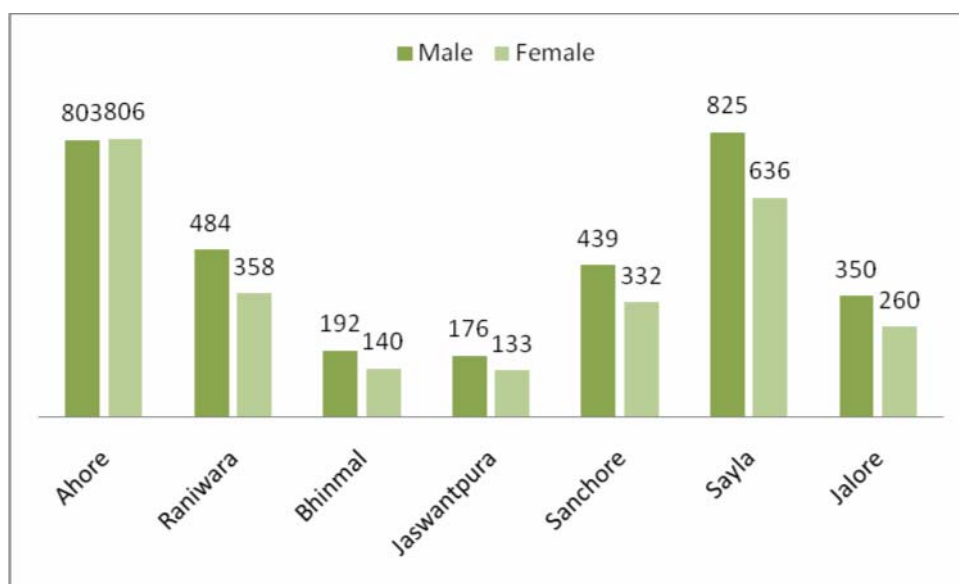
11.1 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम

वेक्टर जनित रोग राज्य की जनसंख्या को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले रोग में से एक है। राज्य में द टकों से मलेरिया मुख्य रोग बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक देखा गया है। राज्य में द टकों से मलेरिया मुख्य रोग बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक देखा गया है। जिले में वर्ष 2008-09 के दौरान मलेरिया पी0एफ0 के 29, पी0वी0 के 792 केस दर्ज किये गए।

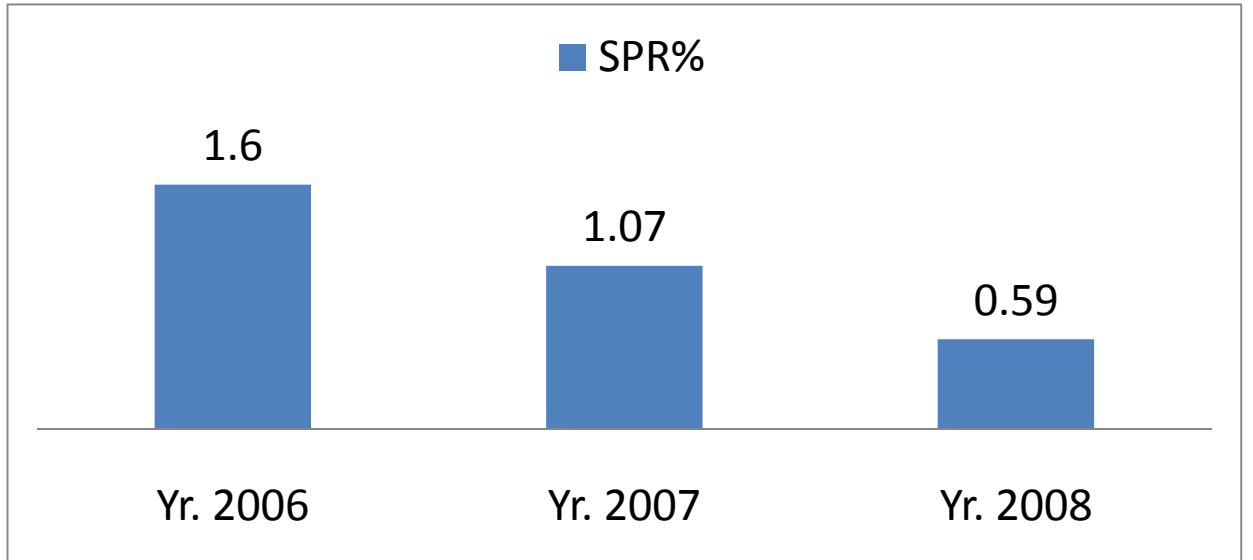
सारणी- 11.1.1 जिले में मलेरिया की स्थिति स्रोत सी.एम.एच.ओ.,जालोर, मार्च 2009

वर्ष	रक्त पट्टिका जांच	च्वपजपअम	च्दः	च्ः भे	च्अ बेंमे	च्ः	च्
2008	138400	821	0०59	29	792	3०53	0०48
2007	139983	1496	1०07	80	1516	5०35	0०88
2006	198441	3177	1०6	318	2859	10	1०97

च्दःमतव च्वपजपअपजल त्जमए |च्।ददनंस च्तेपजपब प्दकमगए



चित्ररू 11.1.1 जिले में मलेरिया की स्थिति लिंगानुसार, स्रोत सी.एम.एच.ओ.,जालोर,मार्च 2009



चित्र-11.1.2 एस.पी.आर. ;द्व वर्ष 2006ए 2007ए 2008

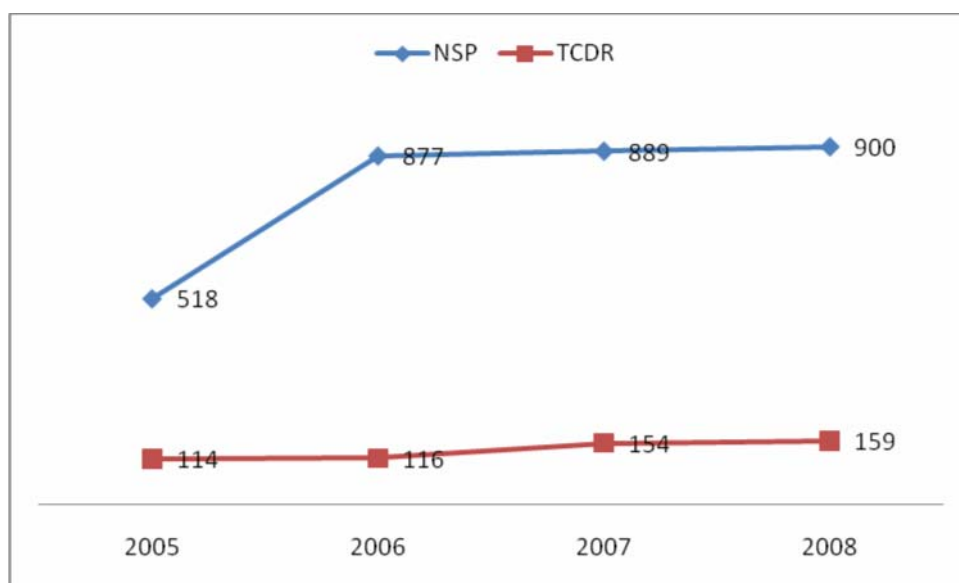
11.2 स गोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम

टी.बी. एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है तथा सभी प्रमुख बिमारियों में से मृत्यु का बड़ा कारण है। एक टी.बी. मरीज वर्ष में 10 से 15 नये रोगी पैदा कर सकता है। इसी के मद्देनजर संशोधित राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत डॉट्स (डायरेक्टली ऑब्सर्वड ट्रीटमेन्ट शॉर्टकोर्स) की रणनीति इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में लाई गई है। डॉट्स पद्धति में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में मरीज को दवाई दी जाती है एवं समय-समय पर उसकी थूक व बलगम की जाँच की जाती है। जालोर जिला 6 टी.बी. यूनिट में विभाजित है। प्रत्येक टी.बी. यूनिट पर एक चिकित्सा अधिकारी (एम0ओ0टी0सी0), लेब सुपरवाइजर तथा सुपरवाइजर पदस्थापित है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व कुछ चिन्हित प्राथमिक स्वा. केन्द्र सहित वर्तमान में जिले में 27 चिन्हित माइक्रोस्कोपीक केन्द्र क्रियाशील है। इन केन्द्रों पर टी.बी. का निदान कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देखरेख में दवाईया उपलब्ध कराई जा रही है।

सारणी:11.2.1 क्षय रोग,वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	विवरण	2005	2006	2007	2008
1	जनसंख्या ; पद सीद्ध	16१01	16१01	16१30	16१58
2	ईलाज शुरू करने वाले मरीजों की संख्या	1826	1865	2513	2638
3	इलाज के दौरान मृत्यु की दर	3:	5:	5:	2:
4	डिफॉल्ट दर	7:	6:	4:	3:
5	क्योर दर	85:	81:	88:	88:
6	नये धनात्मक रोगी (छणैण्च)	518	877	889	900
7	टोटल केस डिटेक्शन रेट ;ज्वक्त्द्ध	114	116	154	159

स्रोत : जिला क्षय रोग अधिकारी, कार्यालय जिला क्षय निवारण केन्द्र, जालोर



चित्र-11.2.1 टी.बी. प्रोग्रेस

सारणी में दिए गए आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जालोर टी0बी0 की दृष्टि से औसत जिला है, जो राज्य के औसत के लगभग रहता है। जिले की गत 4 वर्षों में केस चयन दर व क्योर दर बढ़ी है तथा नये धनात्मक रोगी बढ़े हैं। डॉट्स का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष, चिकित्सा अधिकारी देखरेख में मरीज को मानक दवाईया देना है

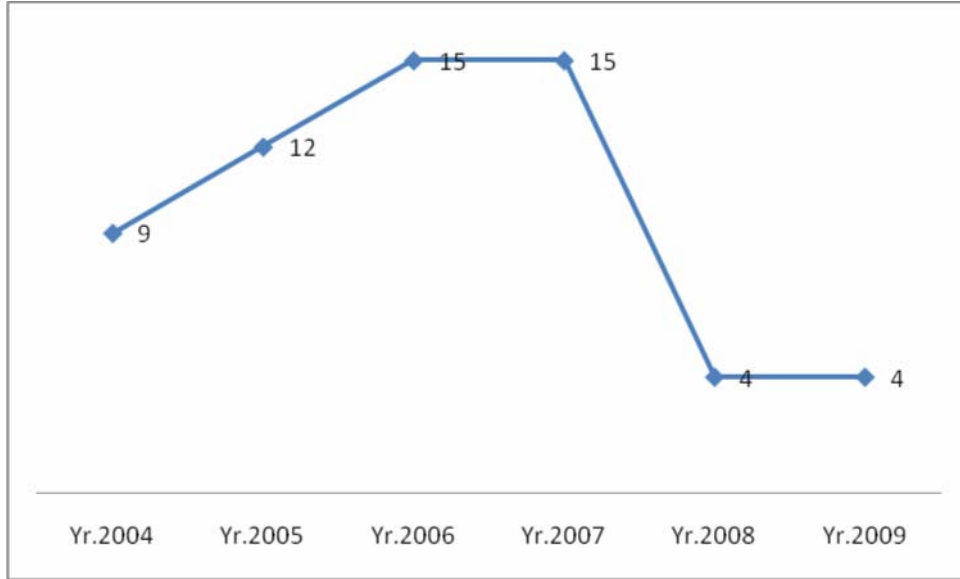
11.3 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्नमूलन कार्यक्रम :

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट हैं कि वर्ष 2006-07 में कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ी हैं। जो कि वर्ष 2008-09 में कम हुई हैं।

सारणी- 11.3.1 जालोर जिले में वर्ष 2004-2009 तक लेप्रोसी केसेज की संख्या

वर्ण	ठसवबा	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	ीवतम	4	4	0	3	0	0
2	श्रंसवतम	3	2	7	5	2	3
3	लंसं	2	4	2	3	1	0
4	श्रूदजचनतं	0	2	0	1	0	0
5	ठीममदउंस	0	0	5	1	1	0
6	तंदपूतं	0	0	1	1	0	0
7	दबीवतम	0	0	0	1	0	0

स्रोत-सी.एम.एच.ओ., जालोर,



चित्र-11.3.1 जालोर जिले में वर्ष 2004–2009 तक लेप्रोसी केसोज की संख्या

11.4 राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम

हमारे देा में अंधता का एक बड़ा कारण वृद्धावस्था में होने वाला मोतियाबन्द है। जिले में वर्ष 2006–07 के दौरान 4029 ऑपरेशन कर लोगों को लाभान्वित किया गया है। जिसमें एक भी जटिलता रिपोर्ट नहीं की गई है। यह बात गौर करने लायक है कि जिले में कुल किये गए मोतियाबिन्द ऑपरेशन में से 1298 (32.21 प्रतिशत) स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किये गए। शिविरों में यह स्थिति 50% रही।

11.5 बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवनरक्षा कोष योजना

इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के इनडोर एवं आउटडोर रोगियों को मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों, एवं सामु.स्वा.केन्द्रों तथा प्रा.स्वा.केन्द्रों पर नि:शुल्क निदान एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। वर्तमान में जिले में 9 बीपीएल काउंटर खोले जा चुके हैं।

11.6 समेकित रोग नियंत्रण निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.)

एकीकृत निगरानी परियोजना देा का विकेन्द्रीकृत राज्य आधारित निगरानी कार्यक्रम है। इसका आय आसन्न प्रकोपों के प्रारम्भिक संकेतों का पता लगाना तथा समय पर प्रभावी कार्यवाही करने में सहायता प्रदान

करना है। और इसमें मौजूदा नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध होंगे तथा स्वास्थ्य संसाधनों का और अधिक दक्ष रूप से आवंटन करने में मदद मिलेगी।

12.0 महिला विकास ;**खैरतपुर**

'वनतबमरु खैरतपुर कमचरण श्रंसवतम

जिले में स्त्री पुरुष लिंगानुपात (प्रति हजार) 964 है। जो राज्य के औसत 921 से काफी अधिक है जो अच्छा है। फिर भी यह अनुपात दर्शाता है कि जिले में 1000 पुरुषों के मुकाबले 964 स्त्रियां ही हैं। जो चिन्ता का विषय है। इससे भी चिन्ता का विषय जिले के अन्दर इस लिंगानुपात में असमानता है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में यह लिंगानुपात 970 है वहीं भादरी क्षेत्र में मात्र 889 ही है। इसमें भी जालोर नगर पालिका क्षेत्र में यह और भी कम, मात्र 873 ही है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ आहोर क्षेत्र में यह अनुपात बहुत अधिक 1023 है। वहीं रानीवाडा क्षेत्र में राज्य के औसत के करीब 933 ही है।

जिले में उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला विकास अभिकरण के कार्यालय वर्ष 2008-09 से अलग-अलग संचालित हैं। इनका संचालन उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जालोर द्वारा किया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत 7 बाल विकास परियोजनाएँ पंचायत समितिवार संचालित हैं जिसमें 1183 आँगनवाड़ी केन्द्र तथा 64 मिनी आँगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत व संचालित हैं। पूरक पोषाहार लाभान्वितों के मासिक लक्ष्य 121500 एवं स्कूल पूर्व शिक्षा के लक्ष्य 48600 के विरुद्ध प्रतिमाह क्रमशः 86 एवं 77 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित हो रही है। माह जुलाई 09 में पूरक पोषाहार से 105034 एवं स्कूल पूर्व शिक्षा से 37095 को लाभान्वित किया गया है जो क्रमशः 86 एवं 76 प्रतिशत हैं।

विभाग द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचड़ी) तथा बेबी मिक्स/पजीरी क्रमशः 3 से 6 वर्ष के बच्चों को तथा गर्भवती/धात्री माताओं/किशोरी बालिकाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, जो कुपोषित एवं अतिकुपोषितों को दिया जाता है। जालोर परियोजना में न्यूट्रीशन मिशन के तहत पूरक पोषाहार बेबी मिक्स, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार कर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पौषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना एवं सन्दर्भ सेवा, परिवार कल्याण के कार्य किये जाते हैं। परिवार कल्याण के माह जुलाई 09 में 29 एवं कुल 143 केस हुए हैं। वर्ष में दो बार 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन 'ए' का घोल रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं आँखों की रोगनि हेतु पिलाया जाता है।

महिला विकास अभिकरण के अन्तर्गत महिलाओं के संबंधित कार्य संपादित किये जाते हैं। जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार द्वारा स्वावलम्बी बनाया जाता है। जिले में प्रारम्भ से कुल 2040 समूहों का गठन तथा 554 समूहों को 187.71 लाख रुपये का ऋण विभिन्न बैंकों से उपलब्ध करवाया जाकर लाभान्वित किया गया है। किशोरी बालिकाओं को 'आपकी बेटा' योजना के तहत पौषण, स्वास्थ्य एवं शारीरिक बदलाव की शिक्षा के साथ स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर साथिन का एक पद स्वीकृत है। जिले में स्वीकृत 264 साथिनों के मानदेय पदों के विरुद्ध 51 साथिन कार्यरत हैं।

विभागीय गतिविधियों का लक्ष्य एवं प्रगति विवरण वर्ष 09-10 का माह जुलाई 09 तक निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	गतिविधि	लक्ष्य	प्रगति विवरण	वि. वि.
		मासिक/वार्षिक		

1	समेकित बाल विकास सेवा परियोजना	7	7	7	100 :
2	आंगनवाडी केन्द्र संचालन	1183	1183	1183	100 :
3	मिनी आंगनवाडी केन्द्र संचालक	64	64	64	100 :
4	पूरक पोषाहार लाभार्थी	121500 / 1458000	105034	420105	86 :
5	शाला पूर्व शिक्षार्थी	48600 / 583200	37095	148525	76 :
6	पोषाहार वितरण	243.934 डण्ड	205.617 डण्ड	241.939 डण्ड	99 :
7	आशा सहयोगिनी नियुक्ति	1183	.	460	34 :
8	स्वयं सहायता समूह गठन	500	2	15	3 :
9	स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण	500	.	.	.
10	साथिन नियुक्ति	264	—	51	19.31 :

(ब) कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला विकास अभिकरण —

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1	कार्यक्रम अधिकारी	1	—	1	अप्रैल 09 से रिक्त
2	कनिष्ठ लेखाकार	1	—	1	अप्रैल 07 से रिक्त
3	कनिष्ठ लिपिक	1	1	—	—
4	प्रचेता	7	—	7	9 वर्षों से रिक्त हैं
	कुल :-	10	1	9	—

मानदेय पदों का विवरण :-

1	साथिन	264	51	213	4 वर्षों से रिक्त हैं
---	-------	-----	----	-----	-----------------------

जिले में स्वीकृत विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 129 पदों के विरुद्ध मात्र 42 पद भरे हुए हैं। इस प्रकार 67 प्रति त पद पिछले 9 वर्षों से रिक्त चल रहे है। राष्ट्रीय एवं विभागीय कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु रिक्त पदों को भरा जाना अत्यावश्यक हैं।

13.0 एस. डब्ल्यू. ओ. टी.—विश्लेषण

मजबुती

आधारभूत ढांचा- जिले में वर्तमान में 8 सामु.स्वा.केन्द्र, 52 प्रा.स्वा.केन्द्र, 366 उप स्वा.केन्द्र संचालित हैं। जिला मुख्यालय पर एक जिला चिकित्सालय संचालित हैं।

मानव संसाधन- जिले में वर्तमान में 104 वि.िष्ट पद वाले चिकित्सा अधिकारी, पैरामैडिकल स्टाफ में 7 मेलनर्स-प्रथम, 125 मेलनर्स-द्वितीय, 20 स्टाफ नर्स, 47 महिला स्वास्थ्य दिका, 362 प्रसाविका, 54 लैब टेक्नीशियन, 22 वाहन चालक, 51 एमपीडबल्यू., 135 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 61 स्वीपर, 192 जीएनएम, 137 अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं 490 आ.ि.ा कार्यरत हैं।

योजनाएँ-जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मि.ान, राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना (आर.एच.एस.डी.पी.), राष्ट्रीय वेक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.)राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन.एल.ई.पी.), परिवर्तित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.),समेकित रोग नियंत्रण निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.),राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम (एन. बी .सी. पी.), बी.पी.एल. मुख्यमंत्री जीवनरक्षा कोष योजना, एवं गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग प्रतिशोध) अधिनियम 1994 आदि योजनाएं संचालित है।

संरचना-जिले में स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन के लिए जिला स्वास्थ्य समिति, डी.एस.एच. गठित है। जिसके अर्न्तगत जिले में कार्यरत अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम समितियां सम्मिलित है। जिला स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष जिला कलेक्टर एवं पदेन सदस्य सचिव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होता है। समिति की मासिक बैठक आयोजित होती है, जिसमें योजना एवं उसके क्रियान्वयन संबंधी निर्णय लिये जाते है।

जननी सुरक्षा योजना लागू होने से पूर्व डी0एच0एच0एस0-2 के दौरान संस्थागत जन्म का प्रति.ात 16.4 था जो डी0एच0एच0एस0-3 के समय बढ़ कर 35.1 प्रतिशत दर्ज किया गया। जालोर जिले के चिकित्सा संस्थानों पर वर्ष 2007-08 व 2008-09 के दौरान कुल संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है।

डी.एल.एच.एस-2 में कुल पूर्ण टीकाकृत बच्चें ;12-23 माहद्ध का प्रति.ात 14.4 था जो कि डी.एल.एच.एस-3 में बढ़कर 51 हो गया इससे स्पष्ट हैं कि जिले में टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ी हैं।

परिवार कल्याण में डी.एल.एच.एस-3 में महिला नसबंदी प्रति.ात, आई.यू.डी. प्रति.ात एवं कण्डोम प्रति.ात बढ़ा है। अतः स्पष्ट हैं कि जिले में परिवार नियोजन संबंधी साधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है।

कमजोरी

जिले में महिला साक्षरता दर ;7 वर्ष से अधिकद्ध 27.5 प्रति.ात हैं जो कि राजस्थान में सबसे निचले पायदान पर है। अतः महिलाओं में स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में अनभिज्ञता।

मानव सं.ाधन की कमी:- जिले में 56: पद चिकित्सा अधिकारियों, 44: पद आयुर्वेदिक चिकित्सक, 15: पद अन्य पैरामैडिकल स्टाफ एवं 67: पद आ.ि.ा के रिक्त है जो कि जिले में कार्यरत मानव सं.ोधन पर अतिरिक्त कार्यभार को द.ाता हैं।

डी.एल.एच.एस-3 के अनुसार सुलभ सुविधा उपभोग का प्रति.ात एवं पाईप से पेयजल के उपभोग का प्रति.ात घटा है।

परिवार कल्याण में पुरुष नसबन्दी मात्र 0.4 प्रति त है जो कि डी.एल.एच.एस-2 में सिर्फ 0.3 प्रति त ज्यादा है। स्पष्ट है कि जिले में पुरुष नसबन्दी के प्रति जागरूकता का अभाव है।

जिले में कुल कार्यरत चिकित्साधिकारियों में केवल 14.86: महिला चिकित्साधिकारी कार्यरत है, जो कि स्टाफ व्यवस्था में लैंगिक असमानता को दर्शाता है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव। जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों के केवल 54: ही पद भरे हैं। बाकी 46: पद रिक्त है।

स्टाफ में गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण का अभाव।

जसवन्तपुरा, हाडेचा सा. स्वा. के. रोगी ठहराव की दृष्टि से अनुपयुक्त। जसवंतपुरा में 2007-08 में कुल अंतरंग रोगियों की संख्या 2697 थी और 200 रोगी प्रति भौया थे।

अवसर

उपकरणों से संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता।

शत प्रतिशत सर्वे की आवश्यकता।

ग्राम समर्पक अभियान द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार।

ग्राम स्वास्थ्य समितियों, और पेयजल एवं स्वच्छता समितियों का पेयजल शुद्धि एवं फ्लोरोसिस के लिए उचित रणनीति की आवश्यकता।

निरंतर निरीक्षण एवं मूल्यांकन।

जोखिम/खतरा/चुनौति

घरेलू प्रसव

सम्पूर्ण टीकाकरण हेतु प्रयास।

अन्धविश्वास एवं कुरीति।

आई.एम.आर. के आकड़ें चिंता जनक।

जिले की महिला साक्षरता दर अत्यन्त कम होना चुनौति।

14.0 लक्ष्य/चुनौति

जिले में आईएमआर एवं सीएमआर के आकड़े चिंताजनक हैं अतः वर्तमान में जिले की कुल आईएमआर 92 है, जिसको आरसीएच द्वितीय के लक्ष्य 2011-12 तक 32 तक लाने का लक्ष्य है। जिले में गरीब परिवारों के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षाको योजना एक महत्वपूर्ण कदम है।

जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंगानुपात, टीकाकरण आदि मामलों में प्रगति के और समग्र प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में समस्त स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक छत के नीचे लाकर उनके क्रियान्वयन के समन्वित प्रयासों को और अधिक गति दी जा रही है। इस मिशन के तहत आम आदमी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने जिले में धनवन्तरी एम्बुलेंस 108 सेवा संचालन शुरू किया है। जिससे किसी भी आकस्मिक घटना में गंभीर रूप से घायल तथा गंभीर बीमारी की आकस्मिक घटना/अटैक के कारण या आकस्मिक प्रसव वेदना में महिला को तुरन्त अस्पताल पहुँचाना संभव हो पायेगा।

जिले में संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देने की दिशा में चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से संस्थागत प्रसवों को महत्वपूर्ण गति मिली है। अतः इसे अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू किया जायेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्राम स्वास्थ्य योजना, मृत एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण सेवायें, लिंगानुपात में समानता बनाये रखना, टीकाकरण, रोग नियंत्रण कार्यक्रम, संचारी व गैर संचारी रोगों की रोकथाम, नियंत्रण, रोग प्रतिरक्षण एवं पोषण जैसी जन स्वास्थ्य की विभिन्न सेवायें सभी को सुलभ करवाना तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों को मुख्य धारा से जोड़ना प्रमुख लक्ष्य हैं।

जिले में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के शिक्षा सूचना और संचार ब्यूरो द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचाने के अवसरतः प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन अब हमें स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पत्रों, पोस्टर, पम्पलैट आदि के अलावा अपने पारम्परिक माध्यमों के साथ स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी महत्वपूर्ण कड़ी आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रसाविका स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि का भी इसमें प्रभावी सहयोग लेना अत्यन्त लाभकारी होगा। जिससे स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं की जानकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क के जरिये स्थानीय सम्बन्धित लोगो तक पहुँचाने का कार्य बखुबी करते हुए लोगो को उन योजनाओं का लाभ उठाने के प्रति जागरूक कर सके।

जिले में स्वास्थ्य विभाग स्टाफ की भर्ती के लिए आनवरत प्रयत्न शील है। जिसे की कार्यरत स्टाफ पर अतिरिक्त कार्यभार को कम किया जा सके।

अध्याय षट्
आजीविका



4.1 रोजगार व श्रम भाक्ति

जिले में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कार्य िल, सीमान्त एवं अकार्य िल तथा आर्थिक क्रियाकलाप अनुसार जनसंख्या एवं उनका प्रति ात का विवरण तालिका संख्या 4.1 में दर्ाया गया है।

तालिका संख्या 4.1

कार्य िल जनसंख्या

संख्या में :-

क्र.स.	तहसील	कार्यशील	सीमांत	अकार्यशील	काश्तकार	खैतीहर मजदूर	पारिवारिक उधोग	अन्य कार्य करने वाले
1	जालोर	60346	20101	138934	26120	16973	3832	33522
2	आहोर	57684	33477	116800	40504	22203	3489	24965
3	सांचौर	168646	79198	120160	205181	12118	6544	24001
4	भीनमाल	56613	31953	132980	43526	11471	4245	29324
5	रानीवाडा	67957	10747	84645	58413	7065	1784	11442
6	सायला	50272	21833	65699	54526	6272	1712	9595
7	बागोडा	44806	23576	62513	54414	4571	1923	7474
योग		506324	220885	721731	482684	80673	23529	140323

(वनतबम ब्मदेने 2001)

उपर्युक्त तालिका संख्या 4.1, से स्पष्ट है कि जिले में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कार्य िल जनसंख्या 506324, सीमान्त कार्य िल जनसंख्या 220885 तथा भोश 721731 जनसंख्या अकार्य िल थी। इससे जिले में बेरोजगारी की स्थिति स्पष्ट होती है।

4.1.1 अनुसूचित जनजाति

जिले में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 126799 है जो जिले की कुल आबादी का 8.75 प्रति ात है, जो राज्य के औसत अनुपात 12.56 प्रति ात से काफी कम है। जिले में भी यह आबादी कुछ क्षेत्र विशेष में अधिक पायी जाती है। जैसे आहोर, रानीवाडा व बागौडा में यह कुल आबादी का क्रम ा: 11.54, 14.23 व 10.09 है, वहीं सांचौर व सायला में क्रम ा: 4.40 व 5.57 प्रति ात ही है। जिले की अनुसूचित जनजाति

आबादी में भील जाति की अधिक संख्या है, जो अभी भी अपने पुराने रीति-रिवाजों से रहते हैं और रोजगार के साधन भी पुराने समय के ही हैं। जिले में अनुसूचित जनजाति आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित व गरीब है। यह आबादी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। इस वर्ग में अधिकतर लोग गरीब हैं। इस वर्ग के लोग भाहरी क्षेत्रों में बहुत कम रहते हैं जिले की कुल भाहरी आबादी में इस वर्ग की जनसंख्या मात्र 5 प्रतिशत है।

4.1.2 अनुसूचित जाति

जिले में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 261315 है, जो जिले की कुल जनसंख्या की 18.03 प्रतिशत है। जिले में यह आबादी लगभग सभी क्षेत्रों में निवास करती है। मात्र तहसील क्षेत्र बागोडा में कम पायी जाती है, जो मात्र 10.54 प्रतिशत ही है। अन्य सभी क्षेत्रों में लगभग समान अनुपात में निवास करती है। यह आबादी भाहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग समान अनुपात में निवास करती है। नगरीय क्षेत्र सांचौर में तो यह जिले के औसत से अधिक निवास करती है। जिले में इस आबादी में मुख्य रूप से मेगवाल व जीनगर जाति निवास करती है। इस जाति के अधिकतर लोग रोजगार की तलाश में राज्य के अन्य जिलों व अन्य राज्यों में पलायन करते रहते हैं। इस वर्ग में भी गरीबी बड़ी मात्रा में है।

4.1.3 गरीबी

जिले में ग्रामीण व भाहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का विवरण तालिका संख्या 4.2 के अनुसार है।

तालिका संख्या 4.2

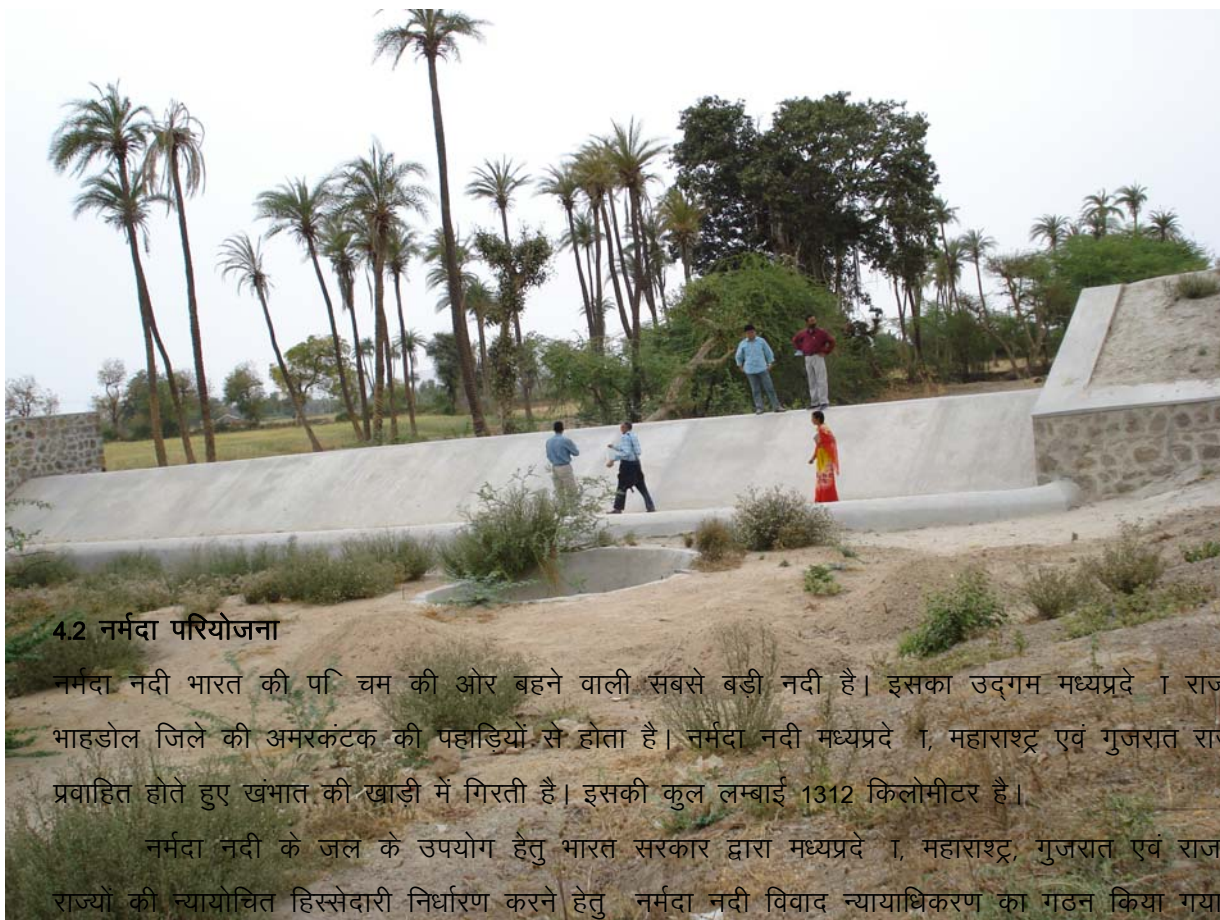
ग्रामीण क्षेत्र

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	परिवारों की संख्या (बीपीएल सेन्सस 2002 के अनुसार)	बीपीएल परिवार (बीपीएल सेन्सस 2002 के अनुसार)	गरीब परिवारों का प्रतिशत
1	प.स.जालोर	29560	5108	17.28

क्रस	पंचायत समिति का नाम	परिवारो की संख्या (बीपीएल सेन्सस 2002 के अनुसार)	बीपीएल परिवार (बीपीएल सेन्सस 2002 के अनुसार)	गरीब परिवारों का प्रतिशत
2	प.स. सायला	42903	9062	21 ^१ 12
3	प.स. आहोर	42809	5142	12 ^० 01
4	प.स.भीनमाल	40861	11692	28 ^६ 61
5	प.स.जसवंतपुरा	30685	4768	15 ^७ 54
6	प.स.सांचौर	73535	33973	46 ^२ 20
7	प.स.रानीवाडा	34111	8984	26 ^३ 34
	योग ग्रामीण	294464	78729	26^७74
शहरी क्षेत्र				
1	न.पा.जालोर	44830	1552	19 ^१ 22
2	न.पा.भीनमाल	39280	1425	21 ^१ 29
3	न.पा.सांचौर	25884	1451	34 ^० 05
	योग नगर	109994	4428	26^१53
	कुल योग	313491	83157	26^१53

तालिका से स्पष्ट है कि 26.53 प्रति शत आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। जिले में भी ग्रामीण क्षेत्रों में यह 26.74 प्रतिशत परिवार है, जबकि भाहरी क्षेत्रों में यह 26.53 प्रतिशत परिवार है। क्षेत्रानुसार अवलोकन से स्पष्ट है कि पंचायत समिति सांचौर क्षेत्र में 46.20 प्रतिशत परिवार आज भी गरीबी रेखा से नीचे है, जबकि भीनमाल एवं रानीवाडा क्षेत्रों में यह क्रमशः 28.61 व 26.34 प्रतिशत परिवार ही है। इस प्रकार जिले में भाहरी के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सांचौर में अत्याधिक गरीबी है।

नर्मदा परियोजना



4.2 नर्मदा परियोजना

नर्मदा नदी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम मध्यप्रदेश राज्य के भाहडोल जिले की अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। नर्मदा नदी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लम्बाई 1312 किलोमीटर है।

नर्मदा नदी के जल के उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों की न्यायोचित हिस्सेदारी निर्धारण करने हेतु नर्मदा नदी विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा नर्मदा नदी के उपलब्ध जल में से राजस्थान राज्य को 5 लाख एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया।

सरदार सरोवर परियोजना:

राजस्थान राज्य को यह पानी गुजरात राज्य के नांदेड जिले के नवगांव ग्राम से 5.63 कि.मी. दूर स्थित निर्माणाधीन सरदार सरोवर बांध से निकलने वाली नर्मदा मुख्य नहर के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके लिए सरदार सरोवर बांध से राजस्थान सीमा तक 458 कि.मी. लम्बी नर्मदा मुख्य नहर का निर्माण किया गया है, जिसके निर्माण लागत के हिस्से के रूप में 647 करोड़ रुपये का भुगतान गुजरात सरकार को किया गया है।

नर्मदा मुख्य नहर के हैड पर जल प्रवाह क्षमता 40,000 घन फुट प्रति सैकण्ड (1133 घन मिटर प्रति सैकण्ड) है, जिसमें से राजस्थान राज्य की हिस्सेदारी 2635 घन फुट प्रति सैकण्ड (74.577 घन मिटर प्रति सैकण्ड) है। राजस्थान गुजरात सीमा पर राज्य को 4.84 लाख एकड़ फीट पानी उपलब्ध होगा जिसमें से सिंचाई के लिये 3.78 लाख एकड़ फीट एवं जल प्रदाय योजनाओं के लिये 1.068 लाख एकड़ फीट पानी उपयोग में

लाया जायेगा। नर्मदा मुख्य नहर के हैड पर जल प्रवाह क्षमता 40,000 घन फुट प्रति सैकण्ड (1133 घन मिटर प्रति सैकण्ड) है,

जल उपलब्धता (लाख एकड़ फीट में)	
नर्मदा मुख्य नहर हैड पर	5.00
राजस्थान सीमा पर	4.84
पेयजल हेतु	1.068
सिंचाई हेतु	3.78

जिलेवार सिंचाई से होने वाले लाभान्वित गांव

सिंचित क्षेत्र लाख हैक्टेयर में)							
क्र. सं.	जिला	सतही प्रणाली		उत्थान प्रणाली		योग	
		गांवों की संख्या	सिंचित क्षेत्र	गांवों की संख्या	सिंचित क्षेत्र	गांवों की संख्या	सिंचित क्षेत्र
1	जालोर	85	1.22	40	0.41	125	1.63
2	बाड़मेर	11	0.04	97	0.79	108	1.83
कुल		96	1.26	137	1.20	233	2.46

नहरें	
मुख्य नहर	74 किमी
वितरिका एवं उप वितरिका	
सतही प्रणाली	263.93 किमी
उत्थान प्रणाली	122.07 किमी
माईनर एवं सब माईनर	
सतही प्रणाली	668.08 किमी
उत्थान प्रणाली	664.92 किमी
योग	1793.00 किमी
सिंचित क्षेत्र	245881 हैक्टर

पेयजल योजना

परियोजना क्षेत्र में भू जल खारा होने से पेयजल की गंभीर समस्या है, इसके निराकरण हेतु परियोजना से सिंचित सीमा के आस-पास के 1336 ग्राम जालोर जिले के 697 ग्राम एवं बाड़मेर जिले के 639 ग्राम एवं 3 कस्बों क्रम 1: जालोर, सांचोर एवं भीनमाल को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी, जिससे 21 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

यह परियोजना इस क्षेत्र के निवासियों के लिये जीवन रेखा साबित होगी। इस परियोजना से थार रेगिस्तान के जालोर एवं बाड़मेर जिले की भूमि को 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे न केवल कृषि का उत्पादन (तकरीबन 90,727 टन) बढ़ेगा अपितु क्षेत्र के निवासियों का समग्र रूप से सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान भी होगा।

वर्तमान प्रगति

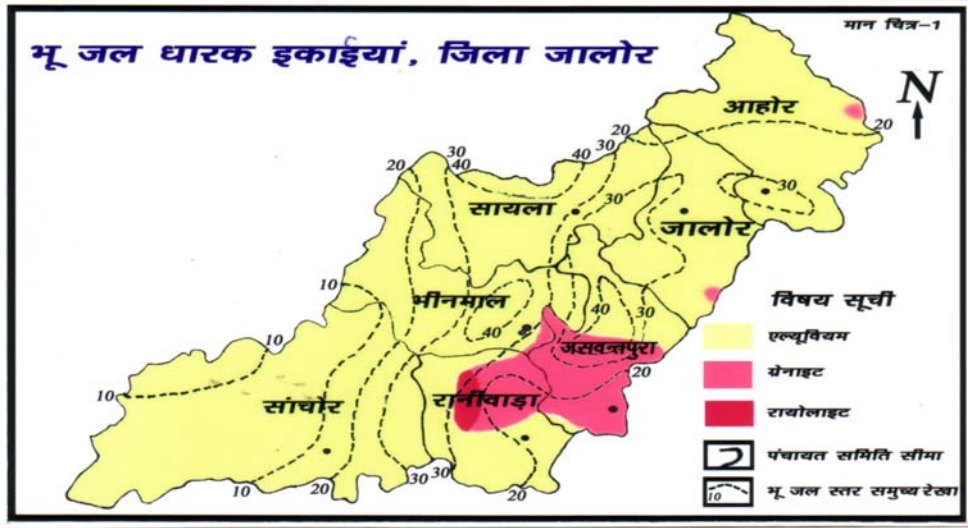
परियोजना में अब तक मुख्य नहर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, साथ ही 721 कि.मी. लम्बी सतही प्रणाली का कार्य एवं 350 कि.मी. लम्बी जलोत्थान वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे वर्ष 2011-12 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस वर्ष रबी में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

4.2.1 जलप्रदाय-

जिले में भू जल संसाधनों का आंकलन ळण्म्ब् के दि ा निदे ाँ के अनुरूप किया गया है। भू जल आंकलन वर्ष 2008 के अनुसार जिले में वार्षिक भू जल उपलब्धता 403.19 मिलियन क्यूबिक मीटर ;उबउद्ध है। कुल वार्षिक भू जल दोहन 908.78 उबउ है व भविष्य में सिंचाई हेतु भू जल की उपलब्धता ;द्ध 542७85 उबउ है। जिले के भू जल की विकास की दर 225.39 प्रति ात है व जिला भू जल की दृष्टि से अतिदोहित श्रेणी में आता है।

जालोर जिले में चार मुख्य जलभृत ;ुनपमितद्ध यंगर एल्यूवियम, ओल्डर एल्यूवियम, ग्रेनाइट व रायोलाइट है। यंगर एल्यूवियम जल भृत ;ुनपमितद्ध नदियों व नालों के पास पाया जाता है। इस जलभृत में भू जल स्तर 7 मीटर से 77 मीटर तक है। नलकूपों एवं कूपों की जलदेय क्षमता 6000 से 27000 लीटर प्रतिघंटा है। ओल्डर एल्यूवियम जलभृत में मुख्यतः बालू रेत, बजरी, रेली, चिकनी मिट्टी व कंकर की परतें पाई जाती है। इस जलभृत में भू जल स्तर 9.00 मीटर से 88.00 मीटर तक है। नलकूपों व कूपों की जलदेय क्षमता 6000 से 35000 लीटर प्रतिघंटा तक है। ग्रेनाइट व रायोलाइट जलभृत में भूमि जल ऊपरी अपरदित जोन व छिछली व मध्यम गहराई में पाये जाने वाली दरारें इत्यादि में पाया जाता है। ग्रेनाइट व रायोलाइट में बने नलकूप एवं कूपों की जलदेय क्षमता 5000 से 10000 लीटर प्रतिघंटा तक है। इस जलभृत में भू जल स्तर 6 मीटर से 30 मीटर तक है।

भू जल की दृष्टि से जिले को 31 पोटेन्शियल क्षेत्रों एवं 6 लवणीय क्षेत्रों में बांटा गया है। इन पोटेन्शियल क्षेत्रों का नामांकन। यंगर एल्युवियम, लव ओल्डर एल्युवियम, ल ग्रेनाइट व ल रायोलाइट में किया गया है। जिले की भू जल धारक इकाईयों (पोटेन्शियल क्षेत्रों) को निम्न मानचित्र में दर्शाया गया है।



जालोर जिले में वर्तमान में 244 कूपों/पीजोमीटर के आधार पर भू जल स्थिति जैसे भू जल स्तर, भू जल निकासी, भू जल गुणवत्ता आदि की जाँच की जाती है। जिले में स्थित आधारभूत कुओं के भू जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण दर्शाता है कि जिले में भू जल स्तर 6.00 मीटर से 88.00 मीटर तक है व जिले की सभी पंचायत समितियों में निरन्तर भू जल स्तर में गिरावट हो रही है। जिले में वर्ष 1995 से वर्ष 2009 के मध्य भू जल स्तर में औसत गिरावट की गणना की गई। भू जल स्तर में वर्ष 1995-2009, 2004-2009 व 2008-09 के मध्य क्रमशः 6.66, 5.53 व 2.83 मीटर दर्ज की गई है। इन अवधियों में भू जल स्तर में औसत गिरावट की दर क्रमशः 1.19, 1.11 व 2.83 मीटर प्रति वर्ष की रही है।

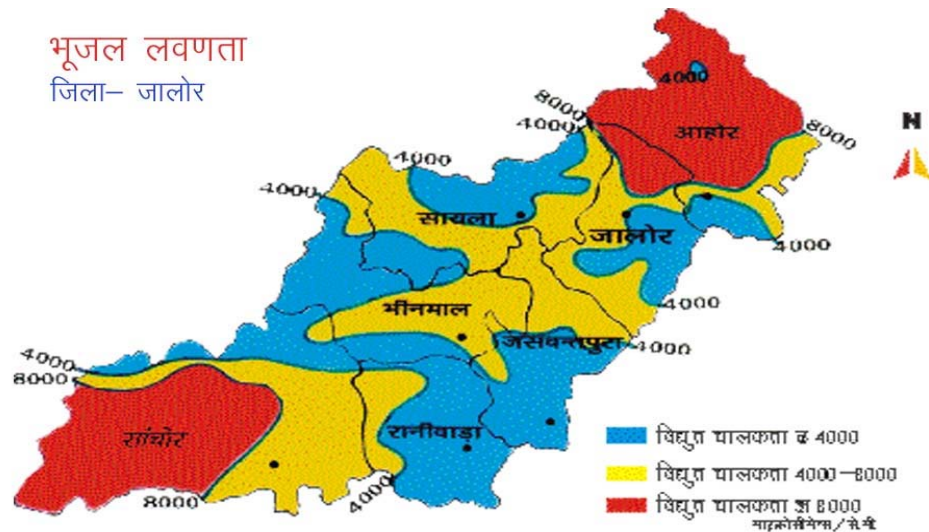
भू जल की रासायनिक गुणवत्ता

जालोर जिले में पंचायत समिति आहोर, रानीवाड़ा, जसवन्तपुरा, भीनमाल व सायला में जवाई-सुकड़ी, सागी, बाण्डी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में भू जल की विद्युत चालकता; स्मबजतपबंस ब्दकनबजपअपजलद्ध 4000 माईक्रोसीमेन्स/सेमी. से कम है। आहोर के उत्तर एवं सांचोर के पश्चिमी भाग में भू जल अत्यधिक लवणीय है। भू जल की विद्युत चालकता; स्मबजतपबंस ब्दकनबजपअपजलद्ध 8000 माईक्रोसीमेन्स/सेमी. से अधिक है यह भू जल कृषि हेतु उपयुक्त नहीं है। जिले में नदियों से दूरस्थ क्षेत्रों में भू जल की विद्युत चालकता; स्मबजतपबंस ब्दकनबजपअपजलद्ध 4000 से 8000 माईक्रोसीमेन्स/सेमी. तक है, जो कि लवणीय जल में बोई जा सकने वाली फसलों के लिए उपयुक्त है।

पंचायत समिति भीनमाल के उत्तर पश्चिम में 60 मीटर एवं सांचोर पंचायत समिति के उत्तर में 120 मीटर गहराई के पश्चात् कृषि योग्य भू जल जिसकी विद्युत चालकता; स्मबजतपबंस ब्दकनबजपअपजलद्ध 4000-6000 माईक्रोसीमेन्स/सेमी. के मध्य पाई गई है। भू जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिकांश क्षेत्रों में 1.5 - 3.0 मिलीग्राम प्रतिलीटर तक है। आहोर एवं जसवन्तपुरा पंचायत समिति के पूर्वी भाग में, सायला के उत्तर व

दक्षिणी-पश्चिमी भाग एवं सांचोर के दक्षिण भाग के भू जल में फ्लोराइड (3 मि.ग्रा./लीटर से अधिक) पाया गया है इन क्षेत्रों में भू जल की पीने की पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसी प्रकार जिले के उत्तर, पूर्व एवं पश्चिमी भाग में नाइट्रेट की मात्रा 100 मि.ग्रा./लीटर से अधिक है। नाइट्रेट की भू जल में अधिक मात्रा कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है लेकिन पीने के पानी की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है। पीने योग्य भू जल नदियों के आसपास के कुछ क्षेत्र में उपलब्ध है।

भू जल की रासायनिक गुणवत्ता



समस्याएं

अत्यधिक भू जल दोहन एवं कम वर्षा के कारण जिले में निरन्तर गिरता भू जल स्तर।

भू जल से सिंचित क्षेत्र में कमी व पीने योग्य पानी की उपलब्धता कम हो रही है।

अधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भू जल गुणवत्ता में ह्रास।

सामान्य से कम वर्षा एवं सूखे के कारण जल उपलब्धता एवं भू जल पुनर्भरण में कमी

भू जल लवणता तथा फ्लोराइड की मात्रा (सान्द्रता) व भू जल गुणवत्ता में ह्रास।

ट्रीटमेन्ट प्लान्ट

जालोर जिले में उपलब्ध पेयजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, टीडीएस आदि की मात्रा अधिक है। इसके निराकरण के लिए प्रत्येक ग्राम स्तर पर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाने की आवश्यकता है। लोगों में इस बात की जागरूकता की आवश्यकता है कि पीने हेतु फिल्टर वाटर एवं अन्य कार्यों के लिए सादा पानी काम लें। जालोर जिले में पेयजल वितरण करने से पूर्व जल का क्लोरिनेशन आवश्यकता तय करने के बाद ही वितरण किया जाता है।

हैण्ड पम्प पर डीफ्लोरिडेशन संयंत्र



भविष्य योजना

भूजल के अत्यधिक दोहन से निरन्तर गिरते जल स्तर के कारण भूजल की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। जिससे ज्वैए छठए बस एवं थस की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

जालोर जिले के तीनो कस्बो एवं समस्त गांवो एवं ढाणियो को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु नर्मदा नहर परियोजना से जोडा जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त परियोजना को तीन चरणो में पूर्ण किया जाना है। जिसकी कुल लागत 1693 करोड़ रूपये है।

प्रथम चरण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है एवं यह कार्य ~~पटख~~ हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। योजना के पूर्ण होने पर जालोर, आहोर एवं सायला तहसील के 281 गांवो को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जायेगा। द्वितीय चरण में सांचौर एवं भीनमाल तहसील के गांवो को लाभान्वित किया जाना है इस योजना के सर्वे का कार्य प्रगति पर है।

योजना के पूर्ण क्रियान्वयन होने पर जालोर जिले के समस्त गांवो एवं ढाणियो को स्वच्छ एवं उत्तम गुणवत्ता का पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

4.2.2 जल संसाधन

जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2008 तक कुल 158 छोटे, बड़े बांधों का निर्माण विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत करवाया गया है। इन बांधों की कुल भराव क्षमता 8085 एमसीएफटी (228.84 मि.क्यू.मी.) है एवं कुल सिंचाई क्षमता 41865 हैक्टर है तालिका संख्या 4.4 के अनुसार है :-

तालिका संख्या 4.4

क्र. सं.	विभाग	बांधों की संख्या	बांधों की कुल भराव क्षमता (एमसीएफटी में)	सी.सी.ए. (हैक्टर में)	लाभान्वित ग्राम की संख्या	लाभान्वित परिवारों की संख्या
1	जल संसाधन विभाग	32	6168.00	32549.00	72	9600
2	पंचायत समितियों को	126	1917.00	9316.00	85	2550

हस्तान्तरित बांध						
योग:-	158	8085.00	41865.00	157	12150	

(स्रोत जल संसाधन विभाग)

जिले में उपलब्ध 432.23 मि.क्यू.मी. पानी में से जल संसाधन विभाग द्वारा 158 बांधों को निमित्त कर 228.84 मि.क्यू.मी.(8085 एम.सी.एफ.टी.) पानी का स्टोरेज कर लिया गया है । इन बांधों का निर्माण होने से सिंचाई क्षेत्र में 41865 हैक्टर व भूमिगत जलस्तर में बढ़ोतरी होने से कृषि एवं पेयजल की उपलब्धता से 157 ग्रामों के मानव विकास में निर्णायक उन्नति हुई है ।

विभाग की भावी वर्ष 2015 तक रणनीति का विवेचना

1-आगामी वर्षों में जिला जालोर के तहसील भीनमाल में निर्मित बाण्डी सणधरा मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य प्रगतिरत रहेंगे । विवरण तालिका संख्या 4.5 अनुसार है:-

तालिका संख्या 4.5

बांध का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	वर्ष 2008-09 तक प्रगति राशि लाखों में	वर्ष 2009-10 हेतु प्रस्तावित प्रगति राशि लाखों में	वर्ष 2010-11 हेतु प्रस्तावित प्रगति राशि लाखों में	लाभान्वित क्षेत्र हैक्टर में	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित परिवारों की संख्या
बाण्डी सणधरा मध्यम सिंचाई परियोजना	3702.82	2758.71	500.00	100.00	4913.00	6	1500

(स्रोत जल संसाधन विभाग)

आगामी वर्षों में जिला जालोर के तहसील आहोर में स्थित बांकली बांध की नहरों का शेष पुनरुद्धार कार्य नाबार्ड से वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रगतिरत रहेगे । विवरण निम्नानुसार है:-

बांध का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	वर्ष 2008-09 तक प्रगति राशि लाखों में	वर्ष 2009-10 हेतु प्रस्तावित प्रगति राशि लाखों में	वर्ष 2010-11 हेतु प्रस्तावित प्रगति राशि लाखों में	लाभान्वित क्षेत्र हैक्टरों में	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित परिवारों की संख्या

बांकली केनाल पुनरुद्धार कार्य	428.62	96.42	250.00	150.00	5382.00	11	1625
-------------------------------	--------	-------	--------	--------	---------	----	------

(स्रोत जल संसाधन विभाग)

3- पिछले वर्षों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स योजना के अन्तर्गत 69 कार्यों को विभाग द्वारा पूर्ण करवाया गया है जिससे 78 ग्रामों के कुओं में जलस्तर में वृद्धि हुई है जिस कारण पेयजल एवं कृषि उत्पादन में अभिवृद्धि होने से मानव विकास पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । आगामी वर्षों हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किये जा चुके हैं :-

योजना का नाम	पूर्व में स्वीकृत कार्यों की संख्या	लागत लाखों में	वर्ष 2008-09 तक प्रगति	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	वर्ष 2009-10 व 2010-11 हेतु प्रस्तावित कार्यों की संख्या	लागत लाखों में	लाभान्वित ग्रामों का नाम	लाभान्वित परिवारों की संख्या
वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स	69	833.11	554.28	78	19	271.31	19	अप्रत्यक्ष लाभा

(स्रोत जल संसाधन विभाग)

4- आगामी वर्षों में जिला जालोर के तहसील जालोर, भीनमाल एवं रानीवाडा के तीन लघु सिंचाई परियोजनाएं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रगतिरत रहेंगे जो निम्नानुसार हैं:-

तालिका संख्या 4.6

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत करोड़ों में	भराव क्षमता (एमसीएफ टी में)	सी.सी.ए. हैक्टयर में	वर्ष 2010-11 हेतु प्रस्तावित राशि करोड़ों में	वर्ष 2011-12 हेतु प्रस्तावित राशि करोड़ों में	वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तावित राशि करोड़ों में	लाभान्वित ग्रामों की संख्या	लाभान्वित परिवारों की संख्या (अनुमानित)
1	आकोली सिंचाई परियोजना	6.64	70.67	458.00	2.50	2.50	1.64	2	376
2	सागी	4.50	97.50	980.	1.75	1.75	1.00	3	250

	सिंचाई परियोजना			00					
3	सावीदर सिंचाई परियोजना	4.00	125.00	448. 00	1.50	1.50	1.00	1	200
	योग:-	15.14	293.17	1886. 00	5.75	5.75	3.64	6	826

(स्रोत जल संसाधन विभाग)

तीनों परियोजना पूर्ण होने पर 293.17 एम.सी.एफ.टी. पानी स्टोरेज कर 1886 हैक्टर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा श्रजित कर 6 ग्रामों को लाभान्वित किये जायेंगे ।

डेयरी



पश्चिमी राजस्थान में जिला जालोर मुख्यालय से 110 किलोमीटर दक्षिण की ओर रानीवाड़ा-सॉचौर मुख्य मार्ग पर स्थित रानीवाड़ा डेयरी का जीवनपथ बहुत संघर्ष पूर्ण रहा है । क्षेत्र के अत्यधिक पिछड़ेपन एवम् अत्यन्त विषम भौगोलिक परिस्थितियों वंश 'टाटा' जैसे वृहत् एवम् प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह का संचालन भी असफल रहा जिसके कारण डेयरी दो बार बन्द हुई ।

ऐसी स्थिति में सहकारिता के माध्यम से जिला जालोर व सिरोही के पशुपालक दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक, सामाजिक व नैतिक उत्थान व विकास के उद्देश्य से दिनोंक 27.03.1986 को संस्थापित यह सहकारी डेयरी पिछले सवा दो दशक से सेवायमान व जिले की सफलतम एवम् प्रगतिशील औद्योगिक संस्था स्वरूप शोभायमान है । राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर से सम्बद्ध इस संस्था का मुख्यालय रानीवाड़ा है तथा कार्यक्षेत्र जिला जालोर व सिरोही । "सरस" ब्राण्ड से प्रचलित रानीवाड़ा डेयरी का दुग्ध, रानीवाड़ा डेयरी का घी,

मक्खन, पनीर, चीज, श्रीखण्ड, दही, छाछ, दुग्ध पाउडर आदि विख्यात दुग्ध उत्पाद इसी फेडरेशन व सम्बद्ध संस्थाओं के उत्पाद हैं ।

विश्वविख्यात अमूल पद्धति का अनुचर जालोर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अपने दर्शन व उद्देश्य से कभी विमुख नहीं हुआ । संघ ने पूर्ण समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है तथा अपनी सदस्य समितियों को पूर्ण पोषित कर उनकी पूर्ण क्षमता से रूबरू कराने में मदद की है । महिला स्वावलंबन, पशु विकास तथा ईलेक्ट्रानिकीकरण के लिए विशेष कार्य किया गया है । महिला समितियों का गठन कर समितियों की प्रबन्ध कारिणी में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की गई है । समितियों के साक्षर सचिव कम्प्यूटरीकृत स्वचालित दुग्ध संकलन युनिटों के कम्प्यूटर्स पर गणना कर रहे हैं व ईलेक्ट्रानिक दुग्ध जॉचकर्ता मशीन संचालित कर रहे हैं । वह दिन दूर नहीं जब ये ही साक्षर सचिव ईन्टरनेट पर संचार कर गर्वित अनुभव करेंगे ।

ग्रामीण क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को संगठित कर सहकारी समिति के माध्यम से दुग्ध क्रय एवम् शहरी बाजारों में विक्रय कर उचित मूल्य उपलब्ध करवाकर उनका आर्थिक, सामाजिक व नैतिक उत्थान ही इस संस्था का मूल उद्देश्य है । संस्था द्वारा वर्तमान में 550 पंजीकृत व प्रस्तावित समितियों से सम्बद्ध 30 हजार दुग्धदाता सदस्यों के माध्यम से 80 हजार तक दुग्ध संकलित किया जा चुका है । संकलित दुग्ध के निस्तारण के लिए रानीवाड़ा मुख्यालय पर स्थापित पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत रिशेप्शन डॉक, 01 लाख किग्रा भण्डारण क्षमता, 50 हजार किग्रा प्रोसेस क्षमता, 50 हजार लीटर पेकिंग क्षमता तथा 10 टन क्षमता का पाउडर संयंत्र स्थापित किया हुआ है । दुग्ध विपणन हेतु जिला जालौर व सिरोही के अतिरिक्त अहमदाबाद तक दुग्ध वितरण पथ गठित है जिनमें औसतन 25000 लीटर दुग्ध प्रतिदिन विपणन किया जा रहा है । पंजीकृत दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु 'सरस' सामूहिक आरोग्य बीमा योजनाएँ संचालित की जा रही हैं जिनमें जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवम् चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं । जिले वार सूचना तालिका संख्या 4.7 में अंकित है ।

तालिका संख्या 4.7

जिले वार संक्षिप्त सूचना

क्र.सं.	गतिविधियाँ	जिला जालौर	जिला सिरोही
01.	दुग्ध संकलन (किग्रा प्रतिदिन)	27000	8000
02.	दुग्ध विपणन (लीटर प्रतिदिन)	9000	5800
03.	कुल पंजीकृत समितियाँ (संख्या)	387	48
04.	कुल पंजीकृत महिला समितियाँ (संख्या)	79	01
05.	दुग्ध दाता पंजीकृत समितियाँ (संख्या)	198	62
06.	कुल संकलन केन्द्र (संख्या)	72	20
07.	दुग्धदाता सदस्य (संख्या)	15689	3965

अन्य दूध उत्पाद वस्तुओं का वर्षवार विवरण

तालिका संख्या 4.8

विवरण	वर्ग	2006.07	2007.08	2008.09	2009.10
क्षेत्र					नवंबर
क्षेत्र	क्षेत्र	441 ^३ 365	402 ^० 074	874 ^४ 406	165 ^९ 879
क्षेत्र	क्षेत्र	391 ^९ 273	509 ^९ 906	540 ^४ 420	630 ^९ 60
क्षेत्र	क्षेत्र	102 ^९ 382	97 ^९ 089	694 ^९ 115	66 ^९ 530
क्षेत्र	क्षेत्र	45 ^९ 132	78 ^९ 825	304 ^९ 452	451 ^९ 40
क्षेत्र	क्षेत्र	14717	13429	17461	23228
क्षेत्र	क्षेत्र	63 ^९ 20	273 ^९ 30	400 ^९ 80	116 ^९ 40
क्षेत्र	क्षेत्र	360	528	4440	1732
क्षेत्र	क्षेत्र	.	522	972	.
क्षेत्र	क्षेत्र	.	.	504	.
क्षेत्र	क्षेत्र	.	.	36	.
क्षेत्र	क्षेत्र	.	.	16775	1350
क्षेत्र	क्षेत्र	.	.	128	.
क्षेत्र	क्षेत्र	.	711	2164 ^९ 6	754 ^९ 8
क्षेत्र	क्षेत्र	.	95 ^९ 2	331 ^९ 4	.

जिले का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने के लिए मानव विकास को प्रभावित करने वाली मुख्य समस्याएं, उनके निवारण हेतु उपलब्ध संसाधन एवं आवश्यकता हेतु सुझाव तथा क्रिटिकल एरिया के चिन्हीकरण एवं उनके विकास हेतु रानीवाड़ा डेयरी से संबंधित मुख्य बिन्दुओं पर प्रस्ताव/सुझाव :

अ) जिले में दूध डेयरी की कार्ययोजना :

01. दूध संकलन के क्षेत्र में :

हालांकि संघ की दुग्ध संकलन मात्रा में विगत कुछ वर्षों से लगातार उतरोत्तर वृद्धि हो रही है फिर भी संघ का उद्देश्य है कि जिले में उत्पादित दूध की अधिकाधिक मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में गठित सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से सहकारिता के उद्देश्यों को पूर्ण करते हुये संकलित की जाकर क्षेत्र के दुग्ध उत्पादको को निजी डेयरियों/प्राइवेट वेण्डर/मावा भट्टा आदि के शोषण से मुक्त किया जा सके । उक्त हेतु संघ की योजना है कि सम्पूर्ण जिले में शेष रहे प्रत्येक गांव/ढाणी में दुग्ध संकलन केन्द्र/समितियों का गठन कर उनके माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकाधिक दुध की मात्रा संकलित की जावे इन्ही प्रयासों का नतीजा है कि गत वर्ष संघ द्वारा सर्वाधिक 80,000 लीटर दूध प्रतिदिन संकलित कर रिकार्ड कायम किया ।

दुग्ध उत्पादको के संघ/समिति के प्रति विश्वास में वृद्धि एवं पूर्ण पारदर्शिता तथा उनके दूध की वास्तविक कीमत प्रदान करने के उद्देश्य से संघ द्वारा जिले की लगभग 300 समितियों/केन्द्रों पर मिल्कोटेस्टर एवं लगभग 110 समितियों पर पूर्ण स्वचालित कम्प्युटीकृत दुग्ध संकलन ईकाई(ए.एम.सी.यु.) स्थापित किये जा चुके हैं तथा शीघ्र

ही शेष रही समस्त समितियों पर भी मिल्कोस्टेशन एवं मिल्कोटेस्टर स्थापित किये जायेगें, साथ ही संघ से अत्यधिक दूरी पर स्थित बड़ी दुग्ध समितियां जिनकी दुग्ध संकलन मात्रा अधिक है तथा जंहा से दग्ध परिवहन मे अधिक समय लगता है ऐसी 04 समितियों को चिन्हीकृत कर उन पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने के प्रस्ताव भिजवा दिये गये है उक्त समितियों के समीपवर्ती समितियों का दुग्ध भी इन्ही समितियों पर संकलित कर ठण्डा करने के पश्चात संघ द्वारा टेंकर के माध्यम से परिवहन किया जायेगा जिससे दूध की गुणवत्ता मे आशातीत सुधार होगा ।

02. दुग्ध विपणन के क्षेत्र मे :

संघ क्षेत्र मे अधिक बड़े शहर /कस्बों के अभाव मे संघ की दुग्ध विपणन मात्रा मे आशातीत वृद्धि नहीं हो पा रही है अतः संघ की कार्य योजना है कि संघ के विपणन नेटवर्क को जिले के छोटे कस्बों/ग्रामो से जोड़ा जावे तथा तथा वर्तमान विपणन नेटवर्क से जुड़े शहरों/कस्बों मे विपणन मात्रा मे वृद्धि की जावे इस हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों मे अधिकाधिक बुथ एजेण्ट नियुक्त कर जिले की आम जनता को उचित दर पर शुद्ध दूध एवं दूध पदार्थ उपलब्ध करवाये जा सके इसी कड़ी मे श्रीमान् जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर एवं जिले की विभिन्न तहसील कार्यालय परिसरों के साथ क्षेत्र के कस्बों मे उचित स्थान पर सरस पार्लर स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है जंहा उपभोक्ताओं को सरस उत्पाद की सम्पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध हो सके । संघ द्वारा वर्तमान मे अनेक प्रकार का पास्चुराईज्ड सरस दूध एवं सरस घी, पनीर एवं मख्खन तैयार कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है, शीघ्र ही दही, ठेलेवर्ड मिल्क, लसी ईत्यादि सरस दूध उत्पाद भी तैयार कर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दूध/घी बुथों/पार्लरों के माध्यम से उचित दर पर उपलब्ध करवाने की योजना है ।

03. संयन्त्र विकास :

संघ के रानीवाड़ा स्थित 100000 लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेसिंग क्षमता के मुख्य डेयरी संयन्त्र के साथ ही उच्च क्षमता का पाउडर प्लाण्ट स्थापित है । मुख्य डेयरी संयन्त्र के साथ वर्तमान मे जालोर एवं साचौर मे दुग्ध अवशीतन केन्द्र संचालित है जिनके माध्यम से दुग्ध संकलित एवं ठण्डा कर मुख्य संयन्त्र रानीवाड़ा लाया जाता है । दुग्ध संकलन मात्रा मे उतरोत्तर वृद्धि के परिणाम स्वरूप संघ के मुख्य संयन्त्र की क्षमता मे वृद्धि करना/नवीन मशीनों की स्थापना प्रस्तावित है, इसी के साथ दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की क्षमता मे भी वृद्धि करने की योजना है जिससे क्षमता के साथ-साथ दूध की गुणवत्ता मे भी और अधिक सुधार लाया जा सके । उक्त के अतिरिक्त डेयरी विकास हेतु विभिन्न परियोजनाएँ प्रस्तावित है ।

ब) डेयरी विकास मे आने वाली समस्याएं एवं सुझाव :

विदित है कि हर अच्छे कार्य मे रुकावटे एवं बाधाये जरूर आती है इसी तरह संघ के सर्वांगीण विकास मे भी अनेक प्रकार की बाधाये/समस्याये उत्पन्न हो रही है जिनमे मुख्यतः निम्न प्रकार है :

01. बनास डेयरी :

संघ के समीपवर्ती गुजरात राज्य की बनास डेयरी (बनास कांटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. पालनपुर) द्वारा संघ कार्यक्षेत्र मे लगभग 30 दुग्ध समितियों/संकलन केन्द्रो की स्थापना कर रू. 320 प्रति किलो फैंट पैदहसम गपेद्ध क्रय दर प्रणाली द्वारा अवेध रूप से दुग्ध क्रय किया जा रहा है जिससे कड़ी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की जाकर संघ का दुग्ध संकलन प्रभावित किया जा रहा है ।

सुझाव : संघ कार्यक्षेत्र से गुजरात राज्य की बनास डेयरी (बनास कांटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. पालनपुर) द्वारा किये जा रहे दुग्ध संकलन को रोकने / बंद करने हेतु बार-बार निवेदन किया जाता रहा है राज्य सरकार से उक्त हेतु उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

02. मावा भट्टे :

किसी भी दुग्ध संघ का भविष्य पूर्णतः उसकी दुग्ध संकलन मात्रा पर निर्भर करता है इस संघ में हांलाकि दुग्ध संकलन सदैव ही औसतन ठीक रहा है परन्तु गत कुछ वर्षों से जिले के लगभग प्रत्येक गांव में दूसरे राज्यों से आये व्यक्तियों द्वारा अवेध मावा भट्टे संचालित कर अवेध मावा उत्पादन का कारोबार चलाकर संघ की दुग्ध संकलन मात्रा को प्रभावित किया जा रहा है जिन्हें बंद करने हेतु समय-समय पर इस कार्यालय से जिला प्रशासन को निवेदन किया जाता रहा है इसके बावजूद ये लोग लम्बे अरसे से जमे हुये हैं तथा दिन बदिन अपना कारोबार/नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं जिससे संघ की दुग्ध संकलन मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

सुझाव : भट्टा संचालको के पास किसी प्रकार का लाईसेंस/प्रपत्र नहीं है जिससे इनके द्वारा उत्पादित मावे पर इनके द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार को किसी प्रकार का कर/ राजस्व नहीं दिया जा रहा है जिससे सरकार को लाखों रू. की राजस्व की हानि हो रही है तथा इनके द्वारा उत्पादित मावा देश के अहमदाबाद, मुम्बई जैसे महानगरो में अवेध रूप से रात को सप्लाई किया जाता है । मावा भट्टो द्वारा ईधन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी (के गट्टे) वनो की अवेध कटाई कर रातों रात गाड़ियो द्वारा क्षेत्र /समीपवर्ती गुजरात राज्य से इन तक पहुंच जाती है जिससे क्षेत्र के वनो की अवेध कटाई के साथ ही पर्यावरण संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । कई मावा भट्टा संचालको द्वारा मावा बनाने में ईधन के रूप में घरेलु एलपीजी के अवेध सिलेण्डर काम में लिये जाने से क्षेत्र में घरेलु उपयोग हेतु गैस की किल्लत कभी भी देखी जा सकती है । इनके भट्टो पर यदि छापे मारे जावे तो ऐसे कई अवेध सिलेण्डर बरामद हो सकते हैं । मावा भट्टा संचालको द्वारा मावा बनाने हेतु क्षेत्र के भोले एवं गरीब दुग्ध उत्पादको से अपनी मानमानी दर पर दूध क्रय किया जाकर उत्पादित मावा मुम्बई अहमदाबाद जैसे महानगरों में उच्च दर पर विक्रय किया जाता है । जिले में उत्पादित सम्पूर्ण दूध में से काफी मात्रा में मावा उत्पादन में खपत होने से सहकारी संघ के दुग्ध संकलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जबकि इस संघ द्वारा सहकारिता के आधार पर दुग्ध उत्पादको से गांवों में स्थित दुग्ध समितियों/संकलन केन्द्रों के माध्यम से उच्च दर पर दुग्ध क्रय कर उचित मूल्य पर दूध एवं दूध पदार्थ आम जन को सप्लाई किये जाते हैं । जिले में चल रहे इन अवेध मावा भट्टों को बंद कराने हेतु संबधित समस्त को शीघ्र एवं कड़ी कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शन दिलवाने का निवेदन जिला प्रशासन से किया जा चुका है कार्यवाही अपेक्षित हैं ।

03. निजी डेयरियां :

वर्तमान में संघ के कार्यक्षेत्र में स्थित लगभग 20 निजी डेयरियों द्वारा मनमानी दर पर 300 से 310 प्रति किलो फ़ैट पैपदहसम गपेद्ध की दर पर दुग्ध क्रय किया जा रहा है जिससे भी संघ की दुग्ध संकलन मात्रा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

सुझाव : विदित हो कि निजी डेयरियों द्वारा संकलित किये दूध एवं दूध उत्पाद पर राज्य सरकार को किसी प्रकार का मण्डी टेक्स/राजस्व नहीं दिया जाता है जिससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लाखों रू. के राजस्व की हानि होती है । यदि उक्त दूध मात्रा सहकारिता के माध्यम से संघ को प्राप्त होती है तो संघ द्वारा घी आदि पर दिये जाने वाले मण्डी कर, आयकर, बिक्री कर के रूप में प्रदान किये जा रहे कर की राशि में इजाफा होकर राज्य सरकार की आय में वृद्धि होगी ।

स) पशु स्वास्थ्य हेतु डेयरी द्वारा संचालित कार्यक्रम :

चूंकि संघ का भविष्य संघ द्वारा संकलित की जाने वाली दूध मात्रा पर ही निर्भर है अतः संघ द्वारा क्षेत्र के दुग्ध उत्पादको के दूधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादन मात्रा में वृद्धि हेतु विभिन्न तकनीकी आदान गतिविधियां एवं सुविधायें प्रदान की जा रही हैं, संघ द्वारा समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादको को सरस संतुलित पशु आहार उचित दर पर उपलब्ध करवाया जाता है । पशुओं में विभिन्न रोगों की रोकथाम उनकी पाचक क्षमता में वृद्धि एवं स्वस्थ रखने हेतु वैट फैन, युरिया मोलेसस ब्लॉक, मिनरल मिक्सचर, गौमिक्स, कालसागर जैसी अनेक ओषधियां/पैलेट्स पशुपालको को उपलब्ध करवाई जाती हैं । विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथान हेतु संघ द्वारा टीके उपलब्ध करवाकर वृहद स्तर पर टीकाकरण करवाया जाता है । दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से संघ द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत समितियों को अच्छी नस्ल के भैंसा सांड उपलब्ध करवाये जाते हैं ।

4.4 उद्योग

जिले का बढ़ता ग्रेनाईट उद्योग :- जिले में इस समय ग्रेनाईट उद्योग बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए इसे ग्रेनाईट नगरी के नाम से जाना जाने लगा है। वर्ष 1980 से प्रारम्भ हुए इस उद्योग में वर्तमान में जिले के सात औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग चार सौ इकाईया ग्रेनाईट टाइल्स एवं स्लेब्स उत्पादन का कार्य कर रही हैं। इन ग्रेनाईट उद्योगों में 125.81 करोड का विनियोजन हो रखा है तथा लगभग 5,000 मानव विकास को रोजगार से जोडा गया है। जिले के चार-पाच बड़े उद्योगों द्वारा ग्रेनाईट टाइल्स एवं स्लेब का देश के बाहर निर्यात भी किया जाता है। इस जिले में कार्यरत उद्योग एवं मानव रोजगार का विवरण तालिका संख्या 4.9 के अनुसार है।

तालिका संख्या 4.9

कार्यरत उद्योग एवं मानव रोजगार का विवरण

क्र० सं०	वर्ष	कार्यरत इकाईयो की संख्या	मालिकाना		रोजगार			पुंजी निवेश करोडो में
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	योग	
1	1980	1208	1087	221	3428	512	3940	044.16
2	1990	2012	1622	390	7320	768	8106	082.65
3.	2000	3097	2552	545	11402	1065	12467	158.44

4	मार्च 2009 तक	4130	3380	750	16310	1550	17860	211.25
	योग :-	4130	3380	750	16310	1550	17860	211.25

स्रोत :- जिला उद्योग केन्द्र

इस उद्योग के पनपने के पीछे सबसे बड़ा कारण ग्रेनाईट में कच्चे माल के रूप में पत्थर/ब्लॉक्स का प्राप्त होना है। इसके अलावा यहाँ के स्थानीय इंजीनियरो द्वारा इससे संबंधित मशीनरी का निर्माण किया जाना है जिससे मशीनरी सुलभता एवं सस्ती दर से प्राप्त होती है। तीसरा मुख्य कारण इस पर लगने वाली जनशक्ति आसानी से स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं। इसलिए इसके भविष्य में और अधिक बढ़ने की संभावना है। आगामी पन्द्रह वर्षों में जिले में लगभग 2,000 उद्योग पनप सकेंगे एवं लगभग 20-22 हजार श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। जिले में कार्यरत उद्योग एवं रोजगार सृजन का विवरण तालिका संख्या 4.10 एवं 4.11 में दर्ज है।

तालिका संख्या 4.10

वृहद एवं मध्यम उद्योग

क्र० सं०	उद्योग का नाम व पता	उत्पादन का नाम	कार्यरत श्रमिकों की संख्या	पूँजी विनियोजन
1.	जालोर सिरोही दुग्ध उत्पादक संस्था(डेयरी) रानीवाडा	दुग्ध, पाउडर, घी, बटर	89	4.55 करोड
2.	श्री राम ग्रेनाईट्स बिशनगढ रोड जालोर	ग्रेनाईट स्लेब एवं टाइल्स	31	7.99 करोड

स्रोत :- जिला उद्योग केन्द्र

तालिका संख्या 4.11

लघु एवं अन्य उद्योग (पंचायत समितिवार)

क्र० सं०	पंचायत समिति	चर्म कार्य से संबंधित	वन आधारित	कृषि आधारित	इंजि० एवं लोह आधारित	खनिज एवं ग्रेनाईट	हाथकरघा उद्योग	विविध	कुल
1	आहोर	10	85	36	68	07	05	77	
2	भीनमाल	1260	69	43	70	10	—	95	
3	सायला	55	42	42	54	60	—	72	
4	जालोर	358	151	50	160	320	105	156	
5	जसवन्तपुरा	10	22	13	25	00	—	12	
6	रानीवाडा	37	33	20	36	05	48	45	
7	सांचौर	78	78	28	55	10	92	76	

योग :-	1808	480	232	415	412	250	533	4130
--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

स्त्रोत :- जिला उद्योग केन्द्र

आगामी व्यूह रचना :-

11 वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि (2009-10 से 2011-2012) के दौरान जिला उद्योग केन्द्र अपनी योजनाओं के माध्यम से आजिविका के अवसर प्रदान करेगा। इसका विवरण नीचे दी गई सारिणी में वर्णित है।

तालिका संख्या 4.12

क्र० सं०	योजना	आजिविका के संभावित अवसर
1.	गृह उद्योग योजना	205
2.	लघु उद्योग के माध्यम से	525
3.	चर्म प्रशिक्षण	45
4.	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	75
5.	पीएमईजीपी	200

स्त्रोत :- जिला उद्योग केन्द्र,

नोट :-

1. जिले में 5 ग्रेनाइट इकाईयों द्वारा निर्यात किया जाता है।
2. उक्त इकाईयों में लगभग 10 प्रतिशत इकाईयों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भागीदारी है।

जिले में औद्योगिक संभावनाओं की दृष्टि से उद्योग पनपने के अच्छे आसार नजर आते हैं। जिले में पक्की सड़कें जो कि विभिन्न जिला मुख्यालयों से जुड़ती हुई समस्त देश में फैली हुई हैं। सड़कों के साथ-साथ जिला रेल लाइन से भी जुड़ा हुआ है, जिससे कच्चा माल लाने और पक्का माल ले जाने हेतु समुचित रूप से उपयोगी है। जिले को भौगोलिक दृष्टि से भूमि, वन, वर्षा, फसलें, एवं उपलब्ध खनिज, कच्चा माल एवं जनशक्ति को देखते हुए निम्न प्रकार के उद्योग लगाने की प्रबल संभावनाएं प्रतीत होती हैं :-

1. ग्रेनाइट एवं इस पर आधारित उद्योग,
2. खनिज एवं मिट्टी आधारित उद्योग,
3. कृषि आधारित उद्योग- जिले में तारा मीरा, अरंडी, ईसबगोल, टमाटर, सरसों, दाल आदि की फसलें अच्छी होने के कारण इसके आधारित उद्योग पनपने की प्रबल संभावना है।
4. वन आधारित उद्योग,
5. इंजिनियरिंग एवं लौह आधारित उद्योग,
6. बुनाई एवं हाथ करघा उद्योग,

7. चर्म आधारित एवं अन्य दस्तकारी उद्योग

खनिज

वर्तमान में क्षेत्र में अधात्विक खनिज एवम् बिल्डिंग डेकोरेटिव, बिल्डिंग स्टोन की उपलब्धता बहुतया में है। इनमें से कुछ खनिजों का दोहन रियासत काल से ही किया जाता रहा है जैसे जिप्सम, चिनाई पत्थर। खनिज नियमावली के अनुसार क्षेत्र में निम्न प्रधान एवम् अप्रधान खनिजों का दोहन किया जाता है :-

क्र. खनिज का विवरण

सं. नाम

- 1 **जिप्सम** जिप्सम की उपलब्धता, सांचौर, आहोर, तहसील में विभिन्न स्थानों में चिन्हित की गई है इनमें कंवला, सांरवा, चितलवाना, हेमागुडा, हालीभाव, चिचावा, सायर का कोसिता व सालटक क्षेत्र मुख्य है।
- 2 **फलोस्पार** फलोस्पार परपल व्हाईट के रंग में उपलब्ध है, इसके विभिन्न ग्रेड में भण्डार तहसील रानीवाडा में जालेरा खुर्द, तावीदर, करडा, लाखावास में उपलब्ध है और निम्न ग्रेड का खनिज सीमेन्ट उद्योग में काम आता है। उच्च ग्रेड का आर्यन इण्डस्ट्रीज में काम आता है व पेन्ट सिरेमिक, मेडिकल, केमिकल उद्योगों के उपयोग में लिया जाता है।
- 3 **जेस्पार (ऐमरी स्टोन)** यह काला रंग में पाया जाता है इसकी हार्डनेश उच्च होने से ऐब्रेशिव इण्डस्ट्रीज में उपयोग में आता है इसका भण्डार मुख्यतः आहोर तहसील में डोडीयाली, आलावा आदि स्थानों पर स्थित है।
- 4 **फैल्सपार** फैल्सपार हल्के भूरे डिपोजिट के रूप में मिलता है और फैल्सपार ब्राउन रंग में बिखरे हुए पट्टिका के रूप में मिलता है। यह मुख्यतः आहोर तहसील के भाद्राजून क्षेत्र में पाया जाता है।

प्रधान खनिज

- 1 **ग्रेनाईट** जिला जालोर एवम् सिवाना तहसील बाडमेर में बहुतायत क्षेत्र में खनिज ग्रेनाईट चट्टाने पहाडी श्रृखला/पहाडी के रूप में अवस्थित है। जैसे धवला, लेटा, जालोर, मायलावास, भेटाला, कंवला, तरवाडा, खाम्बी, नौसरा, सुगालिया जोधा, कोराणा, बाला, तवाब, बोरटा, नासौली, रानीवाडा तथा

सिवाना तहसील में मोकलसर, राखी, फूलन, देवडा, पीपलोन आदि स्थानों पर रोजीपिक, ब्लेक, ऐन्गलो ग्रे, लाईट पिक, लाईट स्केर्टड रेडिस (चिमा-99), सिन्दुरी, सनराईज येलो, कॉपर सिल्क, डेजर्ट पिक, बाला ग्रे/बाला फलोवर, ईम्पिरियल पिक, गोल्डन येलो, टाईगर येलो, मोकल ग्रेन, नगीना, ब्राउन मेरी गोल्ड, मेरी वुड रंग में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं। इसका स्लेब्स/टाईल्स कटिंग/ पॉलिस इण्डस्ट्रीज से तैयार किया जाता है जिसका अधिकतम उत्पादन विभिन्न देशों में तथा देश के कई भागों में बेचान किया जाता है।

- 3 **रॉयलाईट** जालोर तहसील, आहोर तहसील, रानीवाडा तहसील के कुछ स्थानों पर छोटे-छोटे भण्डार उपलब्ध है जो टाईल्स व क्रेसर ग्रेट के उपयोग में आता है।
- 4 **चिनाई पत्थर** जिले में चिनाई पत्थर फ्रेक्चर्ड व निम्न स्तर के ग्रेनाईट/रॉयलाईट चट्टानों का विभिन्न स्थानों पर प्रचुर मात्रा में उपलब्धता पर इसका उपयोग चिनाई पत्थर के रूप में होता है।

खनन पट्टा संख्या व क्षेत्रफल

1. जिले में खनन पट्टों की संख्या — प्रधान खनिज-5, अप्रधान खनिज-532
2. जिले में खनन के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल — 2140 हैक्टर
3. जिले में खनिज वार स्वीकृत खनन पट्टें — 537

तालिका संख्या 4.13

क्र.सं.	खनिज	खनन पट्टों की संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1	फलोस्फार	4	1075
2	जिप्सम	1	300
3	ग्रेनाईट	354	593
4	चुनाई पत्थर	176	170
5	रॉयलाईट	2	2
	कुल	537	2140

तहसीलवार खनिज पट्टे एवम् श्रमिकों की संख्या

तालिका संख्या 4.14

क्र.सं.	तहसील	धारित खनन पट्टे					
		अप्रधान खनिज			प्रधान खनिज		
		ग्रेनाईट	मैसेनरी स्टोन	श्रमिकों की संख्या	जिप्सम	फलोस्फार	श्रमिकों की संख्या
1	जालोर	70	35	550	0	0	0
2	आहोर	116	50	750	0	0	0
3	भीनमाल	29	19	250	0	0	0
4	रानीवाडा	13	43	260	0	4	0
5	सांचौर	1	4	25	1	0	0
	योग	229	151	1835	1	4	200

खनिजवार उत्पादन एवम् आय (वर्ष 2008-09)

क्र.सं.	खनिज	उत्पादन	आय (लाखों में)
1	जिप्सम	70,000	29.9
2	फलोस्फार	—	.33
3	ग्रेनाईट	102250	446.53
4	मैसेनरी स्टोन	7220	174.3
5	जेस्फार	7592	24.55

वर्षवार आय

क्र.सं.	वर्ष	आय लक्ष्य	आय प्राप्ति	प्रतिशत
1	2007-08	550	646	117
2	2008-09	900	987	109
3	2009-10 (अगस्त , 09 तक)	1200	440	37

भविष्य की सम्भावनाएं :- इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में खनिज ग्रेनाईट की प्रचुर सम्भावना है। परन्तु वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश 28-5-2008 से खनिज ग्रेनाईट के खनन पट्टों का आवंटन ग्रेनाईट नीति 2002 के अन्तर्गत दिया जाना है। उक्त नीति के अन्तर्गत विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाकर खनन पट्टों आवंटन पश्चात् राजस्व आय की प्राप्ति होगी एवम् उक्त जिले का विकास होगा एवम् प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रोजगार के साधनों में वृद्धि होने से श्रमिकों का जीवन स्तर सुधरेगा एवम् आर्थिक समृद्धि

आयेगी। चूंकि वर्तमान में जिला जालोर में नैशनल हाईवे एवम् रेल परिवहन का अभाव है जो निकट भविष्य में सड़क निर्माण एवम् रेल ट्रेक बिछाने हेतु खनिज मैसेनरी स्टोन के दोहन की सम्भावनाएं है। वर्तमान में विभाग की अथवा राज्य सरकार की इस कार्यालय के अधिकारिता क्षेत्र में कोई कार्य योजना प्रस्तावित नहीं हैं।

4.5 कृषि एवं उद्यानिकी

जालोर जिले में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में जिले की 77 प्रतिशत जनसंख्या जीवनयापन करती है। जिले में भू-उपयोग एवं भू-जोत वर्ष 2008-09 का विवरण तालिका संख्या 4.15 के अनुसार है।

तालिका संख्या 4.15

भू-उपयोग सम्पूर्ण जिला वर्ष 2008-09

क्र.स.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	कुल भौगोलिक क्षेत्र	1056602
2	वन	22063
3	अकृषि भूमि	170633
4	पडत भूमि	176719
5	कृषि भूमि	863906
6	वास्तविक बोया गया क्षेत्र	652354
7	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र	160481
8	सिंचित क्षेत्रफल	290809

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1056602 हैक्टर है जिसमें से कृषि योग्य भूमि 863906 हैक्टर है। इसमें से सिंचित क्षेत्रफल 290809 हैक्टर है जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 33.66 प्रतिशत है। शेष भूमि में वर्षा आधारित खेती की जाती है। सिंचित क्षेत्र में अधिकांश कुएं एवं ट्यूबवेल है।

जिले में खरीफ में औसतन 6 लाख हैक्टर में एवं रबी में पानी की उपलब्धता के अनुसार 2 से 2.5 लाख हैक्टर में फसले बोयी जाती है। खरीफ में मुख्यतः बाजरा ,ग्वार ,मूंग ,मोठ ,अरण्डी तथा रबी में सरसों ,गेंहू ,जीरा ,इसबगोल की फसल बोयी जाती है।

तालिका संख्या 4.16

जमीपसूपेम संदक दक न्जपसप्रंजपवद जंजपेजपबे ;लमंत 2008.09द्व ;।तमं पद र्द्व

जमीपस	ळमवहतंची पबंस तंमं	थ्वतमेज ।तमं	संदक न्दकमत छवद. हतपसण नेम	बनसजप अंइसम जूम	चमतउंद मदज चेंजनतमे	संदक नदकमत उपेबमस संदमवने जतमम बतवचे दक हतवअमे	बनततम दज थंससवू	व्जीमत थंससवू	छमज वूद तंमं	ळतवे बतवच मक तंमं
श्रंसवतम	126303	2470	5469	7656	6714	20	12038	13146	64935	75773
लसं	98427	607	3402	1124	3840	0	4708	7214	71665	96037
पीवतम	185996	3275	9299	4199	8305	0	15086	17355	116361	123519
ठीपदउंस	164864	11083	6101	3915	8559	0	17340	16623	81356	104995
ठंहवतं	81189	68	2838	525	2512	0	5592	3692	62279	87740
त्दपूतं	97986	4060	3514	1024	3487	7	7928	8270	58986	73841
दबीवत	301637	500	10199	16363	14015	0	23511	24216	196772	250930
ज्वजंस	1056602	22063	40822	34806	47432	27	86203	90516	652354	812835

वनतबम दृ त्मअमदनम कमचज श्रंसवतम

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008-09 में जिले की सांचौर तहसील में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र 196772 हैक्टर है। सांचौर क्षेत्र में वर्तमान में नर्मदा नहर में पानी की आवक होने से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, इससे इस क्षेत्र में उद्यानिकी फसलें सब्जी उत्पादन फल बगीचों की स्थापना तथा अन्य नगदी फसलों की खेती की सम्भावना बढ़ी है। सांचौर व आहोर के कुछ क्षेत्र नहरी है, शेष जिले में वर्षा आधारित अथवा कुएं, ट्यूबवेल से सिंचाई कर फसलें उगाई जाती हैं। सांचौर तहसील में ही सर्वाधिक कल्टीवेबल वेस्ट भूमि रेत के धोरो के रूप में है। फव्वारा व ड्रिप सिंचाई अपनाते से इन पर खेती की सम्भावना बनी है।

तालिका संख्या 4.17

जिले की विभिन्न प्रकार की मृदाओं का सामान्य विवरण

ठसवबा	ठसंबा वपस		दकल वपस		दकप सवउ		व्जीमते		ज्वजंस
	।तमं	:	।तमं	:	।तमं	:	।तमं	:	।तमं व्द
वीवतम	0	0	5871	3 ^प 23	180125	96 ^प 8	0 ^प 00	0	185996
ठीपदउंस	46162	28	21432	13	95621	58	1649	1	164864
श्रंसवतम	151156	12	13893	11	92201	73	5052	4	126303
श्रूंदजचनतं	26792	33	5683	7	43842	54	4871	6	81189
तंदपूतं	0	0	15678	16	61715	62	21557	22	97986
दबीवतम	0	0	39239	13	108661	36	153937	51	301837
लंसं	6434	6 ^प 25	5300	5 ^प 4	82543	83 ^प 9	4150	4 ^प 2	98427
ज्वजंस	94545	8 ^प 9	107096	10 ^प 1	663745	62 ^प 8	191216	18 ^प 1	1056602

वनतबमे . व्द श्रंसवतम 2007.08

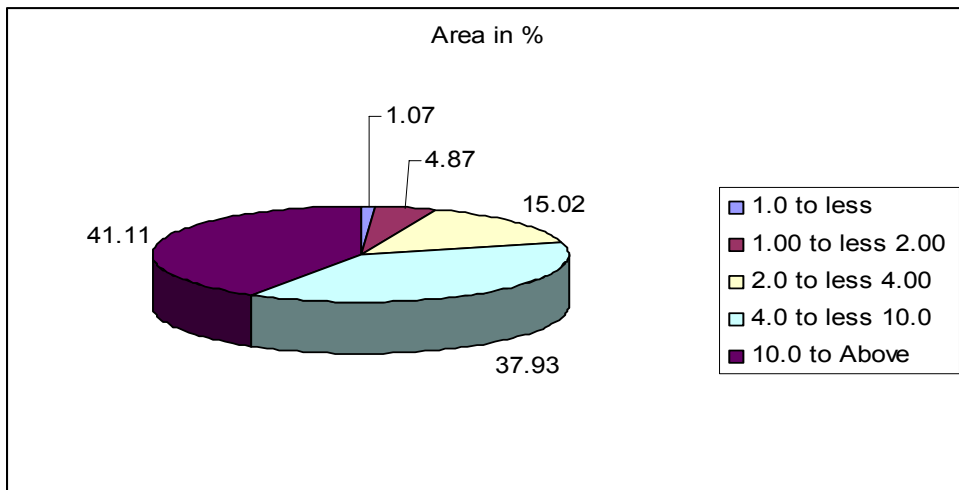
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले में मुख्यतः बलुई दोमट एवं बलुई मिट्टी है। जिनकी प्रतिशत क्रमशः 62.8 तथा 10.1 है। जिले की मिट्टी में क्षारीयता व लवणीयता की समस्या है। जो कृषि प्रबन्धन के लिए चुनौती है। क्षारीय भूमि सुधार के लिए जिप्सम व ढ़ेचा पर अनुदान देकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कृषि जोत का आकार

उपर्युक्त तालिका में दर्शाई गई कृषि जोत की कुल संख्या 150343 में से 48006 जोत (31.93 प्रतिशत) का आकार 4 से 10 है। यद्यपि 10 अधिक आकार प्रतिशत 13.57 सर्वाधिक क्षेत्र प्रतिशत) इसी के तहत है। अधिकतर से 10 हैक्टर व श्रेणी के चित्र संख्या 4.

क्र.सं.	कृषि जोत का आकार (हैक्टर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टर)	कुल जोत संख्या	जोत प्रतिशत	क्षेत्र प्रतिशत
1	1.00 जव समे	14015	8550	27	1.07
2	1.00 जव समे 2.00	25954	39003	62	4.87
3	2.00 जव समे 4.00	41976	120259	99	15.02
4	4.00 जव समे 10.00	48006	303599	43	37.93
5	10.00 जव इवअम	20392	329097	05	41.11
	ज्वजंस	150343	800510	36	100

10 हैक्टर है में से 37.93 जोत श्रेणी में हैक्टर से की जोत का है परन्तु (41.11 आकार जोत इस प्रकार कृषक क्रमशः 4 2 से 4 हैक्टर अन्तर्गत है।

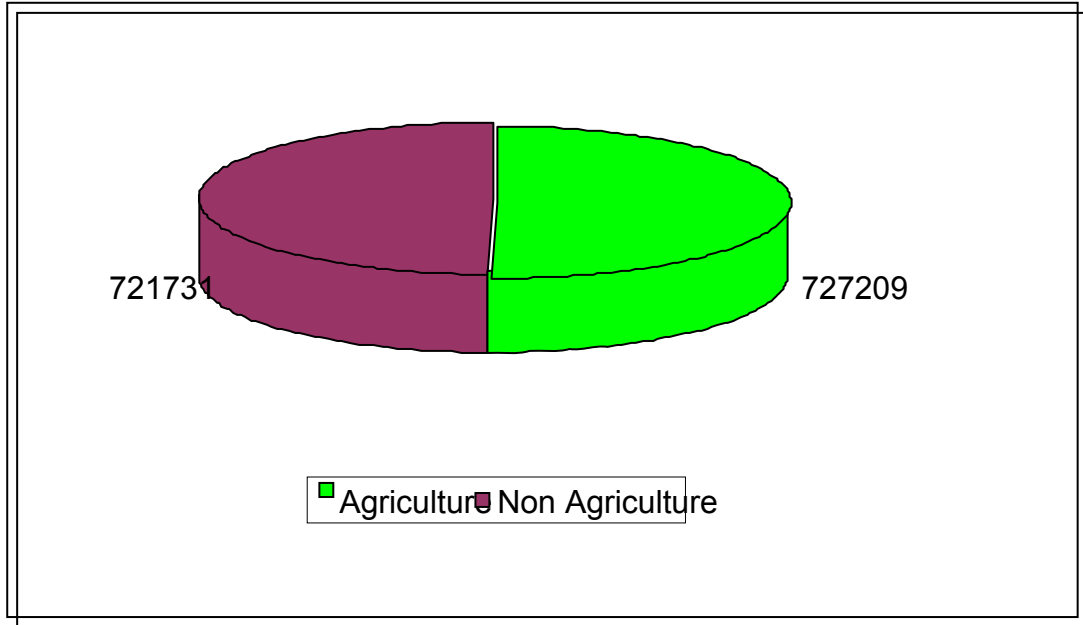


जिले में कृषि मजदूरों व अकृषि मजदूरों का विवरण

वर्ष	छात्रों की संख्या	व्यवसायिक मजदूरों की संख्या	कुल मजदूरों की संख्या	कुल मजदूरों की संख्या				अकृषि मजदूरों की संख्या					
				कृषि मजदूरों की संख्या		अकृषि मजदूरों की संख्या		कृषि मजदूरों की संख्या		अकृषि मजदूरों की संख्या			
				कुल	पुरुष	कुल	पुरुष	कुल	पुरुष	कुल	पुरुष		
2001													

		बमदेने जवजंस												
1	पीवतम	207961	41 ^प 52	102790	105171	49065	42096	53725	63075	40031	24009	छ।	छ।	
2	ठीपदउंस	221546	35 ^प 11	111830	109716	52382	36184	59448	73532	36639	21150	छ।	छ।	
3	शंसवतम	219381	39 ^प 22	111816	107565	53232	27215	58584	80350	45130	21323	छ।	छ।	
4	श्रूदचनतं	130895	31 ^प 13	66774	64121	34597	33785	32177	30336	13828	13201	छ।	छ।	
5	त्दपूतं	163349	36 ^प 84	84512	78837	41741	36963	42771	41874	31736	23246	छ।	छ।	
6	दबीवतम	368004	36 ^प 24	190181	177823	130998	11684	59183	60977	67722	16190	छ।	छ।	
7	लंसं	137804	32 ^प 30	69977	67827	37445	34660	32532	33167	26256	7680	छ।	छ।	
	ज्वजंस	144894	36 ^प 05	737880	711060	399460	32774	33842	38331	26135	126799	छ।	छ।	
		0					9	0	1	6				

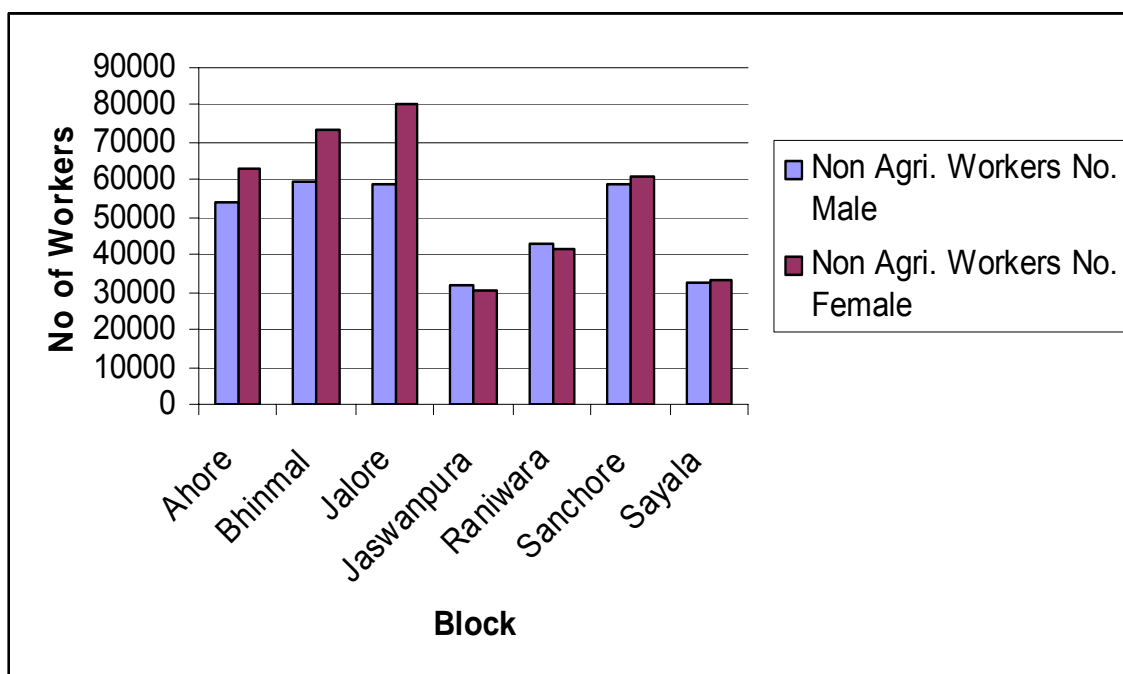
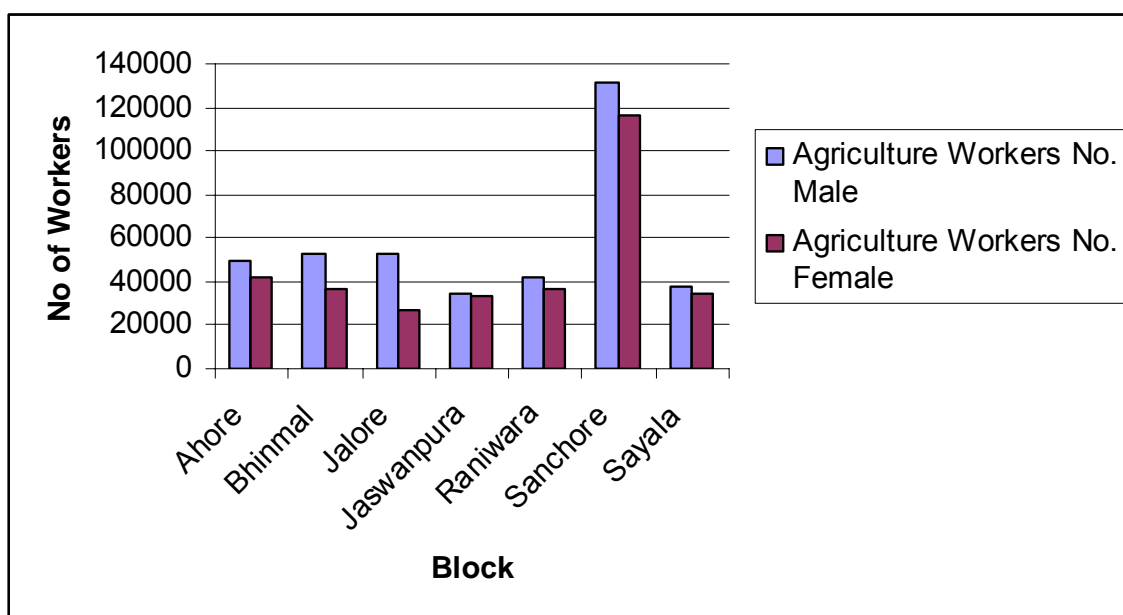
वनतबमे . त्द शंसवतम 2007.08



चित्र संख्या 4.2.2

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि जिले में कृषि एवं अकृषि मजदूरों की संख्या बराबर है। अकृषि कार्य के मजदूर जिले में पहाड़ीयों से पत्थर तोड़ने एवं ग्रेनाईट फेक्ट्रीयों में अधिकतर कार्यरत हैं। जिले में सर्वाधिक मजदूरों की संख्या सांचौर तहसील में है।

मजदूरों का वर्गीकरण



उपर्युक्त ग्राफ में कृषि व अकृषि कार्य में कार्यरत मजदूरों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाई गई है। ग्राफ से स्पष्ट है कि कृषि कार्य करने वाले सर्वाधिक मजदूर सांचौर में हैं तथा अकृषि कार्य करने वाले सर्वाधिक मजदूर जालौर में हैं। लिंगानुपात के हिसाब से सभी तहसीलों में कृषि कार्य करने वाले मजदूरों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। जबकि अकृषि कार्य करने वाले मजदूरों में स्थिति लगभग उलटी है यानि रानीवाडा व जसवंतपुरा को छोडकर शेष तहसीलों में पुरुष मजदूरों की संख्या महिला मजदूरों की तुलना में कम है।

कृषि एवं उद्यानिकी के कार्यक्रम –

जिले में मानसूनी वर्षा सालदर साल कम होती जा रही है ,भूमिगत जल का स्तर घटता जा रहा है एवं जल की गुणवत्ता सामान्य से लवणीयता एवं क्षारीयता की ओर बढ़ता जा रहा है ,बिजली आपूर्ति कम एवं समय

पर नही मिलती है ,तामकम की अधिकता के कारण फसलों की वानस्पतिक वृद्धि का समय कम होता जा रहा है जिसके फलस्वरूप फसलों का उत्पादन गिरता जा रहा है। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर कृषि के क्षेत्र में जोन मुख्यालय होने के कारण संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड का मुख्यालय है ,इसके अतिरिक्त उप निदेशक कृषि ,सहायक निदेशक कृषि जि.प. जालोर ,सहायक निदेशक कृषि भीनमाल एवं सहायक निदेशक उद्यान जालोर व मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जालोर आदि कार्यालयों के साथ कृषि अनुसंधान केन्द्र केशवना व कृषि विज्ञान केन्द्र केशवना कार्यरत है। जिन पर कृषि अनुसंधान कार्य के साथ प्रसार कार्य किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ,जिससे कृषकों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया जा सकें:-

जिले में क्रियान्वित योजनाएं-

1. **आईसीडीपी कॉटन** – इस योजना के तहत 1 एवं 2 दिवसीय प्रशिक्षण ,पौध संरक्षण उपकरण , प्रसार-प्रचार हेतु खरीफ/रबी की बुकलेट एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाता है।
2. **आईसोपोम** – इस योजना के तहत ऑफिसर प्रशिक्षण ,पौध संरक्षण उपकरण , पौध संरक्षण रसायन ,कृषि यंत्र एवं जिप्सम पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है ,प्रसार-प्रचार हेतु खरीफ/रबी की बुकलेट का वितरण किया जाता है।
3. **स्टेट प्लान** – क्षारीय भूमि सुधार हेतु ढेचा बीज कृषकों को उपलब्ध कराना, कृषि योजना आपके द्वार एवं कृषि महोत्सव तथा कृषकों को अन्तरराज्यीय भ्रमण कराना।
4. **वर्कप्लान** – इस योजना के तहत कृषि यंत्र एवं पौध संरक्षण उपकरण, भूमि सुधार हेतु जिप्सम एवं ढेचा बीज उपलब्ध कराना ,प्रशिक्षण एवं प्रसार-प्रचार हेतु खरीफ/रबी की बुकलेट वितरण।
5. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेंहूँ)** – इस योजना के तहत उन्नत बीज पर अनुदान ,पौध संरक्षण , कृषि यंत्र पर अनुदान एवं प्रदर्शन आयोजन व मिनिकीट वितरण किये जाते है।
6. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** – इस योजना के तहत हॉज निर्माण ,स्टोरेजबिन पर अनुदान एवं विशेष प्रोजेक्ट के तहत फसलों को बढावा दिया जाता है।
7. **आरडब्ल्यूएसआरपी** – इस योजना के तहत जिले के आहोर तहसील में कमाण्ड क्षेत्र में यह प्रोग्राम लिया जा रहा है जिसके तहत सिंचित क्षेत्र में उत्पादन बढोतरी हेतु कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ,कृषकों को अन्तरराजजीय भ्रमण तथा कृषकों के यहा प्रदर्शन आयोजित कराया जाता है।
8. **राष्ट्रीय बागवानी मिशन** – इस योजना के तहत वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना ,फल बगीचों की स्थापना ,जैविक खेती ,प्रसंस्करण इकाई स्थापना ,हाईटेक होर्टीकल्चर पर अनुदान दिया जाता है तथा सामुदायिक जल ग्रहण स्रोत पर अनुदान दिया जाता है एवं कृषक प्रशिक्षण आयोजित कराया जाता है।
9. **सूक्ष्म सिंचाई योजना** – इस योजना के अन्तर्गत स्प्रिंकलर ,मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई पर अनुदान दिया जाता है।
10. **राज्य योजना (उद्यानिकी)** – इस योजना के तहत सामुदायिक जल ग्रहण स्रोत ,पौध संरक्षण ,प्रसंस्करण इकाई की स्थापना ,वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना पर अनुदान।
11. **आत्मा योजना** – इसके तहत कृषकों को अन्तरराज्यीय भ्रमण कराना तथा प्रशिक्षण दिया जाता है।

फसलवार बीज प्रतिस्थापन दर (एसएआरआर)

जिले में खरीफ एवं रबी में उन्नत कृषि बीज के उपयोग का लगातार प्रसार-प्रचार किया जाता है। कृषकों द्वारा बाजरा फसल के उन्नत बीज का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, परन्तु अन्य फसलों के उन्नत बीज का प्रयोग लगभग 2-3 साल तक करते रहते हैं। जिससे फसलों की एसआरआर कभी कम कभी ज्यादा रहती है।

तालिका संख्या 4.18

क्र.सं.	फसल	वर्ष 02-03 से 06-07 तक का औसत	वर्ष 2007-08	विवि
1	बाजरा	29.09	42.21	खरीफ
2	मूंग	0.80	10.94	
3	मोठ	2.18	1.13	
4	ग्वार	1.04	4.92	
5	तिल	7.22	18.61	
6	अरण्डी	6.73	40.81	
7	गेहूँ	22.20	57.2	रबी
8	जौ	3.10	15	
9	सरसों	57.50	45	
10	चना	2.91	05	

उपरोक्त तालिका में स्पष्ट है कि खरीफ में बाजरा, मूंग, ग्वार, तिल, अरण्डी फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर में अच्छी वृद्धि हुई है। रबी में गेहूँ में दुगुनी से ज्यादा तथा जौ में चार गुनी से ज्यादा वृद्धि हुई है। जिले में गेहूँ की उत्पादकता वृद्धि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, इसका स्पष्ट प्रभाव गेहूँ की बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि से झलकता है।

ब्लॉकवार कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी

तालिका संख्या 4.19

पंचायत समिति	ट्रेक्टर		पंपसेट		पावरट्रिलर		बीडर		हारवेस्टर/थ्रेसर	
	परिवार	यंत्र	परिवार	यंत्र	परिवार	यंत्र	परिवार	यंत्र	परिवार	यंत्र
	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
आहोर	8951	11036	1521	3198	6235	12036	762	1488	405	405
भीनमाल	6532	8100	6351	9768	5369	8165	604	604	418	418
जालोर	4361	6169	5623	6201	3569	6269	741	741	239	239

जसवंतपुरा	3955	4815	9750	10874	2687	4817	133	133	773	773
रानीवाडा	4387	4530	10566	11736	3654	4830	246	246	1285	1285
सांचौर	11983	14510	20930	30180	7562	14609	419	419	2257	2257
सायला	6122	8340	11536	16458	4562	8403	665	665	1407	1407
योग	46291	57500	66277	88415	33638	59129	3570	4296	6784	6784

वर्ष 2007-08 में

उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है कि सांचौर व आहोर में ट्रेक्टर्स की संख्या सर्वाधिक हैं क्योंकि इन्हीं दो ब्लॉक्स में जिले का सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। आहोर में कुओं में पानी कम है अतः पम्पसेट की संख्या अपेक्षाकृत कम है। पंपसेट की संख्या सांचौर, सायला, रानीवाडा में अधिक है। सायला व रानीवाडा ब्लॉक में भू-जल की स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक है। जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्र, थ्रेसर अनुदान पर वितरित किये जा रहे हैं अतः भविष्य में इनकी बहुत बढ़ोतरी होगी।

स्वोट विश्लेषण (दसलेपे)

इस अध्याय में जिले में उपलब्ध संसाधनों एवं सेक्टर की मजबूती, कमजोरी उपलब्ध अवसरों एवं आकांक्षाओं के बारे में विश्लेषण किया जा रहा है। यह विश्लेषण जिले में कृषि क्षेत्र की तरक्की के लिये सूचक का कार्य करेगा एवं प्राथमिकता निर्धारण में सहायक होगा।

कृषि क्षेत्र (हतपबनसजनतममबजवत) :-

मजबूती (जतमदहजी) -

1. कृषकों के पास तुलनात्मक रूप से जोत का आकार बड़ा होना।
2. जिले के कुछ भू-भाग में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाओं की उपलब्धता।
3. सांचौर सम्पूर्ण तहसील में नर्मदा नहर से सिंचाई होने की सम्भावना (फव्वारा सिंचाई)
4. सिंचित क्षेत्र में नगदी फसले जैसे :- अरण्डी, जीरा व ईसबगोल, पीपीता, तरबूज, बेर एवं नींबू की खेती के अच्छे अवसर।
5. कृषि के विविधिकरण में मूंगफली, पीपीता, राजगिरा, फूल की अधिक सम्भावना
6. शुष्क क्षेत्र में सोनामुखी की खेती को बढ़ावा
7. जीरा, ईसबगोल, टमाटर, ग्वार, सोनामुखी के प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना की पूर्ण सम्भावना।
8. उपलब्ध जल संसाधन से स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप एव पाईप लाईन तकनीकी से सिंचाई कर अधिक क्षेत्र में सिंचाई
9. पाला पडने की न्यूनतम सम्भावना एवं न्यूनतम आद्रता के कारण जीरा, अरण्डी की प्रति हेक्टर पैदावार बढ़ाने की सम्भावना

कमियां (मांदमे) -

1. भूमि की उर्वरा शक्ति के प्रबन्धन का अभाव

2. उचित जल प्रबन्धन का अभाव ।
3. समस्या ग्रस्त (लवणीय एवं क्षारीय) भूमि अधिक
4. समस्या ग्रस्त भू-जल (लवणीय एवं क्षारीय)
5. उन्नत कृषि तकनीकी का खेतों में कम उपयोग ।
6. असमय ,अल्प वर्षा के कारण खरीफ/रबी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव
7. रबी की खडी फसल व खलियान यथा जीरा,ईसबगोल ,रायडा में मानसून पूर्व वर्षा एवं आंधी तुफान से अधिक मात्रा मे बार-बार नुकसान
8. उन्नत कृषि आदानों का समय पर उपलब्ध न होना ।
9. कृषको का उन्नत कृषि तकनीकी अपनाने के प्रति उदासीन रवैया ।

ब अवसर (व्वचवतजनदपजल) –

1. जिले में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की सम्भावना (नर्मदा नहर प्रोजेक्ट)
2. मिश्रित खेती के अवसर ।
3. जैविक खेती की बढ़ती हुई सम्भावनाएँ ।
4. फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के पर्याप्त अवसर ।
5. फसलों के विविधिकरण के अवसर ।
6. उद्यानिकी फसलें यथा ईसबगोल ,जीरा ,टमाटर ,मिर्च ,बेर ,आंवला ,नींबू ,खजूर ,पपीता ,बेलपत्र ,घृतकुमारी एवं फूलों की खेती के प्रयाप्त अवसर
7. कृषि की उन्नत तकनीकी के प्रचार- प्रसार की व्यापक संभावनाएँ ।

क आशंकाए (जेतमंज) –

जिले की कुल कृषि योग्य भूमि में से बड़े भू-भाग का बारानी होना
(वर्षा पर निर्भर होना)

2. अधिकतर भूमि का लवणीय व क्षारीय होना
3. अधिकतर क्षेत्रों के भूमिगत पानी की गुणवत्ता कृषि योग्य न होना एवं भूमिगत अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का गहरा होते जाना ।

स्वोट के अनुसार ; |बबवतकपदह जव*व्द्धरू.

*व् विश्लेषण से हम जिला जालोर की कृषि संबन्धित सभी क्षेत्रों की ताकत और कमियों की पहचान कर चुके हैं। साथ-साथ क्षेत्र में मौजूदा व निकट भविष्य में मिलने वाले अवसरों व संभावित खतरों का अध्ययन भी पिछले पेजो में किया गया है। हमारी समग्र जिला कृषि योजना इसी विश्लेषण को आधार बनाकर बनाई जा रही है। योजना में सभी के सहयोग से जिले की निहित शक्तियों को उभारते हुए एवं कमियों को दूर करते हुए प्रयत्न विशेष प्रोजेक्ट के माध्यम से किये जा रहे हैं। कृषि व संबन्धित क्षेत्रों की उन्नति के लिये किसानों को उपलब्ध सभी अवसर का समुचित लाभ उठाने की स्थिति में लाने के लिये बनाये गये हैं। किसानों के लिये ये अवसर न केवल जिला स्तर पर बल्कि प्रदेश व बाहर से भी मिल सकते हैं क्योंकि वर्तमान व भविष्य के आर्थिक परिदृश्य में खेती सिर्फ एक जिले या राज्य की भौगोलिक या आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर नहीं रह सकती । इन अवसरों के साथ

ही साथ निहित खतरों का सामना भी हमारे किसानों को करना है। इनका सामना करने के उद्देश्य की पूर्ति भी विशेष प्रोजेक्ट्स व दुसरे विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से की गई है। जिले की शस्य पारिस्थितिकी के आधार पर ग्रामवार तहसीलवार व कम उत्पादकता और कमजोर संसाधनों वाले क्षेत्रों को विशेष रूप से चिन्हित करके कार्यक्रमों को बनाया व क्रियान्वयन किया जाना है।

क्षेत्रीय वृद्धि कारक (त्महपवदंस ळतवूजी क्तपअमते) :-

उच्च उत्पादन प्राप्ति में निम्न वृद्धि कारकों की न्यायोचित रूप से उपयोग तथा अपनाने व सुधार की आवश्यकता है।

कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में :-

मिटटी की दशा में सुधार करके

मृदा संरक्षण उपायों को अपनाकर

समुचित जल प्रबंध द्वारा जैसे वर्षा का जल संरक्षण

उपलब्ध जल की मात्रा को सही समय, सही मात्रा में प्रयोग कर

बाजार मांगानुसार फसलों की उन्नत किस्में उगाकर

शत प्रतिशत बीजोपचार अपनाकर

उन्नत कृषि तकनीकी अपनाकर

फलों की खेती यथा पपीता ,बेर ,नींबू ,अनार ,बेलपत्र ,खजूर

समन्वित कीट प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन अपना कर

प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों को उन्नत तकनीकी जानकारी के माध्यम से उत्पादन बढ़ाना

4.6 पशुपालन :

जिले में लोगों की आजीविका कृषि के अलावा पशुपालन पर निर्भर है। पशुगणना 2003 के अनुसार राजस्थान में 4.91 करोड़ पशुधन था, जिसमें जिले में 16.43 लाख पशुधन था जो राज्य में चौदवे स्थान पर था। वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.78 करोड़ पशुधन है, जिसमें जिले में 19.00 लाख पशुधन है। जो तहसीलवार विवरण तालिका संख्या 4.20 में दर्ज है:-

तालिका संख्या 4.20

स्टैटिस्टिकल ब्युरो 2007

रिपोर्ट नंबर 1/2007

राजस्थान के पशुधन ; राज्यवार विवरण

क्र.सं.	पशुधन	2003	2007	वृद्धि/घटती (वर्ष 2003 से 2007 तक)	
				अंक	प्रतिशत
1	गर्भधारी	246936	293509	46573	18.86
।	बकरी	221	316	95	42.98
ठ	घास	246715	293193	46478	18.83
2	गर्भधारी	356496	411694	55198	15.48
।	गाय	34971	42529	7558	21.61
ठ	धूम्र	321525	369165	47640	14.81
3	भैंस	563130	630531	67401	11.96
4	काबू	451248	547858	96610	21.40
5	भैंस - चूने	1535	1652	117	7.62
6	डूंगरी	0	0	0	0
7	कछुआ	7231	3587	-3644	-50.39
8	बाढ़	9304	8177	-1127	-12.11
9	चूने	7067	2910	-4157	-58.82
	कुल	1642947	1899918	256971	15.64
10	तिल	441	42	-399	-90.47
11	कूड़े	116506	63674	-52832	-45.34
12	कृषक	21906	15182	-6724	-30.74

(संलग्नक 1/2007 के अनुसार)

उपरोक्त तालिका संख्या से यह स्पष्ट है कि 2007 पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

पशु नस्ल स्थिति :- जिले में कांकरेज नस्ल के पशु पाये जाते है जिसका विवरण इस प्रकार है-

कांकरेज नस्ल :-

जालोर जिले में कांकरेज नस्ल के पशु सांचोर तहसील क्षेत्र में पाये जाते है, जिसका मूल स्थान गुजरात का "कच्छ क्षेत्र" है इस वंश के पशु (बैल) चलने में तेज और बोझा ढोने के लिये शक्तिशाली होते है। इस नस्ल के पशुओं का शरीर लम्बा व मजबूत, चौड़ा सीना, सीधी कमर, अपेक्षाकृत चौड़ा ललाट जो बीच में धंसा होता है। इसके सींग मजबूत व मुड़े हुए जो मस्तक के बाहरी कोनों से निकलकर बाहर की ओर, फिर उपर व बाद में अन्दर की ओर मुड़ते है। ये सींग काफी ऊँचाई तक खाल से ढके रहते है। कांकरेज गायों का औसत दुग्ध उत्पादन 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात होता है। उक्त नस्ल के पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ये नस्ल विपरित वातावरणीय परिस्थितियों में अकाल से जुझने की क्षमता रखती है। जिले में पाई जाने वाली उक्त नस्ल भारत में पाई जाने वाली गायों की श्रेष्ठतम नस्लो में अपना एक विशेष स्थान रक्खती है।

मानव संसाधन-

जिले में 264 ग्राम पंचायतो मेसे केवल 87 ग्राम पंचायतो में ही पशु चिकित्सा संस्था कार्यरत है। शेष 177 ग्राम पंचायतो में पशु चिकित्सा सुविधाओ का अभाव है, जिले के कई ग्राम पंचायतो के अधिनस्थ ग्रामों के पशुपालको को 15 से 20 कि.मी. दूरी तक पशुपालन की सुविधाओ का लाभ नही मिल पा रहा हैं, वे ग्राम पंचायतें तालिका संख्या 4.21 के अनुसार है:-

तालिका संख्या 4.21

क्र.सं	नाम प.समिति	ग्राम पंचायत का नाम ;बतपजपबंसध्टनसदमतंइसम।तमंद्ध
1.	जालोर	बीबलसर, ऊण, मेडाउपरला, सिवणा, ओडवाडा
2.	आहोर	शंखवाली, पांचोटा, अजीतपुरा, वेडिया, नोसरा, सुगा.जोधा, चुण्डा, वलदरा
3.	सायला	सिराणा, देताकल्ला, उनडी, मंगलवा, कोमता
4.	भीनमाल	कालेटी, मोरसीम, राउता, बाली, डूंगरवा, बोरटा
5.	जसवंतपुरा	बासडाधनजी, सीकवाडा, कलापुरा
6.	रानीवाडा	सिलासण, धामसीन, चाटवाडा, पूरण,पंसेरी
7.	सांचोर	केरिया,,वीरावा, जोरादर, सरवाना, दांतिया, भडवल,खेजडियाली, जाणवी,काछेला, सेसावा, भीमगुडा, जोधावास

वर्ष 2015 तक भावी रणनीति-

1. जिले में 2007 की पशुगणना के अनुसार अनुमानित 19.00 लाख पशु है, उक्त पशुओं की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिले वर्तमान में मात्र 45 प.चि.व 42 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र तथा जिला मुख्यालय पर एक जिला रोग निदान प्रयोगशाला कार्यरत है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सा संस्था स्थापित होनी चाहिये, जिले में वर्तमान में प्रति 21840 पशुओं पर एक संस्था कार्य कर रही है, जो काफी कम है। 2007 पशुगणना को दृष्टिगत रखते हुए 113 अतिरिक्त नवीन पशु चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना करना प्रस्तावित है।
2. वर्ष 2015 तक 30 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, 50 प्रतिशत दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, शहरी क्षेत्र में आवारा पशुओं के नियन्त्रण हेतु ठोस कानून बनाया जाना प्रस्तावित है साथ ही आवारों पशुओं जिनकी वृद्धि अनियंत्रित है उनका बधियाकरण करवाना। नगरीय जनता को आवारा पशुओं से निजात मिलगी।
3. बी.पी.एल पशुपालकों को बी.पी.एल. पशुपालक कार्ड उपलब्ध करवा कर उनके पशुओं को अनुदानित दर चारा, पशु आहार, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
4. जिले की कांकरेज नस्ल की गायों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये एक कांकरेज फार्म स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिससे पशुपालकों को उन्नत नस्ल के बछड़े पैदा कर प्रगतिशील पशुपालकों वितरण किया जावेगा जिससे नस्ल सुधार के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। साथ ही जिले के भैड़पालकों के लिये एक ऊन मंडी स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है जिससे भैड़पालकों को ऊन के उचित दाम मिल सकेंगे।
5. जिले के अश्वपालकों हेतु एक अश्व प्रजनन केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है जिससे मालानी धोड़ों का जिले में विकास होगा।
6. जिले में पशुपोषण प्रयोगशाला खोला जाना प्रस्तावित है, जिससे पशुआहार एवं पशु चारे की जाँच की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तर पर पशुधन विकास नीति बनाया जाना प्रस्तावित है।

4.7 महिला महिला एवं बाल विकास

जिले में महिला एवं बाल विकास कार्यालय संचालित हैं। इनका संचालन उपनिदेश 1क, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जालोर द्वारा किया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत 7 बाल विकास परियोजनाएँ पंचायत समितिवार संचालित है जिसमें 1183 आँगनवाड़ी केन्द्र तथा 64 मिनी आँगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत व संचालित हैं। पूरक पोषाहार लाभान्वितों के मासिक लक्ष्य 121500 एवं स्कूल पूर्व शिक्षा के लक्ष्य 48600 के विरुद्ध प्रतिमाह क्रमांक 1: 86 एवं 77 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित हो रही है। माह जुलाई 09 में पूरक पोषाहार से 105034 एवं स्कूल पूर्व शिक्षा से 37095 को लाभान्वित किया गया है जो क्रमांक 1: 86 एवं 76 प्रतिशत हैं।

विभाग द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचड़ी) तथा बेबी मिक्स/पजीरी क्रमांक 1: 3 से 6 वर्ष के बच्चों को तथा गर्भवती/धात्री माताओं/किशोरी बालिकाओं एवं 6 माह से 3 वर्ष के

बच्चों, जो कुपोषित एवं अतिकुपोषितों को दिया जाता है। जालोर परियोजना में न्यूट्रीशन मिशन के तहत पूरक पोषाहार बेबी मिक्स, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार कर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पौषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना एवं सन्दर्भ सेवा, परिवार कल्याण के कार्य किये जाते हैं। परिवार कल्याण के माह जुलाई 09 में 29 एवं कुल 143 केस हुए हैं। वर्ष में दो बार 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन 'ए' का घोल रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं आँखों की रोगों हेतु पिलाया जाता है।

महिला विकास अभिकरण के अन्तर्गत महिलाओं के संबंधित कार्य संपादित किये जाते हैं। जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार द्वारा स्वावलम्बी बनाया जाता है। जिले में प्रारम्भ से कुल 2040 समूहों का गठन तथा 554 समूहों को 187.71 लाख रुपये का ऋण विभिन्न बैंकों से उपलब्ध करवाया जाकर लाभान्वित किया गया है। किशोरी बालिकाओं को 'आपकी बेटी' योजना के तहत पौषण, स्वास्थ्य एवं शारीरिक बदलाव की शिक्षा के साथ स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर साथिन का एक पद स्वीकृत है। जिले में स्वीकृत 264 साथिनों के मानदेय पदों के विरुद्ध 51 साथिन कार्यरत हैं।

विभागीय गतिविधियों का लक्ष्य एवं प्रगति विवरण वर्ष 09-10 का माह मार्च 09 तक निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	गतिविधि	लक्ष्य मासिक/वार्षिक	प्रगति विवरण		वि. वि.
1	समेकित बाल विकास सेवा परियोजना	7	7	7	100 :
2	आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन	1183	1183	1183	100 :
3	मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालक	64	64	64	100 :
4	पूरक पोषाहार लाभार्थी	121500 / 1458000	105034	420105	86 :
5	शाला पूर्व शिक्षार्थी	48600 / 583200	37095	148525	76 :
6	पोषाहार वितरण	243.934 डण्ड	205.617 डण्ड	241.939 डण्ड	99 :
7	आशा सहयोगिनी नियुक्ति	1183	.	460	34 :
8	स्वयं सहायता समूह गठन	500	2	15	3 :
9	स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण	500	.	.	.
10	साथिन नियुक्ति	264	.	51	19.31 :

जिले में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों का विवरण :-

(अ) उपनिदेशक आई.सी.डी.एस. -

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	वि. विवरण
1	उपनिदेशक	1	—	1	मार्च 09 से रिक्त
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी	7	5	2	9 वर्षों से रिक्त हैं।
3	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	4	—	4	9 वर्षों से रिक्त हैं।
4	कार्यालय सहायक	1	1	—	—
5	लेखाकार	4	1	3	4 वर्षों से रिक्त हैं।
6	सांख्यिकी सहायक	5	—	5	9 वर्षों से रिक्त हैं।
7	वरिष्ठ लिपिक	8	6	2	3 वर्षों से रिक्त हैं।
8	कनिष्ठ लिपिक	12	3	9	9 वर्षों से रिक्त हैं।
9	महिला पर्यवेक्षक	57	16	41	9 वर्षों से रिक्त हैं।
10	वाहन चालक	8	4	4	9 वर्षों से रिक्त हैं।
11	च.श्रे. कर्मचारी	12	6	6	9 वर्षों से रिक्त हैं।
	कुल :-	119	41	78	

(ब) कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला विकास अभिकरण —

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	विशेष विवरण
1	कार्यक्रम अधिकारी	1	—	1	अप्रैल 09 से रिक्त
2	कनिष्ठ लेखाकार	1	—	1	अप्रैल 07 से रिक्त
3	कनिष्ठ लिपिक	1	1	—	—
4	प्रचेता	7	—	7	9 वर्षों से रिक्त हैं
	कुल :-	10	1	9	—

मानदेय पदों का विवरण :-

1	साथिन	264	51	213	4 वर्षों से रिक्त हैं
---	-------	-----	----	-----	-----------------------

वैवनतबम प्बै

कमचज श्रंसवतम द्व

4.8 ग्रामीण विकास एवं भाहरी विकास

1.1 जिला परिशद—

ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतीराज के अन्तर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था है। यह स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिशद है, इस स्तर से ग्रामीण क्षेत्र में विकास इकाई के रूप में

कार्य करती है। त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास की योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना है। प्रत्येक पांच वर्षों में पंचायतीराज जन प्रतिनिधियों के चुनाव करवाये जाते हैं।

पंचायतीराज प्रशासन की दृष्टि से जिले में एक जिला परिशद, 7 पंचायत समितियाँ, 264 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिशद सदस्यों में पुरुष एवं महिलाओं का विवरण सारणी अनुसार है—

क्र.सं.	जिला परिशद सदस्य संख्या	पुरुष	महिला	वि. वि.
1	31	18	13	—

(स्रोत जिला परिशद, जालोर मार्च 2009)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिले में 31 जिला परिशद सदस्य हैं, जिसमें जिला प्रमुख महिला है।

पंचायत समिति में पुरुष महिला

क्र.सं.	पंचायत समिति	पंचायत समिति सदस्य			पंचायत समिति संख्या	ग्राम पंचायत वार्डों संख्या
		सदस्य	पुरुष	महिला		
1	जालोर	17	10	7	25	328
2	टाहोर	23	15	8	41	467
3	सायला	25	17	8	38	484
4	भीनमाल	23	15	8	35	431
5	जसवंतपुरा	17	13	6	29	321
6	रानीवाडा	19	9	8	30	364
7	सांचौर	37	24	13	63	773

(स्रोत जिला परिशद, जालोर मार्च 2009)

पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ—

बीआरजीएफ —

योजना के तहत चयनित जिलों के पिछड़ेपन को दूर करने के हेतु भारत सरकार द्वारा भात-प्रति ात अनुदान राि ा उपलब्ध करवाई जाती है। इस कार्यक्रम का उद्दे य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास की अन्य आव यकताओं की नाजुक कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाना है। जिले में यह कार्यक्रम वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुआ। प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है, जिसे आयोजना समिति अनुमोदित करती है। वर्षवार प्रगति सारणी अनुसार है—

वर्ष	कार्यों की संख्या		वित्तीय प्रगति (लाखों में)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	व्यय
2006-07	283	283	750.00	731.28
2007-08	908	366	1996.74	1317.15
2008-09	मार्च तक प्रारंभ नहीं			

(स्रोत जिला परिषद, जालोर मार्च 2009)

सुझाव—

इस योजना के तहत तैयार प्लान का अनुमोदन जिला आयोजना समिति द्वारा किया जाता है, जिसका अनुमोदन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाता है। इसमें कई कार्य भूमि विवाद, राि ा का अभाव, कार्य स्थल में परिवर्तन इत्यादि कारणों से कार्यों में सं ाोधन किया जाना होता है। जो राज्य स्तर से किया जाना है, उक्त सं ाोधन संबंधित कार्य जिला आयोजना समिति को हस्तांतरित किया जावे।

बीआरजीएफ की राि ा को दो गुना तक बढ़ाया जावे ।

इस योजना में राि ा को बढ़ाने से जिले में पिछड़ेपन को दूर किया जा सकेगा।

निर्बन्ध राि ा योजना को पुनः भुरु किया जावे तथा योजना की राि ा 20 करोड तक किया जावे ताकि जो कार्य अन्य योजनाओं में नहीं हो सकते है, उनको ग्रामीणों की मांग के अनुसार प्राथमिकता दी जा सके।

1.2.ग्रामीण विकास प्रकोश्ट

जिला स्तर पर जिला परिषद् के अन्तर्गत ग्रामीण विकास प्रकोश्ट संचालित है, इस प्रकोश्ट द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित कर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, आधारभूत संरचनाओं का सृजन करना एवं विकास की योजनाओं में आम लोगों की भागरीदारी प्राप्त करना।

महानरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार 'रोजगार को एक अधिकार के रूप में प्रदान करता हैं। इसके माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा हैं। जिससे लोगों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध हो जाये। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को उसके चाहने पर प्रत्ये वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार सरकार

द्वारा उपलब्ध करवायेगी। परिवार के 18 वर्ष से ऊपर अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले सदस्य शामिल हैं। परिवार एक सदस्य का भी हो सकता है व ज्यादा का भी।

जिले में यह योजना 2 मई 2007 से प्रारंभ हुई। जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	वर्ष	जॉब कार्ड जारी किये	वर्ष के दौरान	
			रोजगार की मांग	रोजगार उपलब्ध करवाया
1	2007.08	220154	149680	149680
2	2008.09	240847	169341	169341

(स्रोत-समस्त पंचायत समिति)

उपरोक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि इन वर्षों में जिन परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गई उन परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। महानरेगा योजना के अन्तर्गत सृजित मानव दिवसों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका अनुसार है।

(लाखों में)

क्र.स.	वर्ष	एससी	एसटी	अन्य	योग
1	2007.08	36 ^७ 25	15 ^७ 78	55 ^७ 74	107 ^७ 77
2	2008.09	39 ^७ 37	18 ^७ 64	68 ^७ 21	126 ^७ 22

(स्रोत-समस्त पंचायत समिति)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 2009 तक 126.22 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है, इनमें सर्वाधिक कार्य दिवसों की संख्या एससी/एसटी की है 92.49 महिला हैं जो कि पुरुषों की अपेक्षा अधिक हैं।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विकास कार्य के साथ-साथ आजीविका के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य को स्वीकृत किया गया है। जिसका विवरण श्रेणीवार निम्नानुसार है। (मार्च, 2009)

छवण	बंजमहवतल	छवण विविता	लमंत 07.08 माचमदकपजनतम	छवण विविता	लमंत 07.08 माचमदकपजनतम
1	जल संरक्षण	102	802 ^७ 46	144	574 ^७ 84
2	वानिकी	41	166 ^७ 25	104	276 ^७ 20
3	लघु सिंचाई	5	48 ^७ 73	65	681 ^७ 59
4	सिंचाई कार्य	716	531 ^७ 28	2322	2448 ^७ 68
5	परम्परागत जल स्रोत	800	4784 ^७ 09	754	3344 ^७ 89
6	भूमि सुधार	6	29 ^७ 96	148	556 ^७ 94
7	बाढ बचाव	105	144 ^७ 83	184	1520 ^७ 03
8	ग्रामीण सडके	341	582 ^७ 81	1049	9408 ^७ 34
9	अन्य	0	0	0	0

योग :-	2116	7090 ^प 41	4770	18811 ^प 51
--------	------	----------------------	------	-----------------------

2. नगर निकाय

भाहरी क्षेत्र में नगर पालिकाएँ भाहर के विकास के इकाई के रूप में कार्य करती हैं। नगर निकायों का प्रमुख उद्देश्य भाहरी विकास की योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना है। प्रत्येक पांच वर्षों में नगर निकायों के चुनाव करवाये जाते हैं। जिले में तीन नगर पालिकाएँ हैं, जालोर भीनमाल एवं सांचौर हैं जिनके नगर पालिका सदस्यों की संख्या इस प्रकार है—

क्रस	नगर पालिका	सदस्य संख्या	पुरुश	महिला
1	जालोर	25	17	8
2	भीनमाल	25	13	12
3	सांचौर	25	16	9
योग		75	46	29

(स्रोत नगर पालिका, जालोर, भीनमाल, सांचौर 2009)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पालिकाओं में महिलाओं की स्थिति अच्छी है। नगर निकायों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की सीटें आरक्षित रखी गयीं जिनका विवरण इस प्रकार है—

क्रस	नगर पालिका	अनु. जाति	जनजाति	अन्य पिछड़ा. वग	योग	महिला
1	जालोर	6	2	6	14	8
2	भीनमाल	4	1	5	10	8
3	सांचौर	6	1	7	14	8

(स्रोत नगर पालिका, जालोर, भीनमाल, सांचौर 2009)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर पालिकाओं में महिलाओं की भागीदारी सराहनीय है।

नगर पालिकाओं की प्रमुख योजनाएँ हैं :-

जिले में स्थापित तीनों नगर पालिकाओं द्वारा भाहरी विकास के लिए योजनाएँ क्रियान्वयन की जाती हैं उनमें मुख्य रूपसे निम्न योजनाओं का विवरण इस प्रकार है—

1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोश— इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास की अन्य आवश्यकताओं की नाजुक कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। जिले में यह कार्यक्रम वर्ष 2006-07 से प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है, जिसे जिला आयोजना समिति अनुमोदित करती है—

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोश

कार्यों की स्थिति

नगर पालिका	वर्ष	कार्यों की संख्या
------------	------	-------------------

		स्वीकृत	पूर्ण
जालोर	2006-07	10	09
	2007-08	12	11
	2008-09	16	
भीनमाल	2006-07	5	5
	2007-08	28	28
	2008-09	28	12
सांचौर	2006-07	5	1
	2007-08	8	8
	2008-09	13	9

(स्रोत नगर पालिका, जालोर, भीनमाल, सांचौर 2009)

स्वर्ण जयंति भाहरी रोजगार योजना-

भाहरी क्षेत्र के विकास के लिए भाहरी क्षेत्र में रहने वाले पिछड़े कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों का स्थाई विकास के लिए स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य भाहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित कर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, आधारभूत संरचनाओं का सृजन करना एवं विकास की योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी प्राप्त करना। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से स्वर्ण जयंति भाहरी रोजगार योजना है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया जिनमें महिलाओं की स्थिति सारणी अनुसार है-

स्वर्ण जयंति भाहरी रोजगार योजना

नगर पालिका	वर्ष	अनु. जाति	जनजाति	अन्य पिछड़ा. वग	योग	महिला
जालोर	2008-09	162	102	61	325	265
भीनमाल	2009	20	3	7	30	30
सांचौर	2008-09	39	2	39	80	39

(स्रोत नगर पालिका, जालोर, भीनमाल, सांचौर 2009)

इस योजना में महिलाओं को स्वयं का रोजगार अर्जित करने के लिए नगर पालिका स्तर पर अनेक स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने वाले विषय में प्रशिक्षण देकर रोजगारोन्मुखी बनाया गया।

4.9 पर्यटन

जालोर जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी पिछडा हुआ है। यहाँ पर्यटकों की संख्या लगभग नगण्य रहती है। जिले में निम्नलिखित पर्यटक स्थल है—

तोपखाना—जालोर —



जिले में जहां आजकल तोपखाना हैं, वह वस्तुतः परमार राजा भोज द्वारा बनाई गयी संस्कृत पाठशाला है। रियासत काल में इसमें जोधपुर राज्य की तोपे रखी जाती थी और तब से इसका नाम तोपखाना पडा, यह दर्शनीय स्थल है।

सुन्धा माता —

अरावली पर्वत श्रृंखला में 1220 मीटर की ऊंचाई के सुन्धा पर्वत पर चामुण्डा देवी का प्रख्यात मन्दिर है। गुजरात राज्य से आने वाले दर्शनार्थी रानीवाडा, आबूरोड से बसों आवागमन का साधन है, तहलटी से मंदिर



तक जाने के लिए रोप वे की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान एवं गुजरात के लाखों यात्री प्रतिवर्ष मन्दिर में दर्शनार्थ आते हैं। वर्ष भर झरना बहता हैं। प्राकृतिक वनावली की छटा अत्यन्त रमणीय हैं। कलात्मक ढंग से अंकित की गई देवी-देवताओं की मूर्तिया एवं मण्डप की कलाकृतिया पर्यटकों को देलवाडा जैन मन्दिर की याद दिलाती हैं। यहां सुन्धा अभिलेख भारतीय इतिहास का अनोखा दस्तावेज है।

भीनमाल का वराह मन्दिर,— भीनमाल का वराह श्याम मन्दिर भारत के अति प्राचीन व गिने चुने वराह श्याम मन्दिरों में से एक है। यहां स्थापित नर वराह की मूर्ति जैसलमेर के पीले पत्थर से निर्मित है जो सात फीट ऊंची तथा अढाई फीट चौड़ी है। मन्दिर के कहरी चौक के स्थान-स्थान पर भूमि की खुदाई से प्राप्त मूर्तिया स्थापित की जाती हैं।

अन्य पर्यटक स्थल— समदडी भीलडी रेलमार्ग पर मोदरा गांव में आशापुरी माता का मन्दिर हैं। जालोर दुर्ग की निकटवर्ती पहाडियो पर स्थित सिरें मंदिर नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध ऋषि जालन्धर नाथ की तपोभूमि हैं। सेवाडा मन्दिर (रानीवाडा), जागनाथ महादेव मंदिर (धवला) आपेश्वर महादेव मन्दिर (रामसीन), गौरी मन्दिर

(माण्डोली नगरी) और नन्दीश्वर तीर्थ (जालोर शहर) आहोर तहसील में एंसरका पर्वत पर सूरेश्वर महादेव मन्दिर दर्शनीय स्थल हैं।

अध्याय ट- जेण्डर

जिले में स्त्री पुरुष लिंगानुपात (प्रति हजार) 964 है। जो राज्य के औसत 921 से काफी अधिक है जो अच्छा है। फिर भी यह अनुपात दर्शाता है कि जिले में 1000 पुरुषों के मुकाबले 964 स्त्रियां ही हैं। जो चिन्ता का विषय है। इससे भी चिन्ता का विषय जिले के अन्दर इस लिंगानुपात में असमानता है। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में यह लिंगानुपात 970 है वहीं भाहरी क्षेत्र में मात्र 889 ही है। इसमें भी जालोर नगर पालिका क्षेत्र में यह और भी कम, मात्र 873 ही है।

लिंगानुपात:

जिले में भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार कुल लिंगानुपात 1991 में 942 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 964 हो गया। इससे स्पष्ट है कि लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। ग्रामीण लिंगानुपात 1991 में 947 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 970 हो गया, शहरी लिंगानुपात 1991 में 881 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 889 हो गया। नवजात शिशु लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष) 1991 में 929 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 921 हो गया। इससे स्पष्ट है कि नवजात शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 1991 में 901 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 921 हो गया, एवं अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 1991 में 885 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 904 हो गया। 1991 में महिला कार्य सहभागिता दर 31.60 थी जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 46.09 हो गयी। इससे स्पष्ट है कि महिला सहभागिता दर में वृद्धि हुई है। जिले में विवाह की औसत आयु जनगणना 2001 के अनुसार भी 18.30 वर्ष है। जो कि संतोषजनक है।

जन्म एवं मृत्यु का स्तर:

शताब्दी विकास लक्ष्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिशु मृत्यु दर की स्थिति राजस्थान के सन्दर्भ में अधिक विकट है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व गुणवत्ता की प्राप्ति को इस सूचकांक के माध्यम से आंका जा सकता है। शिशु मृत्यु दर एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है जिस पर अधिकारिक आंकड़ों की उपलब्धता का भी अभाव है। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर गत दो दशक में स्थिर होने के साथ-साथ कमी की ओर अग्रसर है। जिले में शिशु एवं बाल मृत्यु दर के प्राथमिक आंकड़ों का अभाव है। यहां पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, मई 2008 के अनुसार जालोर की बाल एवं शिशु मृत्यु दर के द्वितीयक आंकड़ों का विवरण निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत है जो की चिन्ताजनक हैं

सारणी- राजस्थान व भारत, जालोर शिशु मृत्यु दर 2001

(स्रोत: पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, मई 2008)

	कुल	पुरुष	स्त्री
भारत	54	54	53

राजस्थान	79	78	81
जालोर	88	84	92

सारणी— भारत, राजस्थान व जालोर, बाल मृत्यु दर 2001
(स्रोत: पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, मई 2008)

	कुल	पुरुष	स्त्री
भारत	59	58	61
राजस्थान	88	85	92
जालोर	99	94	104

चित्र—तुलनात्मक आई.एम.आर., सी.एम.आर.
(स्रोत: पोपुलेशन फाउंडेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, मई 2008)

जिले में नामांकित विद्यार्थियों में जेण्डर गेप

जालोर जिले में शिक्षा के स्तर में छात्र-छात्राओं का नामांकन में जेण्डर गेप अत्यधिक है, जिसका विवरण तालिका संख्या 5.1 के अनुसार है।

तालिका संख्या 5.1

जेण्डर गेप

विधालय स्तर	विद्यार्थी		कुल जेण्डर गेप	अनुसूचित जाति	अनुजन जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अल्प संख्यक
	छात्र	छात्रा					
प्राथमिक	158205	126310	11 ^प 11	12 ^प 71	16 ^प 47	7 ^प 81	17 ^प 37
उच्च प्राथमिक	63303	35288	28 ^प 41	18 ^प 91	39 ^प 67	15 ^प 77	18 ^प 07
माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक	26920	8857	50 ^प 49	41 ^प 86	68 ^प 10 ^प	39 ^प 85	47 ^प 56

(वनतबम म्कनण्मचज 2009)

उपरोक्त तालिका का से यह स्पष्ट होता है कि जिले में छात्रों की अपेक्षा छात्राओं के नामांकन में जेण्डर गेप प्राथमिक स्तर पर 11.11 प्रति ात है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बढ़ कर 28.41 प्रति ात तथा उच्च माध्यमिक स्तर बढ़ कर 50.49 प्रति ात हो जाता है, यह अन्तर बालिका शिक्षा के लिए अत्यन्त ही सोच का विशय है। समेकित बाल विकास सेवा योजनान्तर्गत 7 बाल विकास परियोजनाएँ पंचायत समितिवार संचालित है जिसमे 1183 आँगनवाड़ी केन्द्र तथा 64 मिनी आँगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत व संचालित हैं। पूरक पोषाहार लाभान्वितों के मासिक

लक्ष्य 121500 एवं स्कूल पूर्व शिक्षा के लक्ष्य 48600 के विरुद्ध प्रतिमाह क्रमांक 1: 86 एवं 77 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित हो रही है। माह जुलाई 09 में पूरक पोषाहार से 105034 एवं स्कूल पूर्व शिक्षा से 37095 को लाभान्वित किया गया है जो क्रमांक 1: 86 एवं 76 प्रतिशत हैं।

टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पौषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना एवं सन्दर्भ सेवा, परिवार कल्याण के कार्य किये जाते हैं। परिवार कल्याण के माह जुलाई 09 में 29 एवं कुल 143 केस हुए हैं। वर्ष में दो बार 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन 'ए' का घोल रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं आँखों की रोगों हेतु पिलाया जाता है।

महिला विकास अभिकरण के अन्तर्गत महिलाओं के संबंधित कार्य संपादित किये जाते हैं। जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार द्वारा स्वावलम्बी बनाया जाता है। जिले में प्रारम्भ से कुल 2040 समूहों का गठन तथा 554 समूहों को 187.71 लाख रुपये का ऋण विभिन्न बैंकों से उपलब्ध करवाया जाकर लाभान्वित किया गया है। किशोरी बालिकाओं को 'आपकी बेटी' योजना के तहत पौषण, स्वास्थ्य एवं शारीरिक बदलाव की शिक्षा के साथ स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर साथिन का एक पद स्वीकृत है। जिले में स्वीकृत 264 साथिनों के मानदेय पदों के विरुद्ध 51 साथिन कार्यरत हैं।

सार 1 एवं भावी रणनीति

जालोर जिला राज्य व राष्ट्र की तुलना में काफी पिछडा हुआ है। जिले का कुल क्षेत्रफल 10,564,44 वर्ग कि०मी० है। यह जिला राजस्थान प्रान्त का 3.11 प्रतिशत क्षेत्रफल घेरे हुए है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रान्त में जिले का तेरहवां स्थान है। क्षेत्रफल काफी है तथा मानव भाक्ति भी पर्याप्त है साथ ही स्त्री पुरुश अनुपात भी राज्य की तुलना में ठीक है। फिर भी जिला पिछडा हुआ है। * विश्लेषण से हम जिले की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं महिला विकास संबन्धित सभी क्षेत्रों की ताकत और कमियों की पहचान कर चुके हैं। मौजूदा व निकट भविष्य में मिलने वाले अवसरों व संभावित खतरों का अध्ययन भी इस प्रतिवेदन में किया गया है। हमारी समग्र जिला

योजना इसी विश्लेषण को आधार बनाकर बनाई जा रही है। योजना में सभी के सहयोग से जिले की निहित शक्तियों को उभारने एवं कमियों को दूर करने के विशेष प्रयास इस प्रतिवेदन के माध्यम से किये जा रहे हैं। विश्लेषण करने पर **निश्कर्ष** रूप से यह प्रकट हुआ कि जिला शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं महिला विकास संबन्धित सभी क्षेत्रों में पिछडा हुआ है। जिले में साक्षरता अत्यधिक कम है, महिलाओं में 27.80 एवं पुरुषों में 64.72 है, कुल साक्षरता दर 46.49 प्रतिशत है जबकि राजस्थान की साक्षरता दर क्रमशः महिलाओं में 43.85, एवं पुरुषों में 75.7 प्रतिशत है, कुल 60.4 है। जिले में प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालयों की संख्या छात्रों की दृष्टि से अत्यन्त ही कम है जिले में व्यावसायिक शिक्षण संस्थान भी अप्रयाप्त है तथा इंजिनियरिंग एवं पोलोटेक्निकल कॉलेज एक भी नहीं है। जिले में मात्र तीन महाविद्यालय ही है।

जिले में I A U मृत्यु दर 88 है, राष्ट्र की 54, राजस्थान 79 है। अतः जिले की I A U मृत्यु दर अत्यधिक है, जिसको आरसीएच द्वितीय के लक्ष्य 2011-12 तक 32 तक लाने का लक्ष्य है। अतः इसके लिए उपयुक्त रणनीति निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिसमें परिवार नियोजन एवं जननी सुरक्षा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन अति आवश्यक है। जिले में पर्याप्त अत्याधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन युक्त सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों का अभाव होने से लोगों का रूझान पड़ोसी राज्य गुजरात की ओर पलायन अहम चिन्ता का विषय है।

जिले में गरीबी का मुख्य कारण रोजगार के साधनों का अभाव है। जिले में कुल रोजगार का लगभग तीन चौथाई कृषि व कृषि संबंधी मजदूरी ही है। जिले में रोजगार के अन्य संसाधन नहीं है। जिला मुख्यालय पर ग्रेनाईट उद्योग से लोगों के आजीविका का मुख्य स्रोत है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन पर भी लोगों की आजीविका निर्भर होती है, लेकिन इस क्षेत्र में पानी नहीं होने से यह उद्योग भी कगार पर है। इसी तरह लघु उद्योगों में लेटा के खेस, भीनमाल की जुतीया एवं जसवंतपुरा में टमाटर तथा सांचौर में जीरा एवं इसबगोल की खेती जिले की सर्वोच्च उद्योगों में माने जाते हैं।

जिले में भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार लिंगानुपात 1991 में 942 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 964 हो गया। इससे स्पष्ट है कि लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। ग्रामीण लिंगानुपात 1991 में 947 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 970 हो गया, शहरी लिंगानुपात 1991 में 881 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 889 हो गया। नवजात शिशु लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष) 1991 में 929 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 921 हो गया। इससे स्पष्ट है कि नवजात I A U लिंगानुपात में कमी आई है। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात 1991 में 901 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 921 हो गया एवं अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 1991 में 885 था जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 904 हो गया। 1991 में महिला कार्य सहभागिता दर 31.60 थी जो कि मानव विकास अपडेट 2007 के अनुसार 2001 में 46.09 हो गयी। इससे स्पष्ट है कि महिला सहभागिता दर में वृद्धि हुई है। जिले में विवाह की औसत आयु जनगणना 2001 के अनुसार भी 18.30 वर्ष है। जो कि संतोषजनक है।

उपरोक्त वि लेखन से स्पष्ट है कि जिले की भावी रणनीति 2015 तय करने में अत्यधिक प्रयास किये जाने हैं—

शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कर जिले की महिला साक्षरता दर राज्य एवं राष्ट्रीय साक्षरता दर से अत्यधिक कम है एवं पुरुष साक्षरता दर राज्य एवं राष्ट्रीय साक्षरता दर से भी कम है। 1991 से 2001 के दशक में जालोर जिले में महिला साक्षरता में एवं पुरुष साक्षरता में सराहनीय वृद्धि हुई है लेकिन साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान में 31 वां स्थान है। वर्तमान समय में जालोर जिले में शिक्षा एवं साक्षरता के दृष्टिकोण से विभिन्न जाति सबसे अग्रणी है जिनमें साक्षरता 75 प्रतिशत से अधिक है, जालोर जिले में बहुसंख्यक आबादी अनुसूचित जातियों में मेघवाल, अनुसूचित जनजातियों में भील, अन्य पिछड़ा वर्ग में रेवारी, कलबी, स्वर्ण जातियों में भोमिया राजपुत एवं अल्प संख्यक समुदाय में मुसलमानों में साक्षरता दर 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के बीच ही है, इन जातियों में बालिका शिक्षा मात्र 10 से 20 प्रतिशत तक ही है। इसी वजह से जालोर जिले की कुल साक्षरता 2001 की जनगणना के अनुसार मात्र 46.49 प्रतिशत ही है। इन जातियों में साक्षरता दर भात-प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसकी भावी रणनीति 2015 तक तय करने के लिए शिक्षा के अध्याय में वर्णन किया गया जिले में महिलाओं की साक्षरता दर अत्यधिक ही कम है साक्षरता दर को शत-प्रतिशत लाने के लिए विशेष कर रबारी, जोगी, गाडलिया लुहार आदि जातियों में शिक्षा के प्रति रुझान पैदा कर शिक्षा की ओर प्रेरित करना होगा। महिलाओं में राजनैतिक, प्रशासनिक पदों पर भागीदारी तय करने के लिए कुशल कारगर उपाय करने होंगे।

जिले में गत तीन वर्षों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में परिवार नियोजन के साधनों में अदभूत वृद्धि हुई है, जिससे महिला नसबंदी, आयुडी उपयोग एवं कण्डोम उपयोग प्रमुख है। परन्तु पुरुष नसबंदी में स्थिति शून्य जैसी है। जिसे भात-प्रतिशत तक लाना है।

जिले में पानी एवं सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं हैं। ग्राम स्वास्थ्य समितियों, और पेयजल समितियों का पेयजल शुद्धि एवं फ्लोरोसिस के लिए उचित रणनीति बनाने की आवश्यकता है। पेयजल से सम्बन्धित आकड़े अप्राप्त हैं। वर्तमान में जिले में 758 ग्रामीण स्वास्थ्य समितियां कार्यरत हैं। जिले में डीएलएचएस-3 2007-08 के अनुसार सुलभ सुविधा उपयोग का प्रतिशत 11.8 जो कि डीएलएचएस-2 के मुकाबले कम पाया गया। और पाईप से पेयजल के उपयोग का प्रतिशत 70.1 प्रतिशत था। जो कि डीएलएचएस-3 में कम होकर 65.6 प्रतिशत रह गया।

राजस्थान के 33 जिलों में से 18 जिले फ्लोराईड एन्डेमिक घोषित किये गये हैं जालोर में फ्लोराईड के आंकड़े कम उपलब्ध हैं फिर भी कुछ पूर्व अनुसंधान से आंकड़े लिये गये हैं इसमें गोपाल एट.एल. 1985 ने सर्वे के अन्तर्गत राजस्थान के 2700 पानी के नमूनों का फिजिको-केमिकल विश्लेषण किया, जिसमें जालोर के 165 पानी के नमूनों की फ्लोराईड सान्द्रता 14.2 मिली ग्राम/लीटर पाई गई जो कि चिन्ताजनक है। सर्वाधिक सान्द्रता राजस्थान के चुरू जिले में 30 मिली ग्राम/प्रति लीटर पाई गई।

औझा एट.एल. 2003 ने भी फ्लोराईड सान्द्रता का विश्लेषण किया जिसमें नागौर की सान्द्रता 34 मिली ग्राम/लीटर, पाली में 19 मिलीग्राम/लीटर और बाडमर में 18 मिलीग्राम/लीटर पाई गई जो कि जालोर का पड़ोसी जिला है।

डाग्ली एट.एल. 2008 के एपिडेमियोलोजिकल सर्वे के अनुसार जालोर में पानी का स्तर 3.56 पी.पी.एम. से 4.07 पी.पी.एम. के बीच पाया गया। यहां जालोर में प्रमुख भोजन बाजरा व सरसों है जो कि कैल्सियम से भरपूर डाईट है। जालोर में डेन्टल फ्लोरोसिस की प्रवेलेंस 94.9 प्रति 100 है, 5-12 आयु वर्ग में 15 आयुवर्ग में 97.2 प्रति 100 व 35 से 44 आयु वर्ग में 95.8 प्रति 100 है। फ्लोराईड की सान्द्रता 1.5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक होती है तो दांतों पर भुरापन आ जाता है इस अवस्था को दांतों का फ्लोरोसिस कहते हैं और आगे की अवस्था में दांत काले एवं क्षीण हो जाते हैं।

फ्लोरोसिस को कम करने के लिए सुझाव:-

डीफ्लोरोडेशन के लिए कम खर्च वाली विधियां जैसे:- पॉली एलुमिनियम क्लोराईड एवं नालगोण्डा तकनीक का उपयोग ।

फ्लोराईड कमी वाले क्षेत्र में कुओं/ ट्यूबवेल्स का निर्माण करना।

विटामिन -सी भरपूर डाईट का उपयोग ।

समय-समय पर फ्लोराईड एन्डेमिक क्षेत्रों में एपिडेमियोलोजिकल सर्वे करवाना।

दूध पिलाती माताओं को फ्लोराईड रहित पानी पिलाने की सलाह देना।

फ्लोराईड से भरपूर खाद्य (पान, सुपारी, टूथपेस्ट, माउथवाश, तम्बाकू, पान मसाल, गुटखा व चट्टानी नमक) का कम से कम उपयोग।

जिले में कुल कुल भौगोलिक क्षेत्र 10640 हैक्टर भूमि है, जिसमें वन 22063, अकृषि भूमि 170633, पडत भूमि 176719, कृषि भूमि 863906 है, जिले की अकृषि भूमि को उपजाऊ बनाकर उससे सिंचित करने के लिए नर्मदा नहर परियोजना के सिंचाई एरिया को बढ़ाना, जवाई बांध से पंचायत समिति आहोर के कुछ गावों में सिंचाई हो रहे हैं जिसे जालोर मुख्यालय तक लाना इसी तरह माही बांध से जालोर जिले को जोड़ना संबंधी योजना अमल में लाने से जिले की अवशेष अकृषि भूमि सिंचित हो जायेगी इससे नये नये उद्योग, पशुपालन व्यवसाय, जिले में जीरे, इसबगोल, रायडा तथा टमाटर की पैदावार अत्यधिक ओर होगी इससे लोगों का दूसरे राज्य की ओर हो रहा पलायन बंद हो जायेगा।

त्ममितमदबमेरू

बमदेने 2001ण

ड ड – ३ व् श्रंसवतम

लैवक्व डड–भ्व श्रंसवतम

क्वडन् ए छत्भडए डड–भ्व श्रंसवतम

क्वसै बिजोममज 2007.2008

क्वचनसंजपवद विनदकंजपवद विपिकपंए डंल 2008

वीं मज सं 2003

वंहसप मज सं 2008

ळमदमतंस भेचपजंसए श्रंसवतम ;ठवदमेमदेपअपजल बंउच वतहंदप्रमक इल अमतेमेंए व्हहंदपबए थ्वतउमक –

भपउंसंलं ब्वउचण्द्व

प्वै क्मचंजण श्रंसवतम

क्वट् च्त्तपै.मब श्रंसवतम

।हतपबनसजनतम क्मचजण श्रंसवतम

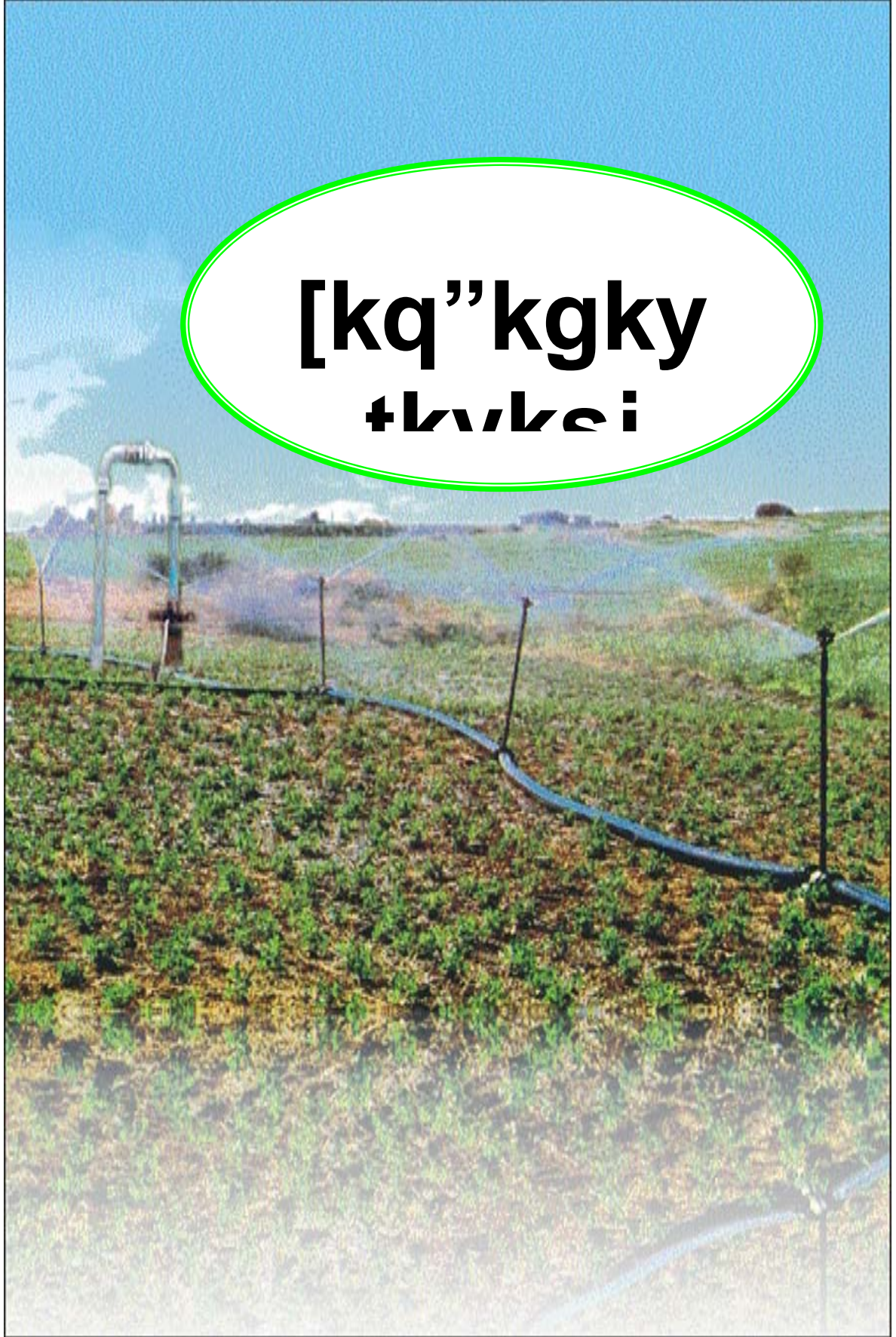
क्वम्क दक प्ततपहंजपवद क्मचजण

ब्वससमबजवतए स्प्टण श्रंसवत

।दपउंस भ्नेइंदकतल क्मचजण श्रंसवतम

क्वंपतलए त्दपूंतण

क्वप्स। च।त्तै।क्व श्र।स्वत्त



[kq''kgky
†kwkei

“इति भुभम”